

Vol. I  
No. 30

Tuesday  
6th April, 1954



## HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES Official Report

### PART II—PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

#### CONTENTS

PAGES

Members elected to Public Accounts Committee and Estimates Committee .....	1898-
L.A. Bill No. XVII of 1954, the Hyderabad (Abolition of Cash Grants) (Amendment) Bill, 1954—Introduced .....	1894-
L.A. Bill No. XIV of 1954, the Hyderabad Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill, 1954—Passed .....	1894-1906
L.A. Bill No. XII of 1954, the Hyderabad Houses (Rent, Eviction and Lease) Control Bill, 1954—First reading concluded .....	1906-1949

*Note:*—A (\*) star at the beginning of a speech denotes confirmation not received.



# THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

*Tuesday, the 6th April, 1954.*

The House met at Half Past Two of the Clock

*[Mr. Speaker in the Chair]*

## Questions and Answers

(See Part I).

### MEMBERS ELECTED TO PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE AND ESTIMATES COMMITTEE.

مسٹر اسپیکر - پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اشیمیش کمیٹی کے ارکان کی جو تعداد مقرر کی گئی تھی ان کے لئے اتنے ہی نامینشن بیپرس آئے ہیں - اس وجہ سے بولنگ کی ضرورت نہیں ہو گی - لہذا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لئے یہ مبرس مقرر ہونے ہیں -

۱ - شری ایم - بچنا -

۲ - شری لمبا جی مکتا جی -

۳ - شری رتن لال کوئیچہ -

۴ - شری شیو بسن گوڑہ -

۵ - شری ایل - کے - شراف -

۶ - شری سید احتمر حسین -

اور اشیمیش کمیٹی کے یہ ۷ ممبرس ہونگے -

۱ - شری وی - ڈی - دیشپانڈے -

۲ - شری جی - کے - گالیکوواڑ -

۳ - شری گندے راؤ -

۴ - شری سری ہری -

۵ - شری شفیع الدین -

۶ - شری کے - آر - فیرا سوانی -

۷ - شری کے - وینکٹ رام راؤ -

1894

**L. A. Bill No. XVII of 1954, the Hyderabad Abolition of Cash Grants (Amendment) Bill, 1954**

*The Minister for Excise, Forests & Revenue (Shri K. V. Ranga Reddy)* : I beg to introduce L. A. Bill No. XVII of 1954, the Hyderabad Abolition of Cash Grants (Amendment) Bill, 1954.

*Mr. Speaker* : The Bill introduced.

**L. A. Bill No. XIV of 1954, the Hyderabad Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill, 1954**

*The Minister for Education & Local Government (Shri Gopalrao Ekbote)* : I beg to move :

“ That L. A. Bill No. XIV of 1954, the Hyderabad Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill, 1954, be read a second time.”

*Mr. Speaker* : The question is :

“ That L. A. Bill No. XIV of 1954, the Hyderabad Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill, 1954, be read a second time.”

The motion was adopted.

*Clause 2.*

*Shri Ankushrao Ghare (Partur)* : I beg to move :

“ That in line 3 of Section 6-A proposed to be inserted between “money” and “and” insert “at 6 per cent per annum”.

*Mr. Speaker* : Amendment moved.

*Shri Ch. Venkatrama Rao (Karimnagar)* : I beg to move :

“ That line 2 of Section 6-A proposed to be inserted for ‘advance’ substitute ‘loan interest bearing of six per cent’.”

*Mr. Speaker :* Amendment moved.

*Shri Gopidi Ganga Reddy (Nirmal-General) :* I beg to move :

" That lines 3,4, and 5 of Section 6-A proposed to be inserted for ' and subject to such conditions as may be specified in rules and orders made in this behalf by Government ', substitute the following :—

" not exceeding ten thousand on the condition that he furnishes the security for the same '."

*Mr. Speaker :* Amendment moved.

شري کے۔ انت رئی (پالکنڈہ)۔ میں نے دو امنڈمنٹس دئے تھے جنہیں ایک  
ہی کردا گیا ہے۔ میں پہلے امنڈمنٹ کو موو کرنا نہیں چاہتا۔ دوسرا حصہ کو موو کر رہا  
ہوں۔

I beg to move :

" That at the end of section 6-A proposed to be inserted by the clause add the following proviso :

' Provided that the rules and orders so made shall be laid before the Legislative Assembly '."

*Mr. Speaker :* Amendment moved.

*Shri B. D. Deshmukh (Bhokardan-General) :* I beg to move :

" That after section 6-A proposed to be inserted by the clause add the following proviso :

' Provided that the amount advanced shall be paid back within three years from the date of issuing '."

*Mr. Speaker :* Amendment moved.

\* *श्री अंकुशराव घारे :-*

अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां जो अमेंडमेंट लाया है, करीब विसका फस्ट रीडिंग चल रहा था तब कहा गया कि हम बिस छोटे से बिल को बड़े बनाये की तजर से देख रहे हैं। हम यह मानते हैं कि ऑडिमिनिस्ट्रेटिव कनविनियन्स के लिये मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लमेंटरी सेक्रेट-रीज आदि रखने का अधिकार लिडर ऑफ दी हाबुस को है, लेकिन लिडर ऑफ दी हाबुस को यह बेखत्यार नहीं है कि पब्लिक मनि को कुछ लोग जो कि पार्टी में गडबड करने के विभकानात हैं,

अब अनुको डिप्टी मिनिस्टर बनाकर खुश करने के लिये कुछ रकम सरकारी खजाने में से अनुको मोटर आदि लेने के लिये दी जाय। आपके एक पार्टि के कुछ लोगों को खुश करने के लिये और अपनी गद्दी कायरम रखने के लिये अस तरह से डिप्टी मिनिस्टर्स, जो कि अपने काम से वाकफियत भी नहीं रखते हैं, और कुछ ज्यादा अबल भी नहीं है, असों की खोगीर भरती करना पालमेंटरी डेमोक्रेसी का मिसयुज करना है। जब की बेकार लोगों को खाना देने के लिये आपके पास पैसे नहीं हैं तब आप डिप्टी मिनिस्टर्स को गाडियां लेने के लिये करीब १ लाख रुपये तक रकम देना चाहते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स को मोटर के लिये अस तरह पैसे दिये जायें तो असमें कोओ बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा यह अमेंडमेंट लाने का भक्सद यह था कि जब की हम कहते हैं कि हमारे यहां फायनान्सियल स्ट्रॉजन्सी हैं और बजेट में पैसे कम हैं अस लिये नेशनल डेव्हलपमेंट के काम हम नहीं ले सकते हैं; तो गैर जरूरी तरीके पर अस तरह खजाने पर बार क्यों डाला जाता है? अस लिये मैंने यह रखा है कि अगर आपको डिप्टी मिनिस्टर्स को लोन देना ही है, तो जैसा अप्रिकलचरल डेटर्स रिलीफ बिल में, जो कि हमारे सामने आ रहा है लोन को रियलाइज करने के लिये ६ परसेंट सूद रखा गया है, असी तरह यहां भी जब डिप्टी मिनिस्टर्स को लोन दिया जाता है, अनुसे भी वह लोन के तौर पर देकर ६ परसेंट अट-रेस्ट लिया जाना चाहिये। हम असको बनीये की नजर से नहीं देखते हैं। लेकिन जब पब्लिक मनी दी जा रही है तब वह किस तरह से रीपे ( Repay ) होगा यह भी देखना चाहिये। हम देखते हैं कि डिप्टी मिनिस्टर्स की पोजिशन मेंटेन होनी चाहिये, लेकिन असके साथ अव्वाम के खजाने से जो पैसा दिया जा रहा है वह भी बराबर रीपे होना चाहिये। अस लिये मैं यह अमेंडमेंट मुब्ल कर रहा हूँ। और मुझे अमीद है कि मिनिस्टर साहब मेरी अस अमेंडमेंट को मंजूर करेंगे।

شروع के - انت ریڈی - مسٹر اسپیکر سر - ڈپ्टी मिनिस्टर्स को لون (Loan) دینے کी जो بحث यहां जहरी है और जैसके متعلق कहा जारहा है कि अनुको ऑफान्स के तौर पर किये रकम डिजाइन्गी तो अस बारे में ये चराहत नहीं की जाएँ कि कृत्ति रकम डिजाइन्गी - कन कंडीशन्स ( Conditions ) पर डिजाइन्गी और वह कृत्ति मृदत में वापसी हो जाएँ - मैं ने अपने अन्दरूनी के ذریعे अस अमेर की खواहश की है कि जो रूपस अस बारे में बनाए जाएँगे वे अम्बली मैं प्रियंकर जाएँ - जहां तक लोन दिने का सवाल है अस बारे में यहां काफ़ अधिकार खिल किया गया है - ये चीज़ यही मृदहम है कि आया अस लोन वह कैप्चर अंथ्रेस्ट ( Interest ) या जाईका या नहीं - जब हम अती रकम ३००० मिनिस्टर्स को ऑफान्स के तौर पर दें रहे हैं तो असकी वापसी का किया तरीफ़ होगा - हो सकता है कि एक ३००० मिनिस्टर या सारे लोन के सारे ३००० मिनिस्टर्स यात् नहीं रहें अप्सी चिरत मैं वापसी रकम की किया दिया जाएँगी - असले मैं अवाहश करूँगा कि जो रूपस बनाए जाएँगे वे हावज़ के सामने रखे जाएँ - तब ही हावज़ अस बोर्डशन मैं हो जाके वह अन मासैल बर गुर्ज़ करें - मैंने समझेता हूँ कि मैंने अन अन्दरूनी को खरो त्योल किया जाएँगा और हावज़ को अने काफ़ी डिफेंस ( Confidence ) मैं लिये का जो सवाल है वह अस्त्र द्वे बोरा किया जाएँगा -

श्री. गोपिंडी गंगा रेड्डी : —

अध्यक्ष महोदय, जब यह अमेंडिंग विल कल लाया गया और अुसके बूपर हाथुस मे बहस हुयी तो मिनिस्टर साहब ने यह कहा की हम अिस विल की तरफ अंक बनाये की दृष्टि से देख रहे हैं। हम बनाये की दृष्टि से नहीं देखते हैं अैसा मेरा कहना है। लेकिन हुकूमत जो भी चीज करती है अुसे जिम्मेदारी की दृष्टि से ही देखना पड़ेगा। जिस तरह अंक स्त्री-हमारे पास अंक स्त्री के अधिकार बताये गये हैं कि वह कार्येशु दासी, कर्णेशु मत्री, रूपेच लक्ष्मी, चमया धरित्री, भोजेशु माता, शयनेशुवैश्या पटकर्म युक्ता कुलधर्म पत्नि, अिस प्रकार स्त्री के अनेक अधिकार बताये गये हैं, और सब तरफ अुसे देखना पड़ता है। जिस तरह शूद्र वैश्य, अिनके अलग अलग काम होते हैं, वह अपनी अपनी नजर से हर एक काम की तरफ देखते हैं, अुसी तरह सरकार को भी कितने ही प्रकार के काम करने पड़ते ह, अिस लिये सरकार को भी सब तरफ देखना चाहिये। सरकार जो भी काम करती हैं अुस तरफ हमे भी अच्छी तरह देखने की जरूरत होती है।

मेरा कहना यह नहीं है कि डिप्टि मिनिस्टर्स को सवारी के लिये मोटर न दी जाय, और हम अनुको मकरूज बनाये। अैसा भी मै कभी नहीं कहूँगा। वह जो कर्जा लेंगे तो अुसको अदा करने के लिये अनुपर अैसी नीबत न आय कि मिनिस्टरी से हटने पर आपका कर्जा अदा करने के लिये अुन्हें दर दर धूमना पड़े। अिस लिये अबतक कोओ जमानत अनुसे नहीं ली जाती, अिस तरह का कर्जा अुन्हें नहीं देना चाहिये। और जो कर्जा आप अनुको देंगे वह अुसी काम के लिये खर्च होना हिये, जैसा कि किसी खास काम के लिये तकादी दी जाती है और वह रकम दूसरे किसी काम के लिये खर्च नहीं की जा सकती, अुसी तरह यह कर्जा भी अुसी काम के लिये खर्च किया जाना चाहिये नहीं तो यदि अुन्हें ज्यादा कर्जा दिया जाता है तो ५ हजार में किसी भी तरह की अंक मोटर खरीद कर बाकी रकम खुद के अंशआराम के लिये खर्च की जायेगी। यह ठीक नहीं है। अिस लिये मेरा सजेशन है कि ज्यादा से ज्यादा बिन्हें दस हजार तक की रकम दी जानी चाहिये और वह भी बगैर जमानत के नहीं दी जानी चाहिये। अगर वे मिनिस्ट्री से अलग होते हैं तो जो जमानत अुन्होंने दी है अुसे देकर वह अलग हो सकते हैं जिससे सरकार का कोओ नुकसान न होगा। और अब्बाम का पैसा भी बरबाद न होगा। अिस लिये मैंने यह अमेंडमेंट लायी है। अुमीद है कि मिनिस्टर साहब, जिसे कबूल करेंगे।

شري سى ايج۔ وينكٹ رام راؤ۔ مسٹر اسپیکر سر۔ میں نے ڈبی منسٹرس کے لون (Loan) کے بارے میں ایک امن्तिन्त پیش کیا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اس امن्तिनگ بل کو کسی طرح قبول نہیں کریں گے لیکن ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ کسی طرح سیجاریٹی سے یہ بل تو منظور ہوئی جائیکا زیادہ سے زیادہ یہ ہوسکتا ہے کہ وہنے فیل ہو جائیگا۔ جیسا کہ آریل سب سمجھتے ہیں ہم تو ایسا نہیں سمجھتے۔ اسلئے ہم نے یہ خیال کیا کہ کم از کم اتنا ہو جائے تو اچھا ہے کہ عوامی نقطہ نظر سے عوامی بھٹ پر کم سے کم بار عائد ہو۔ اس نقطہ نظر سے ہم نے چھوٹے موئے ترمیمات پیش کئے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دو ڈھائی سال میں انہیں یہ قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ دس هزار روپیہ اگر دئے جائیں تو دو ڈھائی سال میں ادا کرنے کیلئے کافی بڑی نسبت دینی

ہو گئی اسلائے ہم نے مناسب سمجھا کہ کم شرح سود عائد کیا جانا چاہئے اسلائے ۶ فیصد سود عائد کرنے کیلئے ہم نے اپنے امنڈمنٹ میں سجیشن ( Suggestion ) دیا ہے - اسکے متعلق یہ کہہ کر ٹال دینا صحیح نہیں ہے کہ رولس بنانے والے ہیں یہ تمام چیزیں اس میں طے کریں گے - رولس کے معاملہ میں میں عرض کروں گا کہ جو رولس آپ بناتے ہیں وہ اسمبلی میں پیش نہیں کئے جاتے - رولس حسب منشاً آپ بناتے ہیں - اسلائے ہم نے امنڈمنٹ پیش کئے ہیں کہ چوہ فیصد سود لیا جائے ۔ ۱ ہزار سے زیادہ لوں نہ دیا جائے واپسی لوں کی مدت ڈھائی سال رکھی جائے ۔ ہمیں امید ہے کہ آنریبل موور ہارے ان امنڈمنٹس کو مان لینگے - اس توقع پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں ۔

\* شری بی - ڈی - دیشیکہ - مسٹر اسپیکر سر - دفعہ ۶ الف کے بارے میں مختلف امنڈمنٹ پیش کئے گئے ہیں - انہی امنڈمنٹس کی روشنی میں میں نے جس پروویزو (Proviso) کی ترمیم چاہی ہے وہ صحیح ہے - جیسا کہ آنریبل منسٹر نے اپنی اپنی تقریروں میں اسکی وضاحت کی کہ جو لوں دیا جائیگا وہ دس ہزار کے لگ بھگ ہوگا - اوسط قسم کی گزاری میں سمجھتا ہوں کہ دس ہزار سے کم قیمت میں نہیں ملیگی - جب ہم دس ہزار کی رقم دے رہے ہیں تو اسبارے میں بھی سوچنا پڑیگا کہ یہ رقم کتنی مدت میں قابل واپسی قرار دیجائیگی - الکشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے ڈپٹی منسٹر پانچ سال رہ سکتے ہیں جسمیں سے تین سال تو گزر جکر ہیں اب دو سال باقی رہ گئے ہیں - انکی تختخواہ کا یہ حصہ وضع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مدت میں یہ رقم وصول ہو سکتی ہے - اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ تین سال میں نو ہزار روپیہ واپس ہو سکتے ہیں - میں کہہون گا کہ کسی دفعہ میں واپسی رقم کیلئے میعاد مقرر کرنی چاہئے جسمیں قرضہ ادا کرنا ضروری ہے ۔

دوسری بات یہ کہ ائرٹسٹ کے تعلق سے چہ فیصد کی شرح تجویز کی گئی ہے جو معمولی سے معمولی شرح ہے - زراعت پیشہ اشخاص سے بھی چہ پرسنٹ سود لیا جاتا ہے - تقاضا پر بھی چہ پرسنٹ سود لیا جاتا ہے - جب زراعت پیشہ اشخاص سے سود لیا جاتا ہے تو ڈپٹی منسٹر کو جو لوں دیا جا رہا ہے اسپر بھی سود عائد کرنا ضروری ہے - اس احاظت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے امنڈمنٹ نہایت واجبی ہیں انہیں قبول کرنے میں موور اف دی بل کو کوئی اعتراض نہوگا ۔

شری سید حسن ( حیدر آباد - سٹی ) - مسٹر اسپیکر سر - اس ڈیمو کریٹک سٹ - اپ ( Set-up ) میں لیڈر آف دی هاؤز کو اسکا حق حاصل ہے کہ وہ ڈپٹی منسٹر میں کا یا پارلیمنٹری سکریٹریز کا تقرر کریں یا ان کی تعداد میں کمی یا زیادتی کریں - لیکن ایسے تقررات کے وقت ملک کے معاشی حالات اور فینانشیل کنڈیشن (Financial Condition) پر نظر رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے - یہ نہیں کہ من ملنے انہی ذاتی اغراض کے تحت تقرر کریں - ہم دیکھو رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی معاشی حالت پست ہوئی جاوہی ہے اور فینانشیل ہو زیشن .....

مسٹر اسپیکر - یہ سکنڈ ریڈنگ کا اسٹیج ( Stage ) ہے اس نوبت پر جنرل بحث نہیں ہونی چاہئے بلکہ امنڈمنٹس کے سلسلہ میں جو کہنا ضروری ہے صرف وہی کہنا چاہئے ۔

شری سید حسن - ہاں میں اسی لحاظ سے کہہ رہا ہوں ۔ ہمارے ہاں کے حالات یہ ہیں کہ کارخانے دن بند ہوتے جا رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگ بیروزگار ہوتے جا رہے ہیں ۔ چھ منسٹر صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ چند مکمکوں کا کنسٹرکشن ( Construction ) ہوتا ہے اور چند مکمکوں کا ڈسٹرکشن ( Destruction ) لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ منسٹر کے مکمکوں کا تو کنسٹرکشن ہوتا ہے لیکن ۔ دوسرے مکمکے ڈسٹرکشن میں ہی ہیں ۔

Mr. Speaker : No General discussion please.

آپ کس ترمیم پر بحث کر رہے ہیں ۔

شری سید حسن - (۲) پرنسٹ اٹریسٹ کے بارے میں جو امنڈمنٹ پیش کی گئی ہے میں اسکے متعلق کہہ رہا ہوں ۔

مسٹر اسپیکر - جنرل ٹسکشن ہو چکا ہے ۔

شری سید حسن - امنڈمنٹ کے تعلق سے ہی میں عرض کر رہا ہوں ۔

جو پارٹی زیر اقتدار ہے اپنا پروگرام جلانے کے لئے یہ سب کچھ کر رہی ہے منسٹر جو ہیں وہ الامنیسٹریشن ( Administration ) کے معاملات سے واقف نہیں ہوتے صرف الامنیسٹریشن پر کنٹرول کرنا انکا کام ہوتا ہے ۔ ملک کے معاشی حالات کے مدد نظر منسٹر اور ڈپٹی منسٹر کا تقریر اور انکی تعداد کا تعین ہونا چاہئے ۔ جب اہل ملک کی بڑی تعداد نے چیخ و پکار چائی تو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

مسٹر اسپیکر - غیر متعلقہ باتیں نہ کہی جائیں ۔ امنڈمنٹ پر کچھ کہنا ہے تو کہئے ۔ آنریبل ممبر کو کافی موقع دیا گیا ہے لیکن بار بار وہی چیزیں دھراں جا رہی ہیں جو پہلے کہی جا چکی ہیں ۔ ریسٹ ( Repeat ) کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ۔

شری سید حسن - جب ایک ممبر ہاؤز میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کچھ کہتا ہے تو اسکو اسکا اندازہ ہوتا ہے کہ فائدہ ہے یا نقصان ۔

مسٹر اسپیکر - غیر متعلقہ باتیں کہنے سے کیا فائدہ ہے ۔ اس سے وقت خانع ہوتا ہے ۔

شری سید حسن - غیر متعلقہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں ۔ منسٹر من اور ڈپٹی منسٹر کے فرائض کیا ہوئے چاہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں جب یہ میوال ہاؤز میں آیا تو چیف منسٹر

صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اپنی وزارت اور اپنی چیف منسٹری کو باقی رکھنے کے لئے ڈپٹی منسٹر کا تقرر کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گورنمنٹ کے آفیسرس کو بھی قرضہ دیا جاتا ہے لیکن انکے ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ انکو پنشن (Pension) (Dibigati ہے جس سے قرضہ کے وصول کا امکان رہتا ہے۔ انکو ڈکلائریشن (Declaration) دینا ہوتا ہے۔ انکی آمدنی کے ذرائع معلوم کئے جاتے ہیں اور اسکا اطمینان کر لیا جاتا ہے کہ وصول قرضہ میں آسانی ہو گی یا نہیں۔

مسٹر اسپیکر - اس امنڈمنٹ کے بارے میں آپکو کچھ کہنا ہے تو کہہئے ورنہ میں آپ کو ٹائیم (Time) نہیں دے سکتا۔

شری سید حسن - میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت ڈپٹی منسٹر کو قرضہ دیگی تو اوسکو وصول کرنے کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اونکو پنشن تو نہیں ملتی۔ نائب وزیر کو کل ہٹا دیا جاسکتا ہے۔ اس لئے یہ دیکھنا ضروری تھا کہ اونکی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں اونکے اسٹس (Assets) کیا ہیں۔ یہ قرضہ وہ کسطر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کو حکومت صاف طور پر ہاؤز کے مامنے رکھنا چاہئے تھا۔ عوام کا پیسہ اس طرح بیجا طور پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ مختلف طریقوں سے بلس لائے جا رہے ہیں۔ منسٹر کے بل - ڈپٹی منسٹر کے بل - پارلیمنٹری سکرٹری کے بلس۔ حکومت کو چاہئے کہ ایسے بلس کو روکے۔ جناب والا اس تعلق سے زیادہ عرض کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اس لئے میں مجبوراً اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

\* شری حی - سری راملو (متہنی) مسٹر اسپیکر - جو بل ڈپٹی منسٹر کو لوں (Loan) دینے کے بارے میں پیش کیا گیا ہے اوس پر اس جانب سے جو امنڈمنٹ پیش کئے گئے ہیں میں اونکی تائید کرتے ہوئے چار الفاظ کھکھل کر بیٹھ جاؤں گا۔ اسٹیٹمنٹ آف آجیکٹس (Statement of Objects) میں تو گرانٹ آف لونس (Grant of Loans) لکھا گیا ہے۔ سکشن ۶ (۱) میں جو امنڈمنٹ لائی گئی ہے اوس میں ری پے ایبل اڈوانس (Repayable advance) بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کے لئے جو روپس بنینگے اون کے تحت وہ لوگ یہ قرضہ ادا کریں گے۔ جب اس کے لئے روپس بنائے جائیں گے تو اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ وی پے ایبل اڈوانس کی حیثیت لوں (Loan) کی ہو جائیگی۔ اور اگر وہ لوں ہوتا ہے اوسکا سود بھی لیا جاسکتا ہے۔ حکومت کو چاہئے تمہاکہ یہ بات وہ اس میں رکھتی مگر افسوس ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ری پے ایبل اڈوانس ہوگا۔ وہی رقم وہ لوگ واپس کریں گے۔ اس سے گورنمنٹ اور پبلک ٹریوزری کا تعصیان ہوگا۔ اسٹیٹمنٹ آف آجیکٹس میں لوں کا نام دیکر اور امنڈمنٹ میں اسکو ری پے ایبل اڈوانس کا نام دینے سے حکومت کی یہ نیت ظاہر ہوتی ہے کہ اون سے سود لئی کا ارادہ نہیں ہے۔ اس لئے اس جانب کے معجزہ سبران نے جو امنڈمنٹ لائے

ہیں جن میں بعض نے ۱۰ ہزار رکھا ہے اور بعض نے ۸ ہزار رکھا ہے۔ اگر اوسکے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ قرضہ ۸۰ ہزار کے لگ بھگ ہو گا۔ اتنی بھاری رقم دینے کی بجائے اسے ضروری کاموں میں لگایا جاسکتا تھا۔ آپ ہمیشہ فینانشیل اسٹرنجنسی (Financial stringency) کی باتیں کرتے تھے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ عذر لنگ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت چاہے تو کسی نہ کسی طرح کام نکال سکتی ہے۔ اور پہلک اور عوام کے مسائل کو حل کر سکتی ہے لیکن وہ حل کرنا نہیں چاہتی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ فینانشیل اسٹرنجنسی کے متعلق ہمیشہ منسٹر اور حکومت کمہتی رہتی ہے لیکن اس کے باوجود ایسے بل لانے ہے۔ اس کا ثبوت یہی ہے کہ ڈپٹی منسٹر اور منسٹر کے سلیریز اور الونسنس کو چاہے تو حکومت بڑھا سکتی ہے۔ ایک لاکھ روپیہ اوس کے لئے نکال سکتی ہے اور سود بھی نہیں لگتی۔ کل اگر کوئی نوکانفینڈنس موشن آجائے یا چیف منسٹر صاحب کسی ڈیلیشن (Deletion) یا اڈیشن (Addition) کو ضروری سمجھیں تو شائد ان لوگوں کو ہٹ جانا پڑیگا۔ پھر وہ قرضہ کیسے وصول کر سکیں گے۔ جب وہ پھر یہم۔ ایل۔ اے۔ ہوجائینگ تو قرضہ کیسے وصول کریں گے؟ آپ لون ڈپٹی منسٹر کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ ایک شخص کو دے رہے ہیں۔ اگر ڈپٹی منسٹر کے پوست کے لئے کار سپلانی کرنا ہوتا تو ٹھیک تھا۔

It will be with the Government and any other Deputy Minister who takes charge will also take charge of the car. But this is a loan given to a particular gentleman and he will take the ownership of car after the loan is repaid.

لیکن آپ تو ایک شخص کو لون دے رہے ہیں جو ڈپٹی منسٹر کا پوست سنہالا ہوا ہے۔ اس لئے اس کا سود لیا جانا بھی ضروری ہے۔ اگر کل وہ شخص ڈپٹی منسٹر کے پوست سے ہٹ جائے اور محض ایم۔ ایل۔ اے رہ جائے یا ایم۔ ایل۔ اے بھی باقی نہ رہے ایک آڑڈنری آدمی کی طرح رہے تب بھی وہ موثر کو استعمال کریگا۔ جب ایک ایم۔ ایل۔ اے کو اڈوانس مل سکتا ہے تو ایک معمولی آدمی کو بھی ملتا چاہئے۔ ایک کسان کو بھی ملتا چاہئے جو اپنا پسینہ بھاکر روپیہ پیدا کرتا ہے اور آپ کو دیتا ہے۔ اس لئے میں کہوں گا کہ آنریل ممبر انت ریڈی نے سود کے بارے میں جو امنڈمنٹ دی ہے اوسکو آنریل منسٹر مان لینگے۔ وونہ اون کی تغواہوں میں کمی کیجائے جیسا کہ سوشلسٹ گورنمنٹ نے ٹراونکور کوچین میں کیا اور دنیا کے سامنے ایک نظیر پیش کر دی۔ ایک طرف تو یہاں وہ پوری تنخواہ بھی اٹھائیں گے اور پھر اون کو وہ آٹھ اثریٹ (without interest) لون بھی دیا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ سوشل ازم کے ایک معمولی ذرہ تک بھی پہنچ سکتے گے۔ کم از کم اٹھریٹ کی حد تک جو امنڈمنٹ آئی ہے اوسکو قبول کر لینا چاہئے۔ اور چونکہ آپ تھی حکومت کی حیات ڈھانی سال کی ہے اس لئے اوس میں جیسا کہ شری بی۔ ڈی۔ دیشمکہ نے امنڈمنٹ پیش کی اندر وہ تین سال رقم وصول کرنے کی شرط رکھنا چاہئے۔ اگر آپ ان شرائط کے ساتھ لون دینگے تو

جو شکوک عوام میں ہیں وہ دور ہو جائیں گے یا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اسٹیٹ بینک کو آذر دیدیتے تو وہ اون لوگوں کو قرضہ دے دیتا - بہت سے پرائیویٹ پرسنس (Private persons) کو اسٹیٹ بینک نے وتو انٹرست (with interest) ( ) قرضہ دیا ہے - آپ فون سے کہدیتے تو وہ قرضہ دیدیتا -

These eight are coming to you and you may please consider their cases.

تو وہ قرضہ دے سکتا تھا - بہت سے لوگوں کو وہاں سے قرضہ دیا گیا ہے - اگر حکومت مصلحت سے کام کرنی تو وہ بہت سے اعتراضات اور کریٹیسیزم سے بچ سکتی تھی - اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ جو لوں دیا جائے وہ سود کے ساتھ دیا جائے اس سے متعلق جو امنڈمنٹ ہے اوسکو قبول کر لیا جائے تاکہ جو رقم دیجارہ ہے وہ منافع کے ساتھ ٹریپریزی (Treasury) میں واپس آسکے -

\* چیف منسٹر (شوی بی - رام کشن راؤ) - یہ ایک چھوٹا سا بل ہے جس پر دو امنڈمنٹ ہیں - میں اس سلسلہ میں خصوصاً عرض کروں گا - میں نے کل اور آج بھی جنرل ڈسکشن سنا ہے - مجھے اس بات سے خوشی ہو رہی ہے کہ آنریل مبرسن گھروں نے امنڈمنٹ پیش کئے ہیں اس ضرورت کو محسوس کیا ہے کہ ڈپٹی منسٹر کو موثر کارک شکل میں کتوئے اس (Conveyance) کی ضرورت ہے - اس حد تک انہوں نے تسلیم کر لیا ہے میں اون کا شکر گزار ہوں - اس کو تسلیم کرنے کے بعد بھی بہت سی باتیں کہیں گئیں جو محض گورنمنٹ پر کریٹیسیزم کرنے کے لئے کہیں گئی ہیں - مثلاً یہ کہا گیا کہ گورنمنٹ کو کسی اور سٹولہ سے اتنی ہمدردی نہیں جتنی ہمدردی کہ اوسے ڈپٹی منسٹر سے ہے - گورنمنٹ کسی اور کو لوں دینے کے لئے اتنی ہمدردی کا اظہار نہیں کرنی گی اس کا کارس کے سلسلہ میں لوں دینے کے لئے کر رہی ہے - وہ ان کو فوراً ہی لوں دینے پر تیار ہو جاتی ہے - آنریل مبرسن شری بی - ڈی - دیشکوہ نے اولڈ مل سکندر آباد کے سلسلہ میں کہا کہ وہ کار خانہ بند ہو گیا اور وہاں کے مزدور بیکار ہو گئی ہیں اون کا پراویڈنٹ فنڈ جمع ہے لیکن اونکو نہیں دیا جا رہا ہے - اگنیسٹ دیٹ پراویڈنٹ خذ (Against that)

Provident Fund ( ) لوں دینے کے لئے کہا گیا لیکن گورنمنٹ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے - اون سے گورنمنٹ کو ہمدردی نہیں ہے لیکن ڈپٹی منسٹر کی کارس کے سلسلہ میں گورنمنٹ ہمدردی کرو رہی ہے - گورنمنٹ فوراً ہی اپنے لوں دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہے - میں اس کا جو لب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا لیکن میں نے خود اس معاملہ میں جس کا ذکر آنریل مبرسن کے کیا دلچسپی لیکر کاپڑوائی کی - جب مل بند ہو گئی اور اسکے بعد جو واقعات شروع ہوئے تو اونیں ہو میں نے لیبر منسٹر - ڈپٹی لیبر منسٹر - لیبر کمشنر اور کارس اینڈ التسٹریٹ کے منسٹر اور اون کے سکریٹری سے متعدد مرتبہ کانفرنس کی - جو بھی لیبر ڈپٹیشن (Deputations) آئے لہذا ہے میں نے کتفکوکی - جب یہ سٹولہ میرے

سامنے پیش ہوا تو میں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے لیبر منسٹر کو لیٹر لکھا ۔ واقعہ یہ ہے کہ اگزپیڈیٹ فیکٹریز اور نان اگزپیڈیٹ فیکٹریز ، ان دو قسم کے فیکٹریز کے لئے براوینڈنٹ فنڈ کو ری فنڈ کرنے کے لئے گورنمنٹ آف انڈیا کا قانون ہے ۔ اور اوسکے تحت رولس ہیں ۔ حیدرآباد اسٹیٹ میں کوئی ایسا قانون اور رولس نہیں ہیں جن میں ترمیم پیش کردیتا جس طرح کہ ڈپٹی منسٹر کے لون کے سلسلہ میں مجھے قانون میں ترمیم پیش کرنے کا موقع ملا ۔ اسٹیٹ لاز ( Govern State Laws ) کو گورن ( Govern ) کرنے والے جو سٹریل لاز ( Central Laws ) ہیں اون کے تحت حکومت کے لئے بجز اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس خصوص میں گورنمنٹ آف انڈیا کی لیبر منسٹری کو لکھا جائے ۔ چنانچہ میں نے پندھر روز پہلے انہیں لکھا تھا ۔ خوش قسمتی سے آج صبح ہی میرے پاس جواب آیا ہے ۔ لیبر منسٹر نے اسکی اجازت دی ہے کہ براونڈنٹ فنڈ کی رقم مزدوروں کو واپس کر دیجائے ۔ اس سلسلہ میں ریجنل براونڈنٹ آفسر کو بھی لکھدیا گیا ہے ۔ چونکہ اس چیز کو پیش کرنا تھا اس وجہ سے میں نے خود جواب دیا ہے ۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی ہمدردی سب کے ساتھ ہے ۔ خواہ وہ ڈپٹی منسٹر ہوں ۔ خواہ آریبل ممبر لیجسلیبو اسٹریل ہوں یا کوئی مل کا مزدور ہو یا کوئی آرڈینری کسان ہو ۔ چونکہ ہم ایسی کریوں پر یتھر ہوتے ہیں جس پر ٹرست ( Trust ) کیا جاتا ہے اس لئے ہم نے اوسی ٹرست کے لحاظ سے امن معاملہ کو حل کرنے کی کوشش کی ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ۔

" I have issued instructions to the Regional Provident Fund Commissioner, Hyderabad, to allow immediate payment of Provident Fund to the employees concerned "

اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں نے کل اس سلسلہ میں یا کسی اور سلسلے میں کیوں نہ ہو جو اعتراض کیا تھا اون کو معلوم ہو گا۔ کہ حیدرآباد گورنمنٹ اس خصوص میں سوچی ہوئی نہیں ہے بلکہ جو مزدور پیروزگار ہو گئے ہیں اور جن کو تکلیف ہو رہی ہے اون کی ہمدردی کے سلسلہ میں اقدام کر رہی ہے ۔ چنانچہ اون کو عارضی ریلیف ( Relief ) دیکھی ہے ۔ گورنمنٹ کو انکی جو بھی مدد کرنا ہے وہ اس سلسلہ میں ضرور کریں ۔ اس سے بُوہ کر میں اس سلسلہ میں کچھ کھانا نہیں چاہتا ۔ امندھنست پیش کرتے ہوئے یہ جو کہا گیا ہے کہ اون رقم پر سود لیا جائے اون سے سیکوریٹی ( Security ) لیجائے اور قرضہ کی رقم معین کی جائے تو ان امور کی نسبت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تینوں چیزوں گورنمنٹ کے سامنے ہیں ۔ یہ نئی چیزوں نہیں ہیں ۔ اون کو من مانے رقم نہیں دیجائیگی اوسکا تعین ہو گا اور کنسیشنل ریٹ ( Concessional rate ) ہو ہی کیوں نہ ہو ان میں اوس رقم پر سود لیا جائیگا ۔ گورنمنٹ کا خیال فوجی اثرست لون دینے کا نہیں ہے ۔ کتنا اثرست لینا چاہئی اس کا ابھی تصفیہ نہیں ہوا۔ ان وجہ سے ہم نے اس بل میں اسے نہیں رکھا ۔ سیکوریٹی کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ کارس خود سیکوریٹی ہونگے ۔

ڈپٹی منسٹر کو اوس وقت تک اوس کار کا مالک نہیں بنایا جائیگا جب تک کہ وہ رقم معہ سود جو انکے ذمہ واجب الادا ہو ادا نہ ہو جائے ۔ سرکاری عہدہ داروں کو کارس کے لئے جو لوں دیا جاتا ہے اوسکے متعلق رولس موجود ہیں اون میں میکورٹی نہیں لیجاتی ۔ اوسی کے مثال رولس اس کے لئے بھی رکھئے جائینگے ۔ رولس حب تیار ہونگے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں سامنے رہینگی ۔ رقم کی مقدار کا تعین ہو گا ۔ میں ہاؤس سے یہ کہدینا چاہتا ہوں کہ خود ڈپٹی منسٹر بھی کارس کے لئے بڑی بڑی رقمیں لیکر گیالنٹری (Gallantry) دکھانے کے لئے تیار نہیں ہیں ۔ نہ وہ اپنے اوپر اتنا بار لینا چاہتے ہیں ۔ اور فہ گورنمنٹ اون کو ضرورت سے بڑھ کر رقم دیگی ۔ کم سے کم انہیں جتنی رقم کی ضرورت ہو گی وہ دیجائیگی ۔ آنریبل ممبرس نے امنڈمنٹ کے ذریعہ رقم کی مقدار دس ہزار اور آٹھ ہزار رکھی ہے ۔ میں اس امنڈمنٹ کو قبول تو نہیں کرتا لیکن یہ حیثیت مور آف دی بل اونکو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی اوس رقم کی مقدار ۱۰ ہزار آٹی ۔ جی سے زیادہ نہیں ہو گی ۔ بلکہ اس سے کچھ کم ہی ہو گی ۔ اسی طریقہ سے سود کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سود لیا جائیگا لیکن میں یہ نہیں کہ سکتا کہ وہ کتنے پرست ہو گا ۔ تین پرست یا چھ پرست ۔ ایک آنریبل ممبر نے ۳ پرست اور دوسرے آنریبل ممبر نے ۶ پرست کے لئے کہا ہے ۔ فینانس ڈارمنٹ حالات کے لحاظ سے اسکا تعین کریگا اور یقیناً کچھ نہ کچھ سود چارج (Charge) کیا جائیگا ۔ یہ اعتراض کہ کیوں اسکی صراحت نہیں کی گئی تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس میں صراحت کرنے کا رواج نہیں ہے ۔ سٹرل گورنمنٹ کے قانون میں بھی کار لوں کے لئے ایک پرائیزن ہے ۔ ہم نے جو امنڈمنٹ ہاؤس کے سامنے پیش کیا ہے اس میں بعینہ وہی الفاظ رکھئے گئے ہیں جو سٹرل گورنمنٹ کے قانون میں ہیں ۔ سکیورٹی وغیرہ کے طریقہ کو رولس میں مدون کیا جائیگا اسلئے ہم نے اسکو رولس کے لئے چھوڑ دیا ہے ۔ دراصل لوں دینے یا نہ دینے کا تصفیہ خود گورنمنٹ کرسکتی تھی جیسا کہ دوسرے عہدہ داروں کی نسبت کیا جاتا ہے ۔ لیکن اسکو ہاوز میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ منسٹر اور ڈپٹی منسٹر کی سالریز اور الونس ہاؤس نے مقرر کئے ہیں ۔ اسلئے جب تک اس میں ترمیم نہو انہیں لوں دینے کی گنجائش پیدا نہیں کی جاسکتی ۔ اسکو ہاؤس کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ منسٹر اور ڈپٹی منسٹر کے بارے میں ایک ایکٹ موجود ہے اس میں جو کنوینینس (Conveniences) انہیں دئے گئے ہیں اس سے بڑھ کر انہیں کنوینینس دینے کا حق حاصل نہیں ہو گا اور جب تک آپ انکے لئے اس لوں کے حاصل کرنے کی گنجائش پیدا نہ کریں وہ لوں حاصل نہیں کرسکتے ۔ چنانچہ یہ اجازت حاصل کرنے کے لئے یہ امنڈمنٹ پیش کیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آنریبل ہاوز اسکو منظور کر لیکا ۔ باقی ڈیپلیمنس رولس میں ہو سکتے ہیں ۔ میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ رقم مناسب اقساط میں وصول کی جائیگی ۔ اقساط کی مدت گورنمنٹ آفیسرس کے لئے یہ ہے کہ لوں ۲۸ اقساط میں واجب الادا ہو گا ۔ اسپر غور کیا جاسکتا تھا کہ یہ اقساط اس سے کم ہا

زیادہ ہونے چاہئیں لیکن ظاہر ہے کہ اب موجودہ ڈپٹی منسٹریں کے لئے ۳۸ سہیں کی مدت باقی نہیں ہے جو بھی مدت اب باقی ہے وہ ۳۲-۳۳ مہینے کی ہے۔ اسی میں یہ رقم ان سے لیجائیگی۔ اگر اس بیں وہ اصل معہ سود ادا کر دیں تو کاریں کے مالک ہو گائیں گے ورنہ ان کے لئے وہ طریقہ اختبار کیا جائیگا جو عہدہ داروں کے لئے اختیار کیا جاتا ہے۔ ڈپریسینشن جارجن (Depreciation Charges) منہا کرنے کے بعد گورنمنٹ خود ان موتروں کو لبیگی۔ یہ تمام تفصیلات رولس میں رکھی جائیں گے اس وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ آنریل سمبرس اپنے امنڈمنٹ کو واپس لے لینے کیونکہ امنڈمنٹ لانے کی جو اغراض تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ گورنمنٹ خود انہیں پورا کرنے والی ہے۔ اتنا عرض کر کے ہوئے میں امید کرتا ہوں کہ امنڈمنٹ واپس لے لئے جائیں گے۔

*Mr. Speaker :* I shall now put the amendments to Clause 2 to vote.

*Shri Ankushrao Ghare :* I beg leave of the House to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

*Shri Ch. Venkatrama Rao :* I beg leave of the House to withdraw my amendment.

The motion was, by leave of the House, withdrawn.

*Mr. Speaker :* The question is :

"That in lines 3,4 and 5 of the Section 6-A proposed to be inserted, for 'and subject to such conditions as may be specified in rules and orders made in this behalf by Government' substitute the following:-

'not exceeding ten thousand on the condition that he furnished the security for the same'."

The motion was negatived.

*Mr. Speaker :* The question is :

"That at the end of section 6-A proposed to be inserted by the Clause add the following proviso:

'Provided that the rules and orders so made shall be laid before the Legislative Assembly'."

The motion was negatived.

*Shri B. D. Deshmukh :* I beg leave of the House to withdraw my amendment.

The amendment was, by leave of the House, withdrawn.

*Mr. Speaker :* The question is :

"That Clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted Clause 2 was added to the Bill.

*Mr. Speaker :* The question is :

"That Short title, commencement, and preamble stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Short title, commencement, and preamble were added to the Bill.

*Shri Gopalrao Ekbote :* I beg to move :

"That L. A. Bill No. XIV of 1954, the Hyderabad Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed."

*Mr. Speaker :* The question is :

"That L. A. Bill No. XIV of 1954, the Hyderabad Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill, 1954, be read a third time and passed."

The motion was adopted.

**L. A. Bill No. XII of 1954, the Hyderabad  
Houses (Rent, Eviction and Lease)  
Control Bill, 1954.**

*Shri Gopalrao Ekbote :* I beg to move :

"That L. A. Bill No. XII of 1954, the Hyderabad Houses (Rent, Eviction and Lease) Control Bill, 1954 be read a first time."

*Mr. Speaker :* Motion moved.

میں سمجھتا ہوں کہ ہم فرست رینڈنگ پر ہ بھے تک ڈسکشن ختم کرسکتے ہیں۔

شروع بی - ڈی - دیشمکو - کوشش کیجائے گی کہ ڈسکشن پانچ بھے تک کیا جائے۔

مسٹر اسپیکر۔ اسکے معنے یہ ہیں کہ پانچ بھے تک ڈسکشن ختم ہو سکتا ہے۔  
شروع گویاں راؤ اکبوری - یہ بل اسی فیصلہ کا نتیجہ ہے جو ہائیکورٹ کے ایک  
مل بیج ( Full Bench ) نے ڈیفنس آف حیدر آباد روپس کے سلسلہ میں  
مادر فرمایا تھا۔ ایوان کو یہ معلوم ہوا کہ اس قلر بیج نے ڈیفنس آف حیدر آباد روپس  
( Defence of Hyderabad Rules ) کو جو ہمارے پاس تھے ایک ایک  
امرجنسی لیجنڈلیشن ( Emergency Legislation ) قرار دیا تھا اور  
اویکو الٹرا وائیز ( Ultra vires ) قرار دیا تھا۔ اسکا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ  
اسکی دفعہ ۲۷ کے تحت جو رئیٹ رکولیشن پابند ہے اس کا نافذ تھا۔ وہ خود بخود کالعدم  
ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسکے دوسرے ہی روز اس رئیٹ رکولیشن کو بھی اسکے نتیجے  
کے طور پر الٹرا وائیز قرار دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لینڈڈ ( Landed Property )

ہر اپنی کو گورن (Govern) کرنے والا کوئی دوسرا قانون باقی نہیں رہا۔  
یہ بھی ظاہر ہے کہ سنہ ۱۹۳۹ع میں جب جنگ شروع ہوئی تو ایک طرف مکانات کی  
قلت محسوس کیجائے لگی اور دوسری طرف مالکان امکنہ زیادہ کرایہ وصول کرنے لگے۔  
تب مختلف صوبہ جات میں یکسرے بعد دیگرے اس قسم کے قوانین نافذ  
ہونا شروع ہوئے۔ جنانچہ ہارے پاس بھی ایک قانون سنہ ۱۹۴۲ع میں نافذ کیا گیا۔  
اب اس پر دو نقاط نظر سے حملہ کیا جا رہا ہے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ دفعہ  
۲ کے تحت وہ قانون نافذ ہوا تھا اس لئے وہ خود بخود كالعدم ہو جاتا ہے کیونکہ  
ڈیفس آف حیدر آباد روپس کو خود الثرا وائز قرار دیا گیا ہے۔

دوسری وجہ یہ بھی بلائی جا رہی ہے کہ کانسٹیوشن کے آرٹیکل ۳۶ اور ۴۰ کو  
ایک جگہ ملا کر پڑھیں تو جیسا کہ پتنہ ہائیکورٹ کے ایک فلر بیج نے ایک کیس میں  
تصیہ کیا وہ غیر دستوری ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ایک ہی  
پائنس پر اتفاق آرا زیادہ ہے۔ وہ یہ کہ ڈیفس آف حیدر آباد روپس کے الثرا وائز قرار پانے  
کے بعد رنٹ ریگولیشن کو بھی الثرا وائز قرار دیا جائے لیکن اسکا لازمی نتیجہ یہ  
تھا کہ جو کارروائیاں اس کے تحت زیر دوران تھیں انکی نسبت ایک عجیب صورت پیدا  
ہو گی۔ اسلئے انکے فوری فیصلہ کیلئے اس بل کو لانے کی ضرورت داعی ہوئی۔

اب میں اس قانون کے سلیمنٹ فیچرس (Salient Features) کی طرف آنریبل  
مہریں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جو پرانا قانون فلر بیج کا فیصلہ آنسے پہلے تک  
نافذ تھا اسکے پروسیجر میں کچھ ڈیکلیٹیز (Difficulties) اور تقاضیں تھیں۔ انکو  
دور کر کے دوسرے صوبہ جات کے ایکٹس کے مائل کامپریمنسیو رنٹ کنٹرول بل  
(Comprehensive Rent Control Bill) لانے کی ضرورت تھی۔ لیکن پہلی چیز جو  
میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں کے پہلے قانون میں جو بنیادی چیزیں اچھی  
تھیں انہیں اور دیگر صوبہ جات کے قوانین خاص طور پر مدرس کے ایکٹ کو پیش نظر  
وکھتی ہوئے یہ بل پیش کیا گیا ہے۔ اس بل کو تین حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے  
ایک تو فیر ونٹ (Fair rent) کے فکریشن (Fixation) کیلئے کچھ  
دفعات ہیں۔ دوسرے ایوکشن (Eviction) (ہر مرسر کشن) (Restriction) عائد  
کرنے کے سلسلہ میں کچھ دفعات ہیں۔ اس سلسلہ میں آپکو یہ معلوم ہو گا کہ ثرا نسفر  
آن ہر اپنی ایکٹ کے لحاظ سے ایک مہینے کی نوٹس کے اختتام کے پہلے لینڈ لارڈ اور فیشن  
کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ عام طور پر ختم کی جاسکتی ہے۔ اور وہ آسانی سے تخلیہ کی  
نالش کر کے قبضہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح فیر ونٹ فکس کرنے کیلئے پہلے کے  
قانون میں کوئی گنجائش نہ تھی بلکہ کئٹرا کچوپول رنٹ (Contractual rent) (Contractual rent)  
دینے کیلئے ہی وہ قانون زیادہ مائل تھا۔ اسلئے جنگ کے بعد آج کے خاص حالات میں  
کثی سیٹیز اور ناؤنس میں جو حالت ہے اسکو پیش انظر و کھتی ہوئے جو گونکہ ٹرانسفر آف  
ہر اپنی ایکٹ (Transfer of property Act) کے دفعات کی تکمیل نہیں ہوتی۔

تھی اسلئے ایک خاص ایکٹ کے ذریعہ ایوکشن پر رشتہ کشن عائد کرنے کی ضرورت داعی ہوئی اسلئے یہ دوسرا حصہ لایا گیا ہے ۔

تیسرا حصہ اس قانون کا وہ ہے جو گذشتہ قانون میں موجود نہ تھا ۔ بعض مکانات جن کو رکویزیشن ( Requisition ) کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ دو حصوں میں منقسم کئے جاسکتے ہیں ۔ ایسے مکانات جو خالی ہیں یا خالی ہونے والے ہیں ۔ اس کے تحت مالک پر یہ لازمی قرار پاتا ہے کہ سکان خالی ہونے کی صورت میں ایک مدت مناسب میں حکومت کو اس کی اطلاع دےتاکہ ایک جنرل یا اسپیسیفک نوٹیفیکیشن کے ذریعہ پبلک نیچر ( Public Nature ) کی جو ضروریات ہیں ان کے لئے یہ مکان حاصل کیا جاسکے ۔ اس کا جو رنٹ فکس ہوتا ہے وہ فیرنٹ ہوگا ۔ اور اسی نوٹیفیکیشن کے ذریعہ کرایہ فکس کر کے ادا کیا جائیگا ۔

اس بل کے ذریعہ یہ تیسرا ہراویزن لایا گیا ہے جو گذشتہ ایکٹ میں نہیں تھا ۔ اس کے علاوہ اس فیصلہ کے مدنظر دو دفعات کا اضافہ لازمی ہو گیا ہے ۔ یہ ظاہر ہے کہ گذشتہ ۷-۸ سال میں اس قانون کے تحت جو فیصلہ جات ہوئے ہیں ، جو تغییرے عمل میں آئے ہیں یا جو کرانے کے تعین ہوئے ہیں یا جو کچھ بھی کارروائیاں ہوئی ہیں ۔ اور اس وقت عدالت ابتدائی میں یا م RAF میں یا ہائیکورٹ میں رٹ کے تعلق سے زیر دوران ہیں انہیں محفوظ کرنا ضروری ہے ۔ کیونکہ اس قانون کو کرایہ داروں کے منافد ہی میں سمجھا گیا ہے ۔ اس لئے اس قانون کو رٹاپکٹیو ایکٹ ( Retrospective effect ) دیکھ سا بیکھرے میں جو عمل ہوا ہے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے ۔ اور جو کارروائیاں پنڈنگ ہیں ان کو بھی اس قانون کے تحت پیش شدہ سمجھنے کے لئے رٹاپکٹیو ایکٹ دیا گیا ہے ۔

دفعہ ۳۲ جس کے تحت عہدہ دار نے فیرنٹ کے تعین کیا ہے یا تخلیہ کی کارروائی کی ہے ہائیکورٹ اس کے الٹراوائریس ( Ultra vires ) قرار پانے کی وجہ سے اگر اس کو ویساہی چھوڑ دے تو ان پر ہرجہ کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے ۔ اس سے بچانے کے لئے اس میں ایک اندھنی فائینگ کلاز ( Indemnifying Clause ) بھی رکھا گیا ہے ۔ اس طرح ان پانچ ضروری اور اہم امور کے بارے میں یہ بل لایا گیا ہے ۔ جس پر معزز ایوان کو غور کرنا ہے ۔

فیرنٹ ( Fair rent ) کے فکریشن ( Fixation ) کے سلسلے میں آنریبل مبرس کو یہ معلوم ہوگا کہ موجودہ قانون کی دفعات کے لحاظ سے فیرنٹ کے تعین کے لئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یکم خورداد سنہ ۱۹۴۸ء میں سیمیلر لسرکم استائنس ( Similar Circumstances ) میں سیمیلر ہاؤسنگ کیا کرایہ تھا اور اسی لوکیالیٹی ( Locality ) کا کیا کرایہ تھا ۔ اس کو پیش نظر رکھتے

رکھتے ہوئے ان برٹیکسنس اور دوسرا ذمہ داریوں کا جو اضافہ ہوا ہے اس کو پیش نظر رکھکر کرایہ کا تعین کیا جاتا ہے - اس سسٹم کی اکچول ورکنگ ( Actual working ) اور نتیجات میں کافی دقیقیں ہوتیں - بعض جگہ ٹیکسنس کے رجسٹرات نہیں تھے - بعض جگہ متصلہ مکانوں کے کرایوں کے سلسلے میں غلط شہادتیں پیش کی جاتی تھیں - بعض جگہ مصنوعی شہادتیں بھی پیش کی گئیں - اس طرح ایک بالکل انسرٹی ( Uncertainty ) تھی جس کی وجہ سے کنٹرولر کو اپنا اختیار تمیزی استعمال کرنا پڑتا تھا - اور کوئی میگزیم لیمٹ ( Maximum Limit ) جسکو سیلنگ کہا جاسکرے اس قانون میں نہیں رکھی گئی تھی اس لئے دوسرا سسٹم جو بھائی مدارس اور لکھنے میں راجح ہے اس کے لحاظ سے یہاں بھی ایک یہاں ایر ( Base Year ) رکھا گیا ہے - اس یہاں ایر کے لئے ہم نے گذشتہ قانون ہی کے یہاں ایر کو لیا ہے یعنی سنہ ۱۹۵۳ء - اس یہاں ایر کے بعد جس طرح دوسرے شہروں میں عمل ہوا ہے اس وقت کے کرایہ پر کچھ پرسنٹ اضافہ کیا جائیگا - ان تینوں مقامات پر مختلف پرسنٹیجس ہیں - یہاں کے حالات کے لحاظ سے بروشیج مقرر کرنیکرے لئے معزز ایوان کو غور کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ فیرنٹ فکریشن کے لئے جو سسٹم رکھا جا رہا ہے وہ کہاں تک کار آمد ہو سکتا ہے - اور میگزیم یا سیلنگ رنٹ نکس کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ کہاں تک مناسب ہے - جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے اسی سسٹم کو یہاں کے لئے پسند کیا گیا ہے جو تینوں پڑے شہروں میں راجح ہے - اس سے ایک ان سرٹی ( Uncertainty ) ایک غیر قطعیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے - اور دوسرا طرف میگزیم سیلنگ کی وجہ سے رنٹ ریا کشنگ ( Rent Racketting ) جو چل رہا ہے اس پر تحدیدات عائد ہو جاتی ہیں - گورنمنٹ بھی اس کو پسند کرتی ہے - مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس کو پسند کریں گے - جہاں تک پرسنٹیج کا تعلق ہے اس کو ورک اوٹ کرنے کے بعد ہر وقت ال جسٹ ( Adjust ) کیا جاسکتا ہے -

اسی طرح ایونکشن کے سلسلے میں دفعہ ۸ میں جو رسٹرکشن عائد کی گئی تھیں وہ ڈفکٹیوی ورڈا ( Defectively worded ) ہوئے کی وجہ سے اس کی الگ الگ تعیین ہوئے کا اللدیشہ تھا - چنانچہ ایسے ارکان جن کا تعلق پیشہ وکلا سے ہے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کرایہ دار اور مالک مکان دونوں کو دقیقیں محسوس ہو رہی تھیں - دفعہ ۸ کی ان خامیوں کو دور کر کے دفعہ ۱۰ اس طرح وضع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ ایک طرف تو ٹینشن کو سیکیورٹی اُف ٹیننسی ( Security of Tenancy ) حاصل ہوئے تو دوسرا طرف لینڈ لارڈ کے بونا فائیڈ رکوائرمنٹس ( Bona fide Requirements ) ہی محفوظ رکھیے گئے ہیں - یہ ہل جیسا کہ میں نے کہا لینڈ لارڈ اور ٹینشن کے درمیان جرڈیشس رلیشن ( Judicious Relations ) کو میں تین ( \* )

کرتا ہے۔ اور کنٹرولر کو اختیار دیا گیا ہے کہ جن صورتوں میں یہ معلوم ہو گا کہ فی الواقعی مالک کو مکان کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں وہ تخلیہ کا حکم دے سکتا ہے۔ اس بل کا جو کلائر ۱۰۰ ہے وہ گذشتہ دفعہ ۸ کے مقابلہ میں زیادہ ریزبیل اور زیادہ جوڈیشیشن رلیشنس قائم کرنے والا ہے۔ اور اس سے سیکیورٹی آف ٹیننسی بھی حاصل ہو گی۔

تیسرا صورت جو میں نے بتائی ہے اس کی تفصیلات عرض کردی گئی ہیں۔ یہ ۲۰ صورتیں ہیں۔ ہم کو یہ بل اسی شدن میں پاس کرنا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس میدان میں جو ایک خلاسا پیدا ہو گیا ہے اس کو پر کیا جائے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو مختصر ساختہ کیا ہے اس کے پیش نظر بحث پر ہتھ زیادہ وقت صرف نہ کرتے ہوئے اس مسودہ قانون کو متفقہ طور پر منظور کیا جائیگا۔

\* شری ۴ - ڈی - دیشمکھ - مسٹر اسپیکر سر - رنٹ کنٹرول کے بارے میں جو بل ہاؤس کے سامنے آیا ہے اسکی تائید کرتے ہوئے میں یہ عرض کرونا گا کہ حیدرآباد میں اس قسم کے قانون کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ اس کمی کو دور کرنے کیلئے یہ بل انٹرودیوں ( Introduce ) کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ بل حیدرآباد اور سکندرآباد کے ٹوئن سیٹیز ( Twin Cities ) میں جو شکایتیں ہیں ان کو رفع کرنے کے بارے میں کس حد تک جامع ہو سکتا ہے۔ فسٹ ریڈنگ کی نوبت پر میں یہ کہونا گا کہ ہائیکورٹ کی رولنگ اگر نہ فوج تو ممکن تھا کہ جس اندھا دھنند طریقہ سے اب تک عمل ہورہا تھا وہی عمل کچھ اور سالوں تک چلتا رہتا۔ اس قانون کے لانے پر حکومت کو مبارک باد دینے کی ضرورت میں اس لئے نہیں سمجھتا کہ ہائیکورٹ کی رولنگ کے بعد حکومت نے ایک خلا محسوس کی اور اس کو پر کرنے کے لئے یہ قانون لایا گیا۔ ہمارے انجوائنگ پروونس ( Adjoining Provinces ) میں اس سے پہلے ہی سے ایسے قوانین موجود ہیں جن پر عمل ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے پاس آج تک شدت سے ضرورت محسوس ہونے پر بل ہاؤس کے سامنے لایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ قانون بنارہ ہیں تو اسکو ہر حیثیت سے مکمل ہانا چاہئے۔ سسری طور پر اس قانون کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حکومت نے کچھ عجیب سا عمل کیا ہے۔ وہ یہ کہ پہلے قانون کے دفعہ (۶) میں یہ بتایا گیا ہے کہ

#### Increase of rent where tax or cess is increased.

میں حکومت کے سامنے یہ تجویز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ طغی کیا گیا ہے کہ لوگن بالائیز یا تحصیلدار جو بھی سی ( Cess ) پر ایک ہو گا اس کے لحاظ سے فیرنٹ ( Fair rent ) کا تعین کریں گے تو اس طرح اضافہ ہو جائیگا اس کی ذمہ داری ٹینسٹ پر رکھی گئی ہے۔ دفعہ ۷ میں یہ جواصول رکھا گیا ہے وہ ٹینسٹ کے حق میں نا انصاف ہو گی اور وہ قانون کی اغراض کے لئے بھی مناسب نہ ہو گا۔ میں دفعہ ۷ کی ہوئی تفصیلات

میں اس وقت جانا نہیں جاہنا لیکن اس بر توجہ کرنے کی ضرورت ہے - دفعہ ۷ میں  
یہ ہے کہ

Landlord not to claim or receive anything in excess of fair or agreed rent.

یہ شرط رکھی گئی ہے - اس کی غرض بادی النظر میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ و ٹینٹ کے  
مفاد کے لئے ہے - لیکن اس میں ایک غیر ضروری براویز و رکھا گیا ہے جس کا اثر ٹینٹ  
پر پڑتا ہے - اس کے ساتھ سانچے اس قانون کا دفعہ ۱۰ بھی بہت اہم ہے - اس کے تحت  
دفعہ (۲) کے لحاظ سے ٹینٹ کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں -  
اور لینڈ لارڈ مختلف حیلے حوالی کر کے ٹینٹ کو یہدخل کرسکتا ہے - اس ضمن میں جو  
قانونی ترمیم ہو سکتی ہے گو اس کو بہت ہی کامپری ہنسیو (Comprehensive )  
طریقے پر مدون کیا گیا ہے لیکن اس میں چند خامیاں ہیں ان کے بارے میں دوسری  
ریڈنگ کے موقع پر امنڈمنٹس پیش کئے جائیں گے -

اکزیپشن (Exemption) کے تعلق سے جو دفعہ ۲۶ ہے مجھے اسبارے  
میں بھی اپنے خیالات ظاہر کرنا ہے - حکومت کا یہ عام اصول ہو گیا ہے کہ ہر قانون میں  
وہ اکزیپشن رکھتی ہے - جس کی وجہ سے پورے قانون کے اغراض و مقاصد فوت ہو جاتے  
ہیں - یہاں یہ کہا گیا ہے کہ

This Act shall not apply to—

- (a) any house taken on lease or requisitioned by Govt.
- (b) any house belonging to—
  - (i) Government ;
  - (ii) any local authority ;
  - (iii) City Improvement Board, Hyderabad ;
  - (iv) Town Improvement Trust, Secunderabad ;
  - (v) Salar Jung Estate ; or
  - (vi) any ward of the Court of Wards ;

اے کو چھوڑ دیا جائے تو ہی - اور سی دو ضمن رکھے گئے ہیں - جو اکزیپشن رکھا  
گیا ہے وہ بہت سیاسی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے - ایک طرف تو آپ قانون بناتے ہیں  
دستور کے نفاذ کے بعد تو آپ اونچ نیچ کو مٹانے کا ذم بہرتے ہیں - اور کہتے ہیں کہ  
امیر غریب کا امیتاز نہیں کیا جاتا - ایسی صورت میں میں یہ کہوں گا کہ حکومت جب  
کوئی قانون بناتی ہے تو حکومت پر بھی اس قانون کا اطلاق کیوں نہ کیا جائے - اسکو  
کیوں اکزیپٹ کیا جاتا ہے - اس سے وکاؤٹیں پیدا ہوتی ہیں - (سی) میں یہ الفاظ  
ہیں کہ

Any person, whom or institution which the Government  
may by a general or special order exempt.

یہ کیا طریقہ ہے میری سمجھ میں نہ آیا - اس ضمن کے تعلق سے میں کہونگا کہ ہماری حکومت کا جو رویہ رہا ہے وہ قابل افسوس ہے - چند اشخاص یا ان کے انسٹیٹیوشنز (Institutions) کے بارے میں بارہا توجہ دلائی گئی ہے لیکن اب تک کچھ نہیں ہوا - مثال کے طور پر میں کہونگا کہ راج پرمکھ کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے بارے میں متعدد مرتبہ کہا گیا لیکن نظام صاحب کے انسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے اور جاگیرداروں کی جانبیاد کی حفاظت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے - سالارجنگ اور دوسرے متعدد جاگیرداروں کے ٹینٹس ہیں "سی" ، کامنشاً واضح ہے کہ جاگیرداروں اور نوابوں کو حکومت مستثنی کرنا چاہتی ہے - اس دفعہ میں یہ چیزیں مضمرا ہیں - اگر ایسا نہیں ہے تو موور آف دی بل اسکی وضاحت کریں - جیسا کہ خانگی مکانات کے مالکوں کے بارے میں اصول مدون کرتے ہیں ویسا ہی اصول راجاؤں مہاراجوں جاگیرداروں اور راج پرمکھ کی جانبیادوں کے بارے میں بھی مدون کیا جانا چاہتے ان کو مستثنی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے - اب زمانہ آگیا ہے کہ پڑے پڑے جاگیرداروں کے جو مکانات ہیں ان کو ان مکانات کا حق ملکیت کس طرح پہنچ سکتا ہے اس پر غور کیا جائے - اس ڈھنگ سے سوجنے کے بارے میں ہم طے کر رہے ہیں - اینسٹی لینڈ لارڈ (Absentee Landlord) کے بارے میں یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ ان کو ٹینٹس کے حقوق ملنے چاہئیں - لیکن یہاں آپ ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں - میں عرض کروں گا کہ حکومت کی پالیسی ری ایکشنزی (Reactionary) ہے - حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ وہ غریب اور اپر میں امتیاز کرنا چاہتی ہے - حالانکہ آج عوام یہ چاہتے ہیں کہ غریب و امیر کے فرق کو متاثرا جائے - عام طور پر ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اس بل کی تائید کریں اور اس پر غور کریں کہ کس طرح اس کو منظور کیا جائے ۔

\* شری کے وینکٹ رام راؤ (چنا کونڈور) مسٹر اسپیکرسر - جو بل ہمارے سامنے آیا ہے اوس کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ یہ بل ایک دفعہ ہائیکورٹ جانے کے بعد کالعدم قرار دیا گیا ہے - اس کے بعد اس میں کچھ تبدیلی کر کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے - ہم نے دیکھا کہ مینوسپالیٹیز کو جن اراضیات کی ضرورت تھی انہیں حاصل کرنے کے لئے مہینے دو مہینے میں لینڈ اکویزیشن کا قانون سنہ ۱۹۵۱ ع میں بنایا گیا - اس کو بھی کالعدم کر دیا گیا - یہ گوت گیتا اور رامائن کی طرح ہم چلتے آرہے ہیں - جنگ کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے عوام دشمن حکومت نے جو قانون بنایا تھا اوسکو منسوخ کرنے کی ضرورت تھی لیکن آج تک بھی اسکو جیسے کا قیسہ رکھا گیا ہے - جب وہ عدالت سے کالعدم قرار دیا گیا تو اوس وقت ہاری حکومت جاگا کے الٹھی - میں یو چھتا چاہتا ہوں کہ اس قانون کے عدالت تک جا کر کالعدم قرار پائے کی وجہ کیا ہے - کہاں ہیں آپ کے وہ لیگل الڈائیزر جنہیں ہزاروں روپیے تھخواہ دھکائیں ہوں ہیں یہ آپ کو بڑا ناز ہے اور جن کے متعلق آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے

لیگل اڈوائیزر کا ایسا منورہ ہے اور ہمارے لیگل اڈوائیزر نے یوں کہا ہے اور وون کہا ہے - اس قانون کو دیکھئر انہوں نے آپ کو صحیح مشورہ کیوں نہیں دیا جو ہائیکورٹ میں جا کر کالعدم قرار بایا - اس کے بعد میں اس بل کے بعض خدو حال پر روشنی ڈالوں گا - اس بل میں مالک مکان و کرایہ دار کے جو تعلقات ہیں انکو ریگولیٹ (Regulate) کرنے کی کوشش کی گئی ہے - ان کے تعلقات کو ریگولیٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے ہم اس کو مانتے ہیں کہ ایک قدم آگئے کی طرف بڑھایا گیا ہے - لیکن جس حد تک اس قانون کو آگئے بڑھانے کی کوشش کی جانی چاہیئے تھی نہیں کی گئی - اوس طرف آنریبل ممبرس یہ سمجھتے ہوں گے کہ "ہاؤز ٹو دی ٹینٹ"، House to the tenant ( ) کا نعروہ ہم لگا رہے ہیں - لیکن وسی زنجیروں کو توڑنے میں اور اس میں جو فرق ہے ہم اس کو محسوس کرتے ہیں - اس لئے ہم نے چند امنڈمنس اور چند سوچنائیں پیش کی ہیں۔

لینڈ لارڈ اور ٹینٹ کے جو تعلقات ہیں انکو ریگولیٹ کرنے کے سلسلہ میں مختلف پروپریئنس (Provisions) رکھے گئے ہیں - وہ مشتری جو ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرے ہو اس کے بارے میں الفاظ کہنا چاہتا ہوں - کنٹرولر یا یہاں یہ تعریف کی گئی ہے کہ -

"Controller means any person appointed by Government to perform the functions of a Controller under this Act"

ہارا روز مرہ کا تجربہ ہے کہ رنٹ کنٹرولر کے جو اختیارات ہیں وہ مال کے عہدہ داروں کے تفویض کردئے گئے ہیں - ڈپٹی کمٹریس ان اختیارات کو استعمال کرتے ہیں - میں مانتا ہوں کہ م RAFUE و نگرانی کی ساعت کا اختیار ڈسٹرکٹ ججس اور ہائیکورٹ کو دیا گیا ہے تب بھی ابتدائی مقدمات مال ہی میں چلتے ہیں حالانکہ مقدمہ کی بنیاد پہیں قائم ہوتی ہے اور لینڈ لارڈ و ٹینٹ کے تعلقات کے استقرار کے مقدمات مکملہ مال کے عہدہ داروں کے تفویض کیا جانا کسی طرح مناسب نہیں ہے - کنٹرولر کے اختیارات عدالتی حکام کے تفویض کشے جائیں تو مناسب ہوگا - پورے قانون کو دیکھیں تو کوئی دفعہ ایسی نہیں معلوم ہوئی کہ ان تمام امور کی ساعت کے اختیار کو عدالتوں سے چھیننا نہ گیا ہو - رنٹ کنٹرولر جو تصفیہ کرتا ہے اس کے خلاف م RAFUE یا نگرانی کرنا ہوتا عدالتی حکام کے پاس جاسکتے ہیں - دونوں جگہ سیمائیں سیلی ( ) حاصل کرنے کی بجائے کیا یہ صحیح نہیں کہ عدالتی عہدہ داروں ہی سے تمام امور کا تصفیہ کرایا جائے -

ایف - (۱) میں ٹینٹ کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے -

"Such sub-tenants and other persons as have derived title under a tenant before coming into operation of the Hyderabad Rent Control Order 1953 F., or this Act"

یہاں ذیل کرایہ دار کے جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں کیا وہ سہواً نظری کا نتیجہ ہیں کیونکہ دفعہ ۱ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مالک مکان کے ٹائیتل (Title) سے کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کرایہ دار کے حقوق کھو بیٹھتا ہے۔ تو میں سمجھنا ہوں کہ یہاں ٹائیتل کے جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ نا موزون ہیں انکو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

اس کے بعد میں مسور آف دی بل کی توجہ فیرنٹ ( ) کی طرف سندوں کراون گا۔ دفعہ ۲ کے تحت "سی" میں کہا گیا ہے کہ

"To the circumstances of the case including any amount paid by the tenant by way of premium or any other like sum in addition to rent after the 1st of April 1941".

یعنی کرایہ کے تعین کے لئے ضمن سی ہے اس کو کنٹرولر اپنی درستی میں رکھنے گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جب کوئی کرایہ دار اپنی کرایہ داری کو نافذ کرتا ہے تو بطور "پگڑی" کے کچھ رقم حوالہ کرتا ہے اگر یہ بات ہے تو مسور آف دی بل اس پر روشنی ڈالیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ پگڑی کے سلسلہ میں جو رقمات وصول کی جاتی ہیں ان پر بھی غور کیا جانا چاہیش کیونکہ یہ چیزیں خلاف مشا قانون ہیں۔ ان امور کے تعلق سے لینڈ لارڈ کے مقاد کو پیش نظر رکھا جائیگا یا ٹینٹ کے فالڈ کو یہ چیز صراحةً طلب ہے۔ رزیڈنسیل پرپریس (Residential purposes) اور نان رزیڈنسیل پرپریس (Non-residential purposes) کا بھی لحاظ رکھنا چاہیشے۔

پچاس سے سو روپیہ تک کرایہ دینے والے بھی ہوتے ہیں اور اوس سے کم کرایہ دینے والے کرایہ دار بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ پچاس فیصد کرایہ میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ اس سے چھوٹے موٹے جو کرایہ دار ہوتے ہیں ان پر بہت بڑا بار پڑیگا۔ سو روپیہ کرایہ ادا کرنے والے کا اسٹیشن (Status) اور رہنمائی اور چھوٹے کرایہ داروں کا اسٹیشن الگ ہوتا ہے۔ کم کرایہ ادا کرنے والوں میں اور بڑے کرایہ داروں میں امتیاز کی ضرورت ہے۔ جو لوگ کم کرایہ ادا کرنے ہیں یعنی جو لوگ پچاس روپیہ سے کم کرایہ ادا کرنے ہیں ان کے لئے ۲۵ فیصد کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ چھوٹے لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہو سکے۔ دفعہ (۵) کے تعلق میں عرض کروں گا کہ مکان کو ترقی دینے کی وجہ سے یا اوس کی تعینی و توثیق کرنے کی وجہ سے مکانت اگر بڑھ جائے تو کرایہ میں اضافہ کرنے کا حق لینڈ لارڈ کو ہو گا۔ اس کا حساب کرنے کے سلسلہ میں چہ فیصد سود آپ نے رکھا ہے اگرچہ اوس میں فاث اکسیلنگ ( )۔ بھی رکھا ہے لیکن آخری حد تک تو چہ فیصدی کی رکھی گئی ہے۔ تجارت کا محروم رکھنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہیکہ جو بھی کیبل (Capital) میں اسٹیشن (Invest)

کیا جانا ہے وہ ڈید کیبیٹل (Dead Capital) ہونا ہے اوس پر ہم اوس منافع کی نفع نہیں کرسکتے جو قرضہ کے سلسلہ میں بینک دینا ہے اوس بر زیادہ سود کی نفع ہم نہیں کرسکتے۔ اس لئے ڈید کیبیٹل پر جو سود جو فیصدی کا رکھا گیا ہے وہ غابل شور ہے (۷) میں یہ رکھا گیا ہے کہ لوکل انہار ڈیز (Loca authorities) کی جانب سے اگر ٹیکس میں اضافہ ہونا ہے تو کراہیہ میں بھی ہوسکتا ہے اس کا ایک سکشن رکھا گیا ہے۔ لیکن جہاں ٹیکس کم ہوتا ہے وہاں کراہیہ میں بھی کمی کرنے کے لئے کوئی پراویرن ہونا چاہئے۔ اس قسم کا کوئی پراویرن نہیں ہے (۸) میں یہ ہیکہ اگر مالک مکان کا پتہ نہ لگے تو کراہیہ دار کنٹرولر کے پاس رقم جمع کر سکتا ہے۔ پہلے کے ذریعہ میں ٹیٹش کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر مالک مکان کا پتہ نہ لگے تو وہ منی آرڈر کر سکتا ہے۔ اور فیس منی آرڈر کراہیہ میں سے وضعات کر لے سکتا ہے۔ یہاں رقم جمع کرنے کے سلسلہ میں اور نوٹس وغیرہ کے سلسلہ میں اخراجات کا بار مالک مکان پر ڈالنے کی بجائے کراہیہ دار پر ڈالا گیا ہے۔ اس لئے یہ کثڑا ڈکٹری (Contradictory) ہے۔ ڈپازٹ کو ہی کفالت سمجھنا چاہئے اور ڈپازٹ اماونٹ میں سے نوٹس وغیرہ کے اخراجات وضعات کرنا چاہئے۔

دفعہ (۱۰) کا تعلق کراہیہ دار کی یددخلی سے ہے۔ اس سلسلہ میں بعض وجوہات بتائے گئے ہیں۔ مجھے اون وجوہات پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سکشن (۲) کے ذیلی سکشن (۵) میں یہ ہیکہ

"that the tenant has secured alternative house or ceased to occupy the house for a continuous period of four months without reasonable cause..."

اس میں آئرنسیو ہاؤز (Alternative house) کے جو الفاظ رکھے گئے ہیں وہ ویگ (Vague) ہیں۔ آئرنسیو ہاؤز اس طرح سے ہونا چاہئے کہ وہ پرمیٹش (Permanent) نہ ہو۔ اگر وہ کسی اور جگہ منتقل ہو کر سکونت اختیار کیا ہو تو وہ آئرنسیو ہاؤز ویگ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں امنیٹش بھی ہاری جانب سے پیش کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن (۶) میں یہ ہیکہ

"that the tenant has denied the title of the landlord or claimed a right of permanent tenancy and that such denial or claim was not bona fide..."

ٹائل (Title) کے سلسلہ میں میں اپوان کی توجہ مبذول کراچا ہوں۔ یہاں پر پرمیٹش ٹیٹش کے جو الفاظ رکھے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہنے کے وہ دوامی کراہیہ دار ہے تو اوس کراہیہ دار کے حقوق کراہیہ داری حتم ہو جائیں گے۔ اگر سکشن (۴) کے ضمن (۳) کو دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ اگر کسی شخص کے ایک سے زائد مکانات ہیں تو اوس وقت کراہیہ دار کو یددخل نہیں کرسکتا۔ کراہیہ دار اوس کے پہنچ میں رہیگا اور اوس کو استفادہ کا حق حاصل ہو گا۔ ان دفعات کو پڑھنے کے بعد ہم یہ تیجھے

نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تاویکہ کوئی چیز وجود میں نہ آئے اوس وقت وہ کرایہ دار پرمینٹ کرایہ دار سمجھا جائیگا۔ لیکن بھریہ بھی کہا جاتا ہیکہ اگر کوئی کرایہ دار پرمینٹ کرایہ داری کا ادعا کرتا ہے تو اوس کے کرایہ داری کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں اس لئے پرمینٹ ٹینسی کے الفاظ کو نکالنے کی ضرورت ہے کسی کرایہ دار کے حقوق ختم ہونے کے لئے دوسری وجوہات بھی بنائی کئی ہیں اون کے تحت کرایہ داری کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک نہیں۔ بلکن محض اس وجہ سے کہ کسی کرایہ دار نے پرمینٹ ٹینسی کے رائلز (Rights) کا ادعا کرے تو اوس کے حقوق کرایہ داری ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک نہیں ہے۔ منکیت کے ادعا پر اگر اوس کے حقوق کرایہ داری ختم کئے جاتے ہیں تو اوس پر اعراض نہیں ہو سکتا۔

دفعہ (۲۲) کے پروسیجر کے سلسلہ میں مجھے یہ کہنا ہے کہ اس دفعہ کے تحت اگر کسی ٹینٹ کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا تو اوس کا اثر ذیلی کرایہ داروں پر بھی ہو گا۔ اگر کوئی شخص یعنی ذیلی کرایہ دار مقدمہ کا فریق نہ بھی ہوتا تو اس پر بھی فیصلہ کا اثر پڑیگا۔ حالانکہ اگر کوئی شخص فریق نہ ہو تو اس پر اس کا اثر نہ پڑتا چاہیے اگر ایسا ہو تو ذیلی کرایہ دار بنا کر تمام حقوق کا فیصلہ کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ اس سے لیٹیگیشن (Litigation) کم ہونے کا امکان ہے۔ کیونکہ آخر میں فراؤ (Fraud) اور کلوژن (Collusion) کے الفاظ بھی رکھئے گئے ہیں۔ کوئی ذیلی کرایہ دار کہہ سکتا ہے کہ سائز کے ذریعہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ایک طرفہ ہوا اس لئے بھر وہ رنٹ کنٹرولر کے پاس رجوع ہو گا۔ اس وجہ سے دفعہ (۲۲) کے پروسیجر میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ مرمت کے سلسلہ میں ۱۲/۱ حصہ یعنی ایک مہینہ کا کرایہ رکھا گیا ہے۔ لیکن آج کل حالات ایسے ہیں کہ اگر ایک دفعہ چونا ہی ڈالا جائے تو وہ ایک سہیہ کے کرایہ سے زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دفعہ (۲۶) کے سلسلہ میں مجھے یہ کہنا ہے کہ اس سلسلہ میں اس سے پہلے ہماری جانب سے ایک برایویٹ بلیش کیا گیا تھا اوس وقت پہلے اطہیان دلایا گیا تھا کہ عنقریب حکومت رنٹ کنٹرول پل مکمل شکل میں لانے والی ہے لیکن جب ہم اس قانون کو دیکھئے ہیں تو ماہیوسی خون ہے۔ مکانات کے کرایہ کے متعلق معمول سے طور پر بعض تعلقات کو ریگولیٹ (Regulate) کرنے کے سلسلہ میں یہ بل لایا گیا لیکن اس میں بھی بعض لوگوں کو اس سے مستثنی رکھا گیا ہے مثلاً سالاوجنگ اسٹیٹ وغیرہ۔ حالانکہ یہ وہ سرمایہ دار لوگ ہیں جنہوں نے کافی سرمایہ ان سے لیدا کیا۔ ایک طرف تو اون کی لکھوکھا ایک آراضی ہے اور دوسری طرف اون کے سینکڑوں مکانات ہیں۔ ان لوگوں کو آپ پروٹکشن (Protection) دہنسے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں عرض کروں گا کہ دفعہ (۲۷) کی ضراعت کے ماتوں

اسکرولٹی ( Scrutiny ) کرنے کی ضرورت ہے - بعض چیزوں اوس میں سے اومٹ ( Omit ) کی جاسکتی ہیں - اس طرح اسی بل کے خدم و حال ہیں - آن دی ہوں ( On the whole ) ہم اس بل کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں - بلکہ اس کو و یلکم ( Welcome ) کریں گے کہ کراپہ داروں اور مالکوں مکان کے حقوق کو اس میں ریکولٹ کیا گیا ہے - اتنا ہی مجھے کہتا تھا -

\* شری سری ہری - (کنوث) - مسٹر اسپیکر سر - اس بل کے بارے میں جو تقاریر ہوئیں اوس میں یہ چیز تسلیم کریں گئی ہے کہ واقعات اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس بل کو جلد از جلد پیش کیا جائے - چنانچہ ممبر انچارج نے اوس کو پیش کر دیا - لیکن اس پر اوس جانب سے اون کو محض اس وجہ سے بیار کباد نہیں دی گئی چون کہ یہ قانون ہائی کورٹ سے منسوب ہو چکا تھا اس لئے اب وہ یہاں پیش کیا گیا - لیکن میں اون کو بیار کباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بل یہاں لایا ہے - سابقہ قانون "حکم نگرانی کراپہ امکنہ" کی بہ نسبت اس قانون میں کافی تبدیلیاں ہو گئی ہیں - ان کی وجہ سے مختلف سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں - سابقہ احکام کے تحت م RAFUE سماحت کرنے کے اختیارات مکثی صاحب کو تھے اس بل میں وہ اختیارات ناظم صاحب عدالت ضلع کو دئے گئے ہیں - ساتھ ہی ساتھ سابقہ احکام میں ہائی کورٹ میں نگرانی پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی - این لئے وٹ ( Writ ) کی درخواست وہاں پیش نہیں کی جاسکتی تھی - لیکن این بل میں ہائی کورٹ میں نگرانی پیش کرنے کا اختیار دیا گیا ہے - اسی طرح جتنی بھی ضابطہ کی چیزوں ہو سکتی تھیں وہ اس میں درج کی گئی ہیں - خاص طور پر جو تبدیلی کی گئی ہے وہ یہ کہ سابقہ احکام میں دفعہ (۸) میں پیدھی کے سلسلہ میں جو شرائط و تجویز گئے تھے اب دفعہ (۱۰) میں اون شرائط میں اور بھی اضافہ کیا گیا ہے - اگر کراپہ دار پندرہ دن تک کراپہ ادا نہیں کرتا ہے یا کسی ذیلی کراپہ دار کو اپنے مکان میں رکھتا ہے یا ایسا کوئی فعلی کرتا ہے جس کی وجہ سے مکان کو نقصان پہنچ سکتا ہو وغیرہ وغیرہ ان کا اضافہ کیا گیا ہے - اگر ان چیزوں کی خلاف ورزی کریے تو وہ مکان سے پیدھی کئے جائے کا مستحق ہو گا - کراپہ میں اضافہ کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں بھی ایک خاص طریقہ اختیار کیا گیا ہے - تدریجی طریقہ اس سلسلہ بین اختیار کیا گیا ہیکہ جن مکانوں کا کراپہ کم ہو گا کم اضافہ ہو گا اور جن مکانوں کا کراپہ زیادہ ہو زیادہ اضافہ ہو گا - یہ چیز سابقہ قانون میں میں تھی میں امن بل کے سلسلہ میں بعض سمجھیشن دینا چاہتا ہوں - اس بل کے ضمیمه میں (۰۰) شہروں کے نام دئے گئے ہیں - میں کہوں کا کہ جیدرا یاد اسٹیٹ میں جہاں جہاں سی سینسپالائز ہیں اون شہروں کے نام بھی اس میں شامل کرنا چاہتے - جن کی آبادی پندرہ ہزار یا زیادہ ہے اون بھی سی سینسپالائز قائم ہوں ہیں اگر یہ قانون اون شہروں میں بھی لا کوئی ہو جائے تو وہاں کوئی کراپہ داروں کو بھی کافی سہولتیں مل سکتی ہے - کیوں نکوئی اون شہروں کے کراپہ داروں کو امن قانون کے نفاذ کے بعد کوئی طمانیت نہیں ہو گی - اون کو مالک مکان جب چاہے

بیدخل کر سکے گا۔ اور جس قدر چاہیے شرح کرايدہ بڑھادیگا۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو گا بعض گاؤں ایسے ہیں جہاں بہت زیادہ کرايدہ لیا جاتا ہے۔ اگر یہاں ۱۰-۱۰-۱۵ روپیہ کرايدہ لیا جاتا ہے تو وہاں سو روپیہ تک بھی کرايدہ ادا کرنے ہیں اس لئے وہاں بھی کرايدہ میں تخفیف ہونے کی ضرورت ہے۔ اون گاؤں میں بھی اس قانون کو نافذ کرنا چاہئے جہاں یہ نافذ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لئے میں تجویز کروں گا کہ جہاں سُنی میونسپالٹیز ہیں وہاں اس قانون کو بھی نافذ کرنا چاہئے۔

میرا دوسرا سچشنا یہ ہے کہ اس میں کنٹرولر کی جو تعريف رکھی گئی ہے وہ کسی عہدہ دار کو مقرر کرنے کے لئے ہے۔ لیکن جیسا کہ عموماً ہوتا ہے ڈپٹی کنکٹر ہی کو یہ کام بھی دیا جائیگا۔ اس بل کی دفعہ ۱۶ میں بتایا گیا ہے کہ اس کی روزانہ ساعت ہوتی رہے گی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوسکے کا کیوں کہ ڈپٹی کنکٹر کے ذمے دوسرے بہت سے کام ہوتے ہیں اور انہیں دورہ جانا پڑتا ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں گہ یہ اختیار عدالتون کو دین تو دفعہ ۱۶ کی پوری پوری تعامل ہوسکتی ہے۔ ورنہ جب ڈپٹی کنکٹر دوسرے پر جاتے ہیں تو وہ دو دو ہفتے دوسرے پر رہتے ہیں اس لئے روزانہ ساعت کا امکان نہیں رہتا۔ اس لئے میں یہ تجویز کروں گا کہ ابتدائی ساعت کا اختیار جو دفعہ ۱۶ کے تحت وہ عدالت کو دیا جائے تو اس بل کا منشاً ہو رہا ہوسکتا ہے۔

دفعہ ۲۸ میں جو سزاویں بتلائی گئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ احکام تاویں ضروری ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک ہزار روپیہ تک جو جرمانہ بتلایا گیا ہے وہ کچھ سخت ہے۔

اس بل میں یہ بھی ایک خاص شرط مالکان مکان پر عائد کی گئی ہے کہ جو بھی مکان خالی ہو جائے اس کی اطلاع فوراً کنٹرولر کو کریں تاکہ سرکاری اغراض کے لئے اگر اس کی ضرورت ہو تو سرکار اپنے قبضہ میں لے سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسما قانون نہ ہونے کی وجہ سے بہت جگہوں پر مکانات ملنے میں دقت ہوئی چنانچہ عادل آباد جب مستقر آصف آباد کو بنتقل کیا گیا تو وہاں کچھریوں اور سرکاری عہدہ داروں اور عملہ تک لئے مکانات نہیں مل سکے۔ اب ایسا نہ گا۔

میں یہ چند تجاویز آربیل منسٹر انجمن کے سامنے رکھتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ وہ ان کا لحاظ کریں گے۔

\* شری یل - یں - ریڈی - (وردها پیٹ) - منسٹر اسٹیکر سر - اب جو بل ہارے سامنے پیش ہوا ہے وہ کرايدہ داروں اور مالکان مکان کے دریان اچھے تعلقات کو رکھوں گا (Regulate)۔ کرنے کے لئے کسی حد تک قائمہ مند ہے۔ اس سے پہلے جو قانون تھا وہ منسوخ ہوئے کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا اس کو جلد پر کرنے کی ضرورت تھی اس لئے حکومت اس بل کو لائی ہے۔ مگر اسی سلسلہ میں چند اسی پاتیں ہیں جن پر ہافز کو غور کرنا ضروری ہے۔ سکنڈ ایڈنک کی نوبت پر جب امنٹسٹ پیش ہوں گے

تو تفصیلات میں ہاؤز کے سامنے رکھوں گا لیکن اس فرست رینڈنگ کی نوبت پر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسودہ قانون میں کنٹرولر کی جو تعريف کی گئی ہے مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ کنٹرولر عموماً ڈپٹی کلکٹر ہوتا ہے اس لئے یہ کام ان کے حوالہ نہ کر کے عدالتون کے سپرد کیا جائے تو فریقین کو اطمینان ہو سکتا ہے اور مکمل انصاف کیسے جانے کی بھی توقع ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ کرتے ہوے کنٹرولر کو یہ اختیار دیں تو کافی گز بڑھنے کا امکان ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں کنٹرولر سے فریقین مطمئن نہیں ہوتے اس لئے اس اختیار کو عدالتون کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ رنٹ وغیرہ کے اضافہ کے سلسلہ میں سنہ ۱۹۴۱ع کے باہر سہیں کے پہلے کو یسک ایر (Basic year) تصور کیا گیا ہے۔ قانون میں ایسی تجویز ہے۔ سنہ ۱۹۴۱ع ہی سے پہلے کے زمانہ کو یا سنہ ۱۹۴۱ع ہی کو معیار قرار دیا جائے تو اچھا ہے کیونکہ اسی زمانے سے کرایہ بڑھ رہا تھا مگر اس کے بعد ریزنیبل رنٹ (Reasonable rent) جو طریقے کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں چھوٹے چھوٹے کرایہ داروں کے لئے کیٹیگریز (Categories) نہیں بتائے گئے جو اندروں ایکسو روپیے کرایہ کے سمجھتا ہوں کہ۔ چھوٹے چھوٹے کرایہ داروں کے تحفظ کی زیادہ ضرورت ہے ۳۰۔۳۰ - ۲۰ - ۲۰ روپیے کرایہ دینے والوں کو قانوناً پروٹکشن (Protection) دینا ضروری ہے اس لئے انکی بھی ایک کیٹیگری بتائی جائے۔ عام طور پر جو اضافہ کرایہ ہوا ہے اور چھوٹے لوگوں کے لئے جو ۳۰ - ۲۵ روپیے کی شرح بتائی گئی ہے اس میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ لیکن اس میں کسی حد تک کمی کیجاں تو مناسب ہو گا۔ ایک چیز تو یہ بتائی گئی ہے کہ مکان میں تعمیر و ترمیم کی ضرورت ہو اور مرمت کرائی جائے تو پرست کے لحاظ سے کرایہ میں محسوب ہو گا۔ لیکن اگر اس پرست کے مطابق اعلان کر دیا جائے اور اگر کوئی بلندنگ ۱۲ ہزار روپیہ صرف کر کے مرمت کرائیں تو اس تجویز کی وجہ سے ۶۰ روپیے اس کرایہ میں ادا کرنا پڑیگا۔ رنٹ کنٹرول آرڈر اپلائی (Apply) نہ کرتے ہوئے خانگی طور پر جو باہمی تصفیہ کر لیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں اپسائیں ہوتا۔ اس لحاظ سے پرست بہت زیادہ ہیں اس میں ضرور کمی کی جانی چاہیئے۔ یہ چیز ہاؤز کے لئے قابل غور ہے۔

اس کے بعد ٹیکس کے سلسلہ میں میں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرست مقرر ہوئے کے بعد جو بھی ٹیکس بڑھے گا وہ کرایہ دار برداشت کرنے کے لئے اس پل میں رکھا کیا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ ٹیکس پیداوار کے لحاظ سے عائد ہوتا ہے۔ فائدہ ہو یا تقاضاً کمی ہو یا زیادتی اس کا اثر مالک پر بڑھتا چاہیئے۔ اگر مالک کو چھوڑ کر کرایہ داؤ کو ذمہ دار گردانیں تو یہ نہیک ہو گا۔ خواہ ٹیکس بڑھے یا کم ہو اس سے کرایہ داؤ کو بڑی کرنا چاہیئے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہم ایک ریزنیبل پروپرٹی

( Reasonable proportion ) ادا کرنے کے لئے وکھ سکتے ہیں۔ لیکن سنٹ پرنسٹ کراہدار ہی ادا کرے اس پر ہاؤز کو کافی توجہ کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایوکشن ( Eviction ) کے سلسلہ میں کافی احتیاط کے ساتھ یہ دفعہ مدون کیا گیا ہے۔ ہم ٹینسی ایکٹ کے دفعہ کو اور اس دفعہ کو دیکھتے ہیں تو دونوں میں کافی فرق پاتے ہیں۔ وہاں کے ایشیوڈ ( Attitude ) اور یہاں کے ایشیوڈ میں کافی فرق ہے۔ اس پر جب امنتمش پیش ہوں گے تو تفصیل کے ساتھ بحث کی جائے گی۔ یہاں سے متعلق اور قبضہ مخالفانہ کے ادعا کرنے سے متعلق یا ناجائز مداخلت کرنے سے متعلق بھی کافی احتیاط برتنے اور صراحت کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یہ ہو گا کہ زبان بھی یہ کہا جائے گا کہ ہمارے دریافت، زبانی معاہدہ ہوا تھا۔ میں دو گواہوں سے ثابت کر سکتا ہوں تو اس سے ان کے حقوق پر کافی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ رنٹ کنٹرولر کو حقوق میں مداخلت کرنے کا اختیار نہ ہوتا چاہئے اس لئے اس دفعہ کوخت ان مختلف چیزوں کی صراحت کریں تو مناسب ہو گا۔ سرمدی طور پر دیکھیں تو یہ اصول بہت اچھا معلوم ہوتا ہے مگر قبضہ مخالفانہ رکھتا ہے تو اس کو یہاں کرنا کجناہش ہے۔ اس لئے تحریری معاہدہ کی شرط رکھئے۔ متعلق بھی مشتری متعلقہ غور کریں۔

آخر میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دفعہ ۲۶ میں حکومت جن لوگوں کو مستثنی کرنا چاہتی ہے وہ کسی طرح بھی ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے اسلئے کہ جو جانبیاد کو روٹ آف وارڈز میں سرکار کے زیر انتظام رہتی ہے۔ وہ مستثنی ہو گی۔ سالار جنگ کی جانبیاد بھی مستثنی ہو گی۔ اور دیگر بڑے بڑے اشیائیں کو مستثنی کرنے کے باعث میں بھی بتلایا گیا ہے۔ انہیں مستثنی کرنے کی کیوں ضرورت واقع ہوں، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ کو روٹ آف وارڈز میں ان نابالغوں کی جانبیاد ہوں ہے جو انہی اسکو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ سرکار نے جانبیادوں کا انتظام انہی ذیسے لای ہے اسلئے وہ اپنا انتظام رکھتے ہے تو جو حقوق مالک کو ملتے ہیں وہی حقوق سرکار کو بھی ملتے چاہتیں۔ اگر جانبیاد سرکار کے قبضہ میں ہو تو بھی خواہ وہ عارضی ہی کیوں نہیں اس کے لئے ایک خاص ایشیوڈ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ میں یہ بھرپور ہوں۔ یہ آئی ہے کہ یا اٹا سنکارم میں ایشیوڈ کی زندگی کو اپنایا کہوں لہوں فرار دیکر انکے سرفیکیش کا بعد کر دئے گئے ہیں۔ تفصیل نے ان سرفیکیش کو منسخ کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملت سے جو ایشیش اسپر قابض ہیں اور جو ہیں یہ تو یہ کلٹ نہیں فارسی ملے ہیں انکی جانبیاد کو اپنایا کہوں لہوں فرار دیکر انہیں سرکار نکال دے ہم۔ ایشیوڈ ( Individuals ) کی حد تک تو قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی جانب سے خود اسکی مخلاف ویزی ہوئے ہے اور اسکو روکتے ہی طریقے مائل نہیں ہوتے اس کا یہ مطلب ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں گورنمنٹ کا انتظام ہوتا ہے وہاں ہوام کے حقوق کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ آئی انڈومنٹ ( Endowment ) کو ہی لجھتے۔ کیونکہ اسکا انتظام کیا ہے

اور جن لوگوں کا انڈومنٹ کی زمینات پر ۱۰۰ سال سے قبضہ ہے انہیں بیدخل کیا جا رہا ہے - یا اضافہ قول کا مطالبہ کیا جا رہا ہے - اگر وہ شخص نہیں دے سکتا تو زمینات ہراج کی حقیقی ہیں - اس طرح لوگوں کے حقوق کی کوئی حفاظت نہیں کی جاتی - قانون کا یہ منشاء نہونا چاہئے - مجھے معلوم ہوا ہے کہ گدوال کی مہا رائی نے ۱۲ ہزار ایکر اراضی کے اور وپری ہیں کئی ہزار ایکر اراضی کے اور کولا پور میں ۲ ہزار ایکر کے قابضین اراضی کو بیدخلی کا نوٹس دیا ہے - یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے اسکے لحاظ سے قول ادا کیا جائے تو نہیک ہے ورنہ بیدخل کیا جائیگا - حالانکہ ایسی زمینات یہ فابضین کا پٹھ خود بخود ہو جانا چاہئے - اس طرح گورنمنٹ رعایا کے حقوق پر اپنا ہتھ بٹھانے کی کوشش کرتی ہے - یہ مضبوط بالیسی ہے جسکو ہم برداشت نہیں کر سکتے - خواہ وہ کوئی گورنمنٹ پر اپڑی ہو - می - آئی - بی بلکس ہوں - یا سالار جنگ کا علاقہ ہو یا کورٹ آف وارڈ سے متعلق ہو ہر جگہ پبلک کو وہی حقوق ملنے چاہئیں جو اسی نوعیت کے ایک پرائیویٹ انڈیویجوں کی ملکیت کے صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں - میں متعلقہ منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پر غور فرمائیں -

ابھی ایک آریل ممبر نے یہ سجھاؤ دیا تھا کہ میونسپالیٹیز کو رنٹ کنٹرول کے شیڈول میں شریک کرنا چاہئے - جہانتک مجھے معلوم ہوا ہے جگتیاں اور گدوال میں میونسپالیٹیز نہیں ہیں - وہاں کافی آبادی ہے اور ۲۵ ہزار لوگ رہتے ہیں - جب آپ نے سریا پڑھے جنگاؤں وغیرہ جیسے مقامات کو شامل کیا ہے تو ایسی صورت میں بڑے بڑے ٹاؤنس جو شائد سہواً چھوٹ گئے ہیں انہیں بھی شریک کرنا ضروری ہے - اسی طرح انٹسٹریل ایریا یا بودھن - کوتا گڑھ - بیلم ہلی جیسے اہم مقامات بھی چھوٹ گئے ہیں - منسٹر صاحب انکی جانب توجہ کریں - اور انہیں بھی اس میں شامل کیا جائے -

The House then adjourned for recess till Thirty Five Minutes Past Five of the Clock.

The House re-assembled after recess at Thirty Five Minutes Past Five of the Clock.

[*Mr. Deputy Speaker in the Chair*]

\* شری اناجی راؤ گواستے (پریفی) - منسٹر اسپیکر سر - جو بدل ہاؤس کے سامنے پیش ہوا ہے اسی پر اس جانب کے اور اوس جانب کے آریل ممبرس۔ پس تقریبیں کیں اور اسکی تائید بھی کی اور اسپر تقدیم بھی کی - میں نے اس قانون کو پڑھنے کے بعد اپنی تقدیمات کو پورا کرنے والا تو اسکو نہیں پایا - یہاں نہیں ایکٹ پاس ہوا - جب ہم دیبات میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے لہنسی ایکٹ تو پاس کیا ہے۔ لیکن کہا جنہے

لوگوں کے پاس زیادہ مکانات ہے ان سے مکانات لینے کا قانون بھی پاس کیا ہے - خیر میں یہ توقع تو اس قانون سے نہیں رکھتا تھا - لیکن کم از کم ایسے لوگ جنکے پاس مکانات ہیں اور جو متوسط طبقہ کو جو ۱۰۰ روپیے سے کچھ کم یا زیادہ آمدی رکھتا ہے مکانات دیتے ہیں - اس طبقے کے لحاظ سے ہمیں اس قانون پر غور کرنا ہے - اس قانون میں خاص طور پر جو دفعہ ۱۰ اوکشن (Evictions) کے بارے میں رکھا گیا ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اس متوسط طبقے کے لحاظ سے وہ کس حد تک مناسب یا غیر مناسب ہے - بعض آنریل مبرس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ قانون کے لحاظ سے تو یہ قانون ترقی پسندانہ ہے - لیکن اس کا مقابلہ پہلے کے قانون سے کرنا غلط ہے کیونکہ وہ قانون کچھ اور ہی ماحول میں بنایا گیا تھا - گویہ قانون ہائیکورٹ کے فیصلے کے بعد آیا ہے لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ آج کے حالات کے لحاظ سے ہونا چاہئے - لیکن دفعہ (۱۰) میں پہلی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ کراپہ دینے کی جو تاریخ مقرر کی جاتی ہے اس کے بعد اگر ۱۰ دن کے اندر کراپہ دار کراپہ ادا نہ کرے تو مالک مکان ایوکٹ کر سکتا ہے - ورنہ ایک مہینے کا کراپہ دوسرا مہینے کی آخری تاریخ پر ادا نہ کرے تو ایک کر سکتا ہے - ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے معاشی حالات میں کیا یہ براویزن (Provision) کراپہ دار کے حق میں مفید ہو سکتا ہے - ۱۰۰ روپیے ماہانہ پانے والا ۱۰ یا ۱۵ روپیے ماہانہ کراپہ کے مکان میں رہتا ہے - کسی مہینے میں اسکا بچہ بیمار ہو جاتا ہے - یا بیوی بیمار ہو جاتی ہے ان بر علاج کا غیر معمولی خرچ پڑ جاتا ہے - اسی طرح کہ اور کتنی مشکلات ہیں - اسکی بیوی حاملہ ہوتی ہے - اسکی زچگی ہو جاتی ہے جس پر ۲۰۵۰ روپیے خرچ ہو جاتے ہیں وہ وقت مقرہ پر کراپہ ادا نہیں کر سکتا - ایسی صورت میں مالک مکان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کراپہ دار کو ایوکٹ کرائے - اس طرح میں کہو تو کہ یہ دفعہ مالک مکان کے حقوق کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے - کراپہ داروں کی معاشی حالت اور انکی مشکلات کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے یہ بہت بڑا لذکر ہے -

دوسری چیز (۲) اے کے بارے میں مجھے کہنا ہے - ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے کراپہ کے مکانات توبہت کم اور مشکل سے ملتے ہیں - لیکن ۶۰۰۰ روپیے یا اس سے زیادہ کے مکانات بہت متوجہ ہیں - کوئی شخص اپنی ضرورت کے لحاظ سے اپنا مکان حاصل کر کے کراپہ کی تکمیل کیلئے کسی سب ثینٹ کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے - آپ یہاں یہ کہتے ہیں کہ

"transferred his right under the lease or sublet the entire house or any portion thereof"

اس طرح اگر کوئی شخص اپنے مکان میں سب ثینٹ کو اتنا رکھتا ہے تو مالک مکان کو ایوکشن کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے - میری سمجھے میں نہیں آیا کہ آج کے حالات کے لحاظ سے یہ کھانہ تک مناسب ہے - وہ صرف اسلائی سب ثینٹ کو اپنے مکان میں اتنا رکھتا ہے کہ اسکو لسکے حسب استطاعت مکان نہیں بنتا اور اس طرح وہ ایک دوسرے ماتھیں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے

رکھ کر کرایہ کی تکمیل کر لیتا ہے لیکن ایسی صورت میں مالک مکان کو آپ ایوکشن کا اختیار دے رہے ہیں۔ دوسرے آنریبل ممبرس نے بھی اس پر اپنے خیالات ظاہر کئے ہیں۔

یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنکی وجہ سے مالک مکان کو کرایہ داروں کا تخلیہ کرانے کا کافی اختیار مل گیا ہے۔ اور بہت سے مالکان مکان اس طرح تخلیہ کراتے ہیں۔ میں آنریبل منسٹر مور آف دی بل سے جو خود بھی چند مکانات کے مالک ہیں یہ اپیل کروں گا کہ وہ کرایہ داروں کی مشکلات کو پیش نظر رکھیں۔ مسکن ہے کہ کرایہ دار اپنے مالی مشکلات کی وجہ سے بروقت پورا کرایہ ادا نہ کر سکتے ہوں محفوظ اس وجہ کی بناء پر تخلیہ کرانے کا اختیار دینا بہت بڑا ظلم ہو گا۔

ایک اور چیز آنریبل منسٹر کی توجہ میں لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ اکثر صورتیں ایسی ہیں کہ کسی شخص کے نام پر ایک مکان ہے اور اسکی بیوی کے نام پر بھی ایک مکان ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنی رہائش کے لئے مکان خالی کرانا چاہے تو باوجود اسکے وہ ایک مکان اپنی بیوی کے نام پر بھی رکھتا ہے تاہم اپنے نام پر جو مکان ہے جسکو اوس نے کرایہ پر دیا ہے خالی کر دیتا ہے۔ حالانکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی مکان کرایہ پر دیتا ہے تو اپنے رہنے کے لئے مکان رکھ کر اپنی رہائش کے علاوہ جو مکان ہے اوسکو کرایہ پر دیتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنی حسب ضرورت جس مکان کو وہ خالی کرانا چاہتا ہے جیسی کہ صورت ہو اپنے نام سے یا اپنی بیوی کے نام سے نوٹس دیتا ہے اور اپسی صورت میں اسکا استدلال یہ ہوتا ہے کہ میرے نام پر ایک ہی مکان ہے۔ اسلئے وہ اپنی رہائش کے لئے خالی کرانا چاہتا ہے حالانکہ یہ واقعہ کے خلاف ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ ایسی صورت میں تخلیہ کا اختیار اسکونہ دیا جانا چاہئے۔ نہ صرف حیدر آباد و سکندر آباد میں یہ صورتیں پیش آتی ہیں بلکہ ڈسٹرکٹس میں بھی مکانات کا مسئلہ پیچھے صورت اختیار کر لیا ہے۔ مکانات کے مالک براہم تخلیہ کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بجیت وکیل ہمیں بھی اسکا تجربہ ہے۔ اگر ان خرائیوں کو دور نہ کیا جائے تو مشکلات پیدا ہونگی۔ کرایہ ادا کرنے کے لئے کرایہ دار کو کافی مدت دینی چاہئے۔ اتساط سے یا کسی اور طرح سے حالات کا لحاظ کرنے ہوئے اذائی کی سہولت دی جانی چاہئے۔ مجھے کنسنر (Concern) منسٹر صاحب سے یہ عرض کرنا ہے کہ وہ اس جانب توجہ کریں۔ ورنہ یہ قانون کرایہ داروں کی حفاظت کا قانون نہ رہیگا۔ جب تک اس میں یہ چیزیں جنکی طرف میں اشارہ کیا ہوں شامل نہ کی جائیں میں آنریبل منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتے کے لئے تیار نہیں ہوں بلکہ اوس وقت تک تائید کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوں۔

کرایہ دینے کے متعلق سکشن ۸ و ۹ ہیں۔ کرایہ مالک مکان لینے سے انکار

کرے تو منی آرڈر سے بھیج دیا جائے۔ اگر منی آرڈر سے بھیج دیا جائے تو آپکو معلوم ہے کہ چاہئے کتنی ہی دفعہ منی آرڈر بھیجی جائے واپس کردا کرتے ہیں۔ اسلئے میں کہوں گا کہ ٹیننسی کے قانون میں جس طرح رکھا گیا ہے اوسی طرح یہاں بھی رکھنا چاہئے کہ اگر منی آرڈر واپس کر دیجائے تو تحصیل میں یا جہاں گورنمنٹ آرڈر دے جمع کر دیا جاسکے۔ یا اگر مالک مکان میں آرڈر واپس کر دے تو کراہیہ دار کو اسکا حق دیا جانا چاہئے کہ وہ عدالت میں یا رنٹ کنٹرولر کے دفتر میں جمع کرادے اور رنٹ کنٹرولر کو چاہئے کہ وہ کراہیہ مکان کے مالک کو پہنچا دے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح منی آرڈر واپس آجائے تو کراہیہ دار جو جز معاش آدمی ہوتا ہے اوس کراہیہ کو خروج کر لیتا ہے اس طرح تین چار ماہ کا کراہیہ باقی رہ جائے اور اسکے بعد مالک مکان کی طرف سے مطالبہ کیا جائے تو وہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ میں عرض کروں گا کہ اس سکشن میں جو اختیار دیا گیا ہے وہ کافی نہیں ہے اسلئے میں نے جو مسیحی دیا ہے اسکو قبول کرنا چاہئے کہ کراہیہ دار کو اسکا اختیار دیا جائے کہ وہ رنٹ کنٹرولر کے دفتر میں جمع کرائے یا عدالت میں۔

ایک اور چیز جسکی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سکشن ۱۲ میں سمجھتا ہوں کہ کراہیہ دار کو ستانے کیلئے رکھا گیا ہے۔ جب مالک مکان کراہیہ بڑھانا چاہتا ہے اور کراہیہ دار اسکے لئے آسادہ نہیں ہوتا ہے تو مالک مکان طرح طرح سے اس کو ستانے کی کوشش کرتا ہے۔

**"No landlord shall, without just or sufficient cause, cut off or withhold any of the amenities enjoyed by the tenant"**

یعنی مالک مکان کو اختیار دیا گیا ہے کہ

**"just and sufficient cause"**

فرض کیجئے کہ کراہیہ دار مکان کا تخلیہ نہیں کرتا ہے تو مالک مکان اسکو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لائٹ کا نکشن (Connection) کاٹ دیتا ہے۔ نل پنڈ کر دیتا ہے یا اور جو سہولتیں اسکو حاصل ہیں اون سے استفادہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اور وہ خیال کرتا ہے کہ میں وکیچہ کروہا ہوں "جسٹ اینڈ سفیشیٹ کاز" (Just and sufficient cause) ہے۔ اسکے متعلق کراہیہ دار کو اعتراض ہو تو وہ کنٹرولر کے پاس جائے۔ اسکی بجائے یہ دفعہ ایسی ہوئی چاہئے کہ کوئی لینڈ لارڈ (without the permission of the Controller) ایسا نہیں کر سکتا جائے اسکے یہ کہا جائے کہ کراہیہ دار عدالت میں جائے اور وہاں فیصلہ ہوئے تک وہ تکلیف میں مبتلا رہے یہ کبھی نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ جس طرح یہ سکشن مدون کیا گیا ہے اوبک وجہ سے کراہیہ دار مشکلات میں مبتلا ہوگا۔ گواں اسکا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ عدالت میں چائے۔ جیسا کہ آفیل ہوم منسٹر اکثر کہا کرتے ہیں کہ

بولیں ظلم کرنے ہے تو آپ عدالت میں جاسکتے ہیں - ویسے ہی یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ مالک مکان ظلم کرتا ہے تو کرایہ دار عدالت میں جائے ۔ وہ نل بند کردے تو عدالت میں جائے لائیٹ ( Light ) بند کردے تو عدالت میں جائے ۔ اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے۔ جیا ہے اسکے یہ طریقہ کرنا چاہئے کہ جب تک مالک مکان کنٹرولر کی منظوری نہ لے لے اس طرح کے افعال نہیں کرسکتا ۔

ایک اور چیز ریپیر ( Repair ) کے تعلق سے کہنا ہے ۔

" 15 (1) Every landlord shall be bound to keep the house in reasonably good repairs. "

سب سکشن ۲ میں یہ رکھا گیا ہے کہ

" If the landlord neglects to make within a reasonable time after the notice by the tenant is served upon him by post or otherwise, any repairs which he is bound to make under sub section (1), the tenant may make the repairs himself and deduct the cost of such repairs from the rent or, otherwise recover it from the landlord, provided that the amount so deducted or recoverable in any year shall not exceed one twelfth of the rent payable by the tenant for that year. "

ایک تو یہ ہیکہ اسمن ۱ / ۲ حصہ جو رکھا گیا ہے غلط ہے ۔ مثال کے طور پر یہ کہوں گا کہ ایک ہائل میں چلاتا ہوں جسکا کرایہ سائز روپیہ ماہانہ ہے ۔ اسکی الگزیشی خراب ہو گئی تھی ۔ ہم نے مالک مکان کو درستی کیلئے نوش دی انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی ہے جو اسے خود ریپیر کر لیا جسمیں ستر ۔ اسی روپیہ خرچ ہوئے ۔ ہم نے کرایہ سے منہا کرنا چاہا لیکن انہوں نے اسکو قبول نہیں کیا ۔ آخر میں عدالت میں جا کر اس کا تصنیف ہوا اور ہمکو چہ مہینے کا کرایہ یکمشت ادا کرنا پڑا ۔ چہ مہینے کا کرایہ یکمشت ادا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اسکا اندازہ اون لوگوں کو ہو گا جو اس قسم کے اسٹیلووٹس ( Institution ) چلاتے ہیں ۔ اسکے لئے آپ نے کیا کمپلشن ( Compulsion ) رکھا ہے ۔ یکلخت کسی کو چہ مہینے کا کرایہ دینا پڑے تو کتنی مشکل کا ساتھا ہوتا ہے ۔ اسلئے میں کہوں گا کہ یہ ریپیر ( Repair ) کی جو دلخواہ ہو تو یہ کہیں ہے ۔ یہ چیزوں ایسی ہیں کہ ان سے کرایہ دار کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے ۔ دوسری چیز مجھے یہ عرض کرنا ہے اور جیسا کہ ایک آریل ممبر نے کہا تھا کہ جس کو ہائیکورٹ کے اختیارات دے دی گئے ہیں ۔ یہ اچھی چیز کی ہے ۔ لیکن اس کے ساتھ سائز آریل منٹر اس کے متعلق غور کریں کہ جہاں تک ہوسکے روپیبوکے کسی افسوس کا کوئی تعلق اس میں نہ آئے ۔ یعنی تھصیلدار ۔ لکھن یا ذہنی کاکٹریس کا اس سے تعلق نہ ہو ۔ روپیبوک اس سرمن کسی قانون کی پابندی یا اوس کا اپلیمنٹ ( Implement ) اچھی طرح نہیں کو سمجھتے ۔ عدالت ہی صحیح معنوں میں اوسکو اچھی طرح اپلیمنٹ کہا سکتی ہے ۔ آریل منٹر اس کا نہیں وکھیں کہ اگر روپیبوک اس سرمن کا تعلق اس قانون

سے ہو جائیگا تو آپ کا پورا قانون چوپٹ ہو جائیگا اور اوس کا منشا بھی چوپٹ ہو جائیگا۔ ایک ایک مقدمہ پیش ہوگا اور وہ ان سالہا سال تک چلتا رہیگا۔ خود کئی مرتبہ آنریل منسٹر نے بھی یہ کہا ہے۔ بہ حیثیت وکیل وہ خود بھی اچھی طرح واقف ہیں کہ ریوبینیو آفس میں کس طرح کام چلتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ریوبینیو آفس کا کام اتنا پیچھے ہے کہ اوسکے وجہ سے انہوں نے ریوبینیو آفس میں جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ خود اون کو اس کا تحریر ہے۔ اس لئے میں عرض کروں گا کہ اس ایکٹ کے امپلیمنٹیشن کے سلسلہ میں ریوبینیو آفس کا کوئی تعلق نہیں رہنا چاہئے۔

میری سمجھے میں نہیں آیا کہ دفعہ (۲۶) کیوں اس طرح رکھا گیا ہے۔ خاص طور پر اوس کا ضمن (سی)۔ عوامی اور جمہوری حکومت کے دور میں ایک قانون ایک شخص کے لئے اور دوسرا قانون دوسرے شخص کے لئے کس طرح رکھا جاسکتا ہے۔ خاص حکم کے ذریعہ بعض خاص اشخاص سے متعلق یہ قانون جو لاگونہیں کیا جارہا ہے وہ کیوں نہیں کیا جارہا ہے۔ ایسے لوگ اس سلسلہ میں آئے والے ہیں جن کے پاس زیادہ مکانات ہیں جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں۔ لیکن اون ہی کو اس قانون کی پابندی سے دور رکھنے کی کوشش کیجا رہی ہے وہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ آلکریٹک (Autocratic) گورنمنٹ نہیں ہے ڈیمو کریٹک (Democratic) گورنمنٹ ہے۔ ایسی حالت میں بعض لوگوں کو جن کے اشیش ہیں یا جن کے ہرولیجس ہیں اون کو اس قانون کی پابندی سے اونچا سمجھنا کو نسا طریقہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک آنریل میر نے کہا اس میں راج ہر سکھ بھی آسکتے ہیں خود آنریل مورو آپ دی ہل بھی آسکتے ہیں قانون جب ہم بناتے ہیں تو اوسیں راج ہر سکھ کی یا آنریل منسٹر کی یا کسی ایم ایل ائے یا کسی ڈپارٹمنٹ کی کوئی تخصیصیں نہیں ہونا چاہئے۔ قانون کی پابندی ہر ایک کو کرنا لازمی ہے۔ اور اوس کا نتیجہ بھی ہر ایک کو بھکتا ہوتا ہے۔ لیکن دفعہ (۲۶) میں جو کچھ رکھا گیا وہ کم از کم آج کے ڈیمو کریٹک سٹ اپ میں جیجنے والا نہیں ہے۔ آنریل منسٹر کم از کم اس پر غور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اعتراض کیا جائے کہ آنریل منسٹر صاحب نے خود کو بچانے کے لئے یہ رکھا ہو۔ کیوں آپ اپسے اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ میں نیک نیتی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے سٹ اپ میں یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ شیڈول میں جن (۰.۰) شہروں کے نام بنائے گئے ہیں اون کے متعلق جیسے یہ کہنا ہے کہ شائد یہ سمجھا جا رہا ہو کھیدر آباد سکندر آباد باڑے ٹیکے شہروں اور نیٹر کٹ پلیس (Places) میں ہی گھروں کی قلت ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ بہت سے ٹریڈنگ سٹریٹس میں بھی مکانات کی قلت ہے۔ بعض وقت تو یہ ہوتا ہے کہ خیدر آباد میں مکان مل سکتا ہے لیکن نیٹر کٹ میں یا اپسے نیڈلکے سٹریٹس میں مکان نہیں مل سکتا۔ چو مکان یہاں ۰۔۰ روپیہ میں مل سکتا ہے وہ نالدیٹ میں سو روپیہ میں بھی نہیں مل سکتا۔ بڑی ہی مکانات کی قلت ہے۔ جو کوئی بھی مکان مل جاتا ہوگا اسی میں رجھے ہر بیبور ہو جاتے ہیں آج کل دیجاتوں میں بھی بھی حالات یہاں ہو گئے ہیں۔ آپ نے ہیڈول میں تعلقہ سیلو ٹکو رکھا لیکن میں کہوں گا کہ مستحق اور

بسم میں جہاں ٹاؤن میونسپالٹیز ہیں اور جہاں بڑے بڑے ٹرینڈنگ سنترس ہیں اور جہاں کا پاپولیشن بڑھ گیا ہے وہاں بھی مکانات کی قلت ہو رہی ہے۔ میں اون سے استدعا کروں تاکہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اس شیدول میں اور شہروں کے ناموں کا اضافہ کروں۔ اور ٹرینڈنگ سنترس اور اندھہ سریل سنترس میں جہاں مکانات کی قلت ہے وہاں بھی اس قانون کا امپلیمنٹیشن کرنے کا حکم دیا جائے تو مناسب ہو گا۔

\* شریعتی شاہ جہاں یکم (بڑگی) مستر اسپکسر۔ آج ہمارے سامنے رنٹ کنٹرول کا جو بل لا یا گیا ہے اوسکو میں پہلے کے بل سے بھی بہتر سمجھتی ہوں پہلے کے بل میں بہت سی چیزوں ایسی تھیں جن میں واقعی اصلاح کی ضرورت تھی۔ مگر اس ہر جو تنقید کی جا رہی ہے کہ اس قانون کی وجہ سے مالک مکان کرایہ دار کو فوراً یہ دخالت کر دیگا اور اوسکو نکال دیگا۔ نکال کیسے دیگا۔ عدالت ہے۔ کورٹ ہے۔ رنٹ کنٹرولر کا دفتر ہے۔ ایسا نہیں نکل سکتا۔ واقعی اگر کوئی شخص زبردستی سے کسی مکان کو کرایہ پر لینے کے بعد یہ کہیے کہ چونکہ میں بارہ سال سے اس میں مقیم ہوں اس لئے یہ میرا مکان ہے تو نکال دیا جائیگا۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ مکان کا کرایہ یعنی کے سود کے مہائل ہونا چاہیئے۔ میں یہ کہونگی کہ یعنی میں جو پیسہ جمع رہتا ہے اوسکو دیکھ نہیں لگتی۔ اور نہ وہ ویسٹ (Waste) ہوتا ہے۔ نہ اوس پیسے کے متعلق لوٹ مار کا ڈر رہتا ہے۔

البتہ کبھی یعنی ڈوب جائے تو اوس وقت پیسے ڈوب جانے کا خوف رہتا ہے۔ لیکن جو شخص مکان بناتا ہے اوس کو اپنے پیسے کا ڈر رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مکان میں کرایہ سے رہتا ہے اور اوس مکان کی عمر اگر (۸۰) سال کی ہوں چاہیئے تو کرایہ دار اوسکی عمر ۰۰ سال کی کر دیتا ہے۔ کرایہ دار یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کرایہ ادا کرتا ہوں مکان کا جس طرح چاہے استعمال کروں گا۔ کیوں نہیں ایک سبل لیکر دیوار میں سوراخ ڈال دوں۔ بڑی بیدردی سے کرایہ دار مکان کو استعمال کرتا ہے۔ (انٹریشن) میں یہ تجربہ سے کہہ رہی ہوں۔ کیونکہ میں نے خود بھی کرایہ پر مکان دیا ہے۔ مالک مکان کے پاس بھی پیسہ منت نہیں آتا۔ پیسے کہیں سے ٹپکتا نہیں۔ پیسہ چپ جمع نہیں ہوتا۔ مکان بنانے کے لئے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ پیسہ ہونے کے باوجود کوئی مکان بناتا کر تو دیکھ لیے کہ کیسے مشکلیں پیش آتی ہیں۔ مکان بننے کے بعد کرایہ دار جب اوسکو توڑ پھوڑ کرتا ہے تو تب معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ کسطریج بریاد ہو رہا ہے۔ مکان کی ہر سال درستی کے لئے پیسہ لگایا جاتا ہے۔ پہلے زبانہ میں اوڑھ آئے لیتا تھا اور چار گنڈے میں مزدور ملتا تھا۔ اب تین روپیہ اوڑھ لیتا ہے اور مزدور فی بیچاری ایک روپیہ لیتی ہے اور میرے بھائی مزدور دیڑھ روپیہ لیتے ہیں۔ پہلے میں اور اب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو مکان ۴۰۰ سو میں پنتا تھا اب ۱۲ ہزار میں بھی نہیں پنتا۔ اگر مالک مکان کی سہولتوں کا بھی اس بل میں خیال نہ رکھا جائے تو کوئی جسم مکان بنانے کے لئے تیار نہ ہو گا۔ جب لوگ مکانات نہیں بنائیں گے تو ہمارے پاس روز بہ روز پاپولیشن جو بڑھ رہا ہے اوس کے لئے کہاں سے مکانات

انیونگے - اگر ہم یہ سوچنے کے گورنمنٹ ہر روز مکانات بنایا کریں تو اوس کے لئے ہی پسہ کھان سے آئے - ٹیکس بھی زیادہ نہیں کرنا چاہئے تو پھر کھان سے روپیہ لا لایا جاسکتا ہے - روس اور امریکہ میں جاکر ڈاکہ تو نہیں ڈال سکتے - اور وہ لوگ ہم کو پسہ بھی نہیں دینگے - مجھے کرايدہ داروں سے بھی ہمدردی میں کیونکہ اونکے پاس مکانات نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف الہارہی ہیں - لیکن پسہ والوں کو بھی تغیریب دیجاتی چاہئے تاکہ وہ لوگ مکانات بناسکیں - ڈرکے مارے تو وہ لوگ پسہ زمین میں گاڑھ کر رکھئے ہیں - ورنہ لینڈ ٹوڈی ٹلر (Land to the tiller) کی طرح ہازو ٹوڈی ٹینٹ (House to the tenant) نہ ہو جائے - آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سارے ملک میں کس طرح جہوپڑیاں اور گرسیاں بنی ہوئی ہیں - بل میں کرايدہ کے متعلق چہ پرسنٹ جو رکھا گیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اوس میں کوئی خراب بات نہیں ہے - روس میں بھی چہ پرسنٹ دیا جاتا ہے - دولتمندوں کو بھی اونکے کیپیٹل کا حصہ دیا جاتا ہے - یعنک میں تو پسہ جمع رہتا ہے لیکن مکان میں پسہ گھستا چلا جاتا ہے - یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ کورٹ آف وارڈس کی بلانکس سالار جنگ اسٹیٹ وغیرہ کو اس قانون سے کیوں غیر متعلق رکھا گیا ہے - میں سمجھتی ہوں کہ کوئی شریف آدمی کورٹ میں جا کر پیروی کرنا نہیں چاہتا - لیکن مالک مکان بننے کے بعد اوسکو جا کر پیروی کرنے پڑتی ہے - وہاں کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں - میں بھی مکان کی مالک ہوں میں نے بھی عدالت میں نو سال تک دھکے کھائے ہیں - میرے جیسی اور دوسری مثالیں بھی ہوتگی - کورٹ آف وارڈس - گورنمنٹ اور سالار جنگ اسٹیٹ حقیقی معنوں میں مالک مکان نہیں ہوتے اونکے ملازم اور منتظمین کھان تک کورٹ میں دھکے کھاتے ہوئیں - اونکے لئے ایک علمند قانون بتنا چاہئے - میرے جیسا کوئی مالک مکان ہو تو وہ وکیل بھی رکھ سکتا ہے اور پیروی بھی کر سکتا ہے - لیکن کورٹ آف وارڈس کے مکانات تو بیوان اور بیمود کے ہوتے ہیں - وہ لوگ کیا پیروی کر سکیں گے - یہ بھی کہا گیا کہ اس کا تصفیہ عدالتوں سے ہوا کرے اور مال کے صبغہ میں یہ کیس نہ جائیں - میں کہونگی کہ کورٹ میں بھی پچیس برس سے پہلے معاملہ ختم نہیں ہوتا - وہاں بھی وکیل رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے - لیکن یہاں رنٹ کنٹرولر رہیکا جس کے اوپر ایک اور آدمی رہیکا - مکانوں کا تصفیہ ایک سال نہیں دیٹہ دو سال میں ہو جائیگا لیکن پندرہ یس بوس تو نہیں لیکن کسے اس لئے یہ بل مبارک باد دینے کے قابل ہے - میں کہونگی کہ میرے بھائیوں نے جو اعتراضات کئے ہیں وہ واہس لے لیں - اور اس بل کو بغیر کسی استثنائے کے قبول کر لیں تو مہربانی ہو گی -

\* شری مید اختر حسین (جنکاؤن) جناب اسیکر صاحب - میں اس مسودہ قانون کے پارے میں کچھ عرض کرنا نہیں، چاہتا تھا اس لئے کہ فطری طور پر میں قانون نے زیادہ کھبراتا ہوں۔ خاصہ طور پر ہمارے ملک میں اور ہمارے سماں میں قانون کی جو پہنچ گئیں ہیں وہ اتنی بڑی ہوئی کہ اُن کو ایک عام آدمی کہلاتی ہے جس کا اس سے وابستہ تعلق

نہ ہو اچھی طرح سے سمجھنا مشکل ہے - میں سمجھتا ہوں اور میرا یہ پختہ یقین ہے کہ ایک ابھرے ہوئے ساج اور ترق کرنے کو سوسائٹی جس میں لوگوں کے پیشے اور تعلقات کچھ اس قسم کے ہیں کہ جہاں لوٹنے والی طبقات کم سے کم تر ہو جائیں تو وہاں قانون کی کتابوں کے انبار اور قوانین کی طو مار بھی کم سے کم تر ہو جاتی ہے - قانون کا جو انسان اور نظریات پہلو ہے وہ ایک اہم اور مضبوط بنیاد رکھتا ہے - جب سے انسانی ساج وجود میں آیا ہے اسی وقت سے قوانین اور قواعد کی بھی انسان نے ضرورت نہیں کی ہے - لیکن یہ کس طریقہ سے دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا گی اور اس میں العجین پیدا ہو گئی اور عام آدمی کیلئے اس کا سمجھنا مشکل ہو گیا تو اس کو جائزے کے لئے ہمیں ساج اور اس کے مختلف طبقات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہو گی - جیسا کہ میں نے ابھی کہا قوانین کی طو مار بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی پیچیدگیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے قانون عام قانون نہیں رہا - یہ قانون کا اصولی اور نظریاتی پہلو ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں - اچھے قانون دان اصحاب یہاں موجود ہیں ممکن ہے کہ وہ اس غلطی کو درست کریں - لیکن جب میں نے اپنے تعلیمی مسلسلہ کو جاری رکھنے ہوئے یہلے سال میں داخلہ لیا تو لکچر ٹائڈ کرنے اور کتابیں بڑھنے کا مجھے موقع ملا لیکن جب قوانین کے اطلاق پہلو پر استدی (Study) کرنا پڑا تو مجھے اپنی تعلیم ترک کر دینا پڑا - اس لئے کہ تاویلات اور نظائر میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ ان کو واخذ نہیں کر سکتے - ایک کامن میان اس کو نہیں سمجھ سکتا یہی وجہ ہے کہ یہ قوانین جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ سوسائٹی کا عکس بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں اوس سوسائٹی کا جو طبقات سوسائٹی ہے اور جب وہ سوسائٹی طبقات پر مشتمل ہے تو پھر اس میں العجین ہونا بھی لازم امر ہے - مثال کے طور پر یہ مسودہ قانون جس پر تقریر کرتے ہوئے ایک آنریل ممبر نے ابھی یہ انکشاف کیا کہ وہ خود ایک لینڈ لارڈ ہیں اور یہ بتلایا ہے کہ انہیں کیا دقتیں پیش آتی ہیں تو .....

شریعتی شاہجهان بیگم - میرا کراہیہ دار بھی لینڈ لارڈ (Land lord) ہے -

شری سید اختر حسین - ہمیں عوض کرو رہا تھا کہ اگر آپ لینڈ لارڈ ہیں اور آپ کا ٹیکٹ بھی لینڈ لارڈ ہے اور دیکر لینڈ لارڈ بھی ہیں تو یہ نازک اور پیچھا وشنٹر قابلِ خور ہیں - ان نازک اور پیچیدہ رشتہوں کا جب میں نے مطالعہ کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہمارے پاس نہ صرف ٹیکٹس ہیں بلکہ لینڈ لارڈ ہیں ہمیں ہیں - اور نہ صرف لینڈ لارڈ ہیں بلکہ لینڈ کے بھی لینڈ لارڈ ہیں وہ لینڈ لارڈ ہیں جو بڑی بڑی کوٹیاں اپنے قبیلے میں دکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ بلڈنگس بنائی ہیں ان سے استفادہ کرنا ان کا ایک بطری حق ہے اور وہ ان مکانات یا جائیدادوں کے کراپوں سے اپنی تجویزوں کے بوجہ میں اضافہ کر رہے ہیں - دوسری طرف ہماری ساج میں ایسے طبقات بھی ہیں جو لینڈ لارڈ کمہلاتے ہیں لیکن ان کی حالت لینڈ لارڈ کی نہیں ہے اس لئے کہ کسی بیوہ کے پاس ایک آدھے مکان ہے تو وہ

وہ لینڈ لارڈ کی تعریف میں داخل ہوتی ہے لیکن جو کراہی اسے وصول ہوتا ہے اوس سے بمشکل اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ اس لئے یہ جو فرق آرہا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے اور قانون نہ بنایا جائے تو سوائے اس کے کہ وہ مختلف تاویلات اور بھانے جن سے مختلف پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور وکلا کے لئے (میں وکلا دوست جو اس ایوان میں ہیں معاف فرمائیں) کچھ زیادہ مقدمات اور کیسیں ملیں گے۔ ایک یا دو مکن والے مکان داروں کے لئے دقتیں اور دشواریاں پیش آنے والی ہیں اس لئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسودہ قانون بنایا گیا ہے اس کو ایوان کے سامنے پیش کر کے اس کی منظوری حاصل کرنے سے قبل جیسا کہ جمہوری طریقہ ہونا چاہئے اور ہے اخبارات اور دیگر ذرائع سے اعلان کیا جاتا اس لئے کہ اس قانون کا براہ راست تعلق ان لوگوں سے ہے جو شہروں میں رہتے ہستے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تشویر ہوتی اور حکومت کی طرف سے یہ دعوت عام دیجاتی کہ اس میں کمن قسم کی اچھائیاں یا برائیاں ہیں ان کا اظہار کیا جائے۔ لیکن اب اس مسودہ قانون کو ایوان میں لا کر یہ خواہش کی جاتی ہے کہ ہم اس کو پاس کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر بحث کی جائے اور ترمیمات دی جائیں اگر کوئی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ داد رسی اور انصاف کا جو منشا ہے۔ جو در اصل قانون کا منشا ہوتا ہے۔ وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسودہ قانون کے اثر میں جو طبقات اور مختلف حیثیتوں کے لوگ آنے والے، ہیں ان میں ہمیں تمیز کرنا ہوگا۔ یہاں انہیں صرف دو کلاسیں میں بٹا گیا ہے اور آپ کے ناتے رشتے جو کراہی دار اور مکان دار میں ہوتے ہیں انہیں تعین کریں کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں چند دفعات ہیں لیکن عام لوگ۔ ہماری شہری زندگی میں جو لوگ نظر آتے ہیں ان کو دو حصوں میں منقسم کرنا میں نہیں سمجھتا کہ صحیح اور مناسب ہے۔ اس لئے کہ ہمارے شہروں میں جو لینڈ لارڈس اور مکاندار ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا وہ دو قسم کے ہیں ایک تو وہ مالکان اسکھے ہیں جن کی آمدی یا گزر بسر کا ذریعہ ہیں جائیداد ہے اور دوسرا ہے وہ لینڈ لارڈس ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مکانات اور جائیداد ہے اور وہ اس کو ہماری کی حیثیت سے بڑھاتے جائے ہیں۔ اس پر اپری ٹوکیبیٹ تصور کرتے ہوئے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس رقم پر مناقعہ جو بنک سے اصل کیا جاسکتا تھا اس کے بجائے مکانات پر لگانا ان کا مشغله ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا قانون مدون تھیں ہوا تھا لیکن اب جب کہ ایسا مسودہ قانون لایا جا رہا تھا اس وقت یہ ضرورت تھی کہ کسی ازکم اس جمہوری دور میں اس بات کی ضرورت تھی جب کہ لوگ سماج اور اپنی طرز زندگی کے ہمارے میں ایک نئے نقطہ نظر سے سوچنے لگے ہیں۔ وہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کچھ فرق و امتیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ تب ایسے لینڈ لارڈین جن کہ چار چھ سلکیاں یا دو چار مکانات ہیں اور اس سے اتنی آمدی ہوئے ہے کہ اس کی گذر بسر کے لئے کافی ہو جائے اور ذوسی طرف ایسے مالکان جائیداد میں ہو

بڑی بڑی کوئیوں کے مالک ہیں ان کا ایک علحدہ طبقہ تصور کرتے ہوئے قانون کی تدوین ہوتی۔ اون مالکان امکنہ پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگائی جاتیں جو بڑے ہیں اور چھوٹے مالکان امکنہ کے لئے کم پابندیاں لگائی جاتیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان رشتون پر بھی نظر رکھی جاتی تو زیادہ داد رسی اور انصاف ہو سکتا تھا۔

اس سلسلہ میں اس قانون کی دفعہ ۲۶ کے صرف ایک پہلو پر جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں زیادہ بات چیت نہیں ہوئی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آرائش بلدے کے مکانات کا حصہ پچھلے چند مہینوں سے اتنا عام ہو چکا ہے اسکی تفصیلات میں جانے کی وجہ سے ضرورت نہیں۔ لیکن اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان مکانات میں رہنے والوں کی جیسا کہ منشی صاحب نے فرمایا تھا سب کی سب نہیں تو ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو نجلے درمیانی طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان مکانات کے کراپوں میں اضافہ سے متعلق حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے خلاف نمائندگی کی گئی اور اس پر حکومت کی جانب سے جس کی قسم کی روپورث کی گئی ہے انکی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے میں ایک بات یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کونسی بنیادی وجوهات تھیں یا بنیادی اصول تھے جس کی وجہ سے اس قانون کے اثر سے ان مکانات کو خارج کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ سالار جنگ اسٹیٹ اور اسی قسم کے دوسرے بڑے بڑے اسٹیٹس کو اس قانون کے اثر سے خارج کیا گیا ہے۔ اور کیا حکومت خود اپنے آپ کو ایک بڑے لینڈ لارڈ کی حیثیت سے مستثنی کرتے ہوئے آرائش بلدے کے مکانات کو اس قانون کے زد سے خارج کر کے وہ کوئی بہت بڑا قدم انہاری ہے لیکن مجھے افسوس میں ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ نامبارک اور نامسعود اقدام ہے۔ اس کی وجہ سے وہ تھوڑی بہت رعایت اور مراعات جو آرائش بلدے کے مکانات میں نہ رہنے والوں کو حاصل ہوئی ہیں ان سے بھی انہیں محروم کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آرائش بلدے کے مکانات میں رہنے والوں کو ان مراعات سے محروم کرنا انصاف اور اصول قانون کے خلاف پڑتا ہے۔ اس لئے میں پر زور طریقہ پر یہ اصرار کروں گا کہ متعلقہ منشی صاحب جو نالنصافی آرائش بلدے کے مکانات میں رہنے والوں کے ساتھ ہورہی ہے اس کو روانہ رکھتے ہوئے آرائش بلدے کے مکانات کو اس میں سے خارج کر دیں۔ ورنہ اس کا قوری نتیجہ یہ بھی ہمارے سامنے آنے والا ہے کہ حکومت نے۔ وہ فیصد اضافہ کراپوں کی جو تجویز کی ہے وہ ایک دوسرے رنگ سے ہمارے سامنے آئیگی۔ دفعہ ۲۶ جو اس قانون میں رکھا گیا ہے اس کے لحاظ سے جتنا اضافہ کراپوں میں ہو سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ۵۰ روپیہ کی میان کے کراپوں میں سارے یا وہ فیصد تک ہو سکتا ہے۔ اس لئے جب ان کو مکانات کے کراپوں میں اضافہ ہو گا تو اس کی مقدار سارے یا وہ فیصد سے زیادہ نہ ہو سکتے گی۔ یہ نہ صرف ایک مسئلہ کا حل ہوتا ہے بلکہ حکومت کے سامنے انصاف اور قانون کا ایک دروازہ بھی کھل جاتا ہے لوگوں کے سامنے بھی یہ بات آئی ہے کہ حکومت نے اپنے لئے کوئی منابعی یا اچارے داری نہیں بنالی ہے۔ اگر ان مکانات کو خارج کرنے کی ضرورت ہی تھی تو کم اپنے کم حکومت کو کوئی واضح بیان دہنا چاہیے تھا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان

1982

6th April, 1954.

'Rent Control' Bill, No. XII  
of 1954

مکانات کی کافی تعداد ہے اور ان میں رہنے والوں کی بھی کافی بڑی تعداد ہے ۔ اب ۸۰ فیصد لوگوں پر اس اضافہ کرایہ کا اثر پڑنے والا ہے ۔ متعلقہ منسٹر صاحب کے فرمائے کے بموجب وہ اس اضافہ کرایہ کو برداشت کر سکتے ہیں نو جو حساب میں نے لکایا ہے اور جو تفصیلات میں نے جمع کشے ہیں ان کے لحاظ سے ان مکانات میں رہنے والوں کو اس کے اثر سے دور نہیں رکھا جاسکتا ۔

اگر مختلف وجوہات کی بنا پر منسٹر صاحب ان کے کراپوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس قانون کے تحت اضافہ کیا جاتا اور ایسی صورت میں اس کا جواز بھی پیدا ہوتا ۔ لیکن ایسا نہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف ان مکانوں کے کراپوں کے حق میں نالائق ہوئی ہے بلکہ اس سے کٹی پیچیدگیاں بھی پیدا ہوئی ۔ اشارتاً میں صرف یہ کہوں گا جیسا کہ ایوان کے زیادہ ممبرس کو معلوم ہے کہ جس طرح منسٹر صاحب نے فرمایا تھا چند آنریبل ممبرس اتنی معقول تنخواہ رکھنے کے باوجود آرائش کے مکانوں میں رہتے ہیں ۔ وہ ان کا تخلیہ کرانا چاہتے ہیں ۔ لیکن چند ایسے بھی واقعات کا پتہ چلا ہے کہ بعض ایسے آنریبل ممبرس جو پہلے آرائش کے مکانوں میں نہیں رہتے تھے وکن مقتنہ بننے کے بعد دوسرے لوگوں کی حق تلفی حاصل کی کے آرائش کے مکانات حاصل کشے ہیں ۔ بہر حال یہ امور قابل غور ہے ۔ ان کی جانب فوری قدم الہایا جانا چاہیے ۔ اگر اس قانون میں ان مکانوں کے لئے بھی گنجائش رکھی جائی تو ایسی بد عنوانیاں ہے آسانی دور ہوسکتیں ۔ لیکن ان مکانوں کو اس قانون یہ مستثنی کیا گیا جس کی وجہ سے معلوم نہیں کہ وہ ان مکانوں کے کراپوں میں کس طرح اضافہ کرنا چاہتے ہیں کس طرح تخلیہ کرانا چاہتے ہیں ۔ ایسے کئی شکوک و شبہات اور خدشات ہیں ۔ اس لئے میں منسٹر صاحب سے ہر زور اپبل کروں گا کہ گو اس پارے میں جہاں تک مجھے معلوم ہے اہوزشین کی جانب سے کوئی ترمیم نہیں آئی ہے لیکن وہ خود اپنی طرف سے ایسی ترمیم لا کر آرائش بلہ کے مکانوں کو بھی اس قانون کے تحت لا دیں ۔ یہ انتہائی ضروری ہے اس سے کٹی پیچیدہ سائل حل ہوسکیں گے ۔ اور یہ ایک بہت بڑی مانگ ہے ۔

ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریرِ ختم کرتا ہوں ۔

شی. سچیت رام مाधवराव वाघमारे (निलंगा) :— अपूर्णाध्यक्ष महोदय, अब तक विस बिल पर जो चर्चा हुई ہے अूमं अकसर मेंबरों ने विस बिल का स्वागत कیا ہے । और अन्होंनے यह کہا کہ पहले विल के निःबत में यह बिल चार कदम आगे ही है । लेकिन सिर्फ थोक बॉल्टरेवल मेंबर ने विस बिल के निःबत यह करवाया कि मैं जिसका स्वागत तो क्या द्वारीद भी नहीं کर सکتا । मुझे अून्से वितनाही अजे करना ہے کि आप चाहे जिसका स्वागत न करें, या ताकिद न करें, यह हक्क तो आपको हासिल ہے, लेकिन अकसर लोग विस बिल की ताकिद کर رہے ہیں । और विस बिल का स्वागत भी कर رہے ہیں । जो सजेशन्स آयے ہے अून्स سے बहुत سارے جच्छे भी हی سکतے ہے लेकिन यह कहना कि भैं जिस भी ताकिद भी नहीं कर सकتا یہ چیز کوئی ढੀک نہیں ہے ।

जो चंद अंतराज अिस बारे में अुस जानिव के अॉनरेबल मेवर्स की नरफ मे आये हैं, अुमके निमवन में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अिसमे से सभी अंतराज दुर्स्त नहीं है। अिस कानून के दफा १२ के बारे में जो अंतराज किया गया और यह कहा गया कि यदि खिलाफवर्जी मालिके मकान करें तो किरायेदार को अदालत में जाने के लिये क्यों कहा जाता है? लेकिन मै यह पूछना चाहता हूँ कि खिलाफवर्जी मालिके मकान करें और खुद ही अदालत में या रेंट कंट्रोलर के पास जाय यह कहानक म नासिव है? मैने अिस दफा को काफी गौर से पढ़ा है, और अॉनरेबल मेंबर फराम परभर्णने भी अिस दफा को काफी गौर से पढ़ा होगा औंसा मै मानता हूँ। वह दफा जो है वह अिस तरीके से है। कोओ मालिके मकान बाजवा या माकूल वजह के बगैर अन आशयों में से किसी को मुनखते या मीकूफ न कर सकेगा, जो किरायेदार को हसिल हो। जब मालिके मकान खिलाफवर्जी करना है तो यह लाजमी बात है कि खिलाफवर्जी करने वाला अदालतों में नहीं जाया करता है। यदि यह कर्ज किया जाय कि अेक शखस किसी दूसरे शखस को थप्पड मारता है और अिसप्रकार कानूनको खिलाफवर्जी करता है, तो थप्पड मारनेवाला अदालत में कैसे जायेगा? खिलाफवर्जी करनेवाला अदालत मे रुजू हो, या थप्पड मारनेवाला अदालत में रुजू हो, यह कैसे हो सकता है? और आप जिस तरह से कहते हैं वैसे शब्द रखे जायें, और यदि खिलाफवर्जी करनेवाला मकान मालिक यदि अदालत में रुजू नहीं होता है, तो अिस कानून का मकसद ही बेकार होगा। औंसा नहीं हो सकता है। जिसके खिलाफवर्जी को जाती है अुसे ही अदालत में रुजू होना चाहिये। अिस लिये सिर्फ मुखालिफत करने के लिये मुखालिफत की जाय यह चीज शोभा नहीं देती। खास करके दफा १२ के बारे में अंतराज किया गया अिसलिये मैने अुसके बारे में जवाब दिया।

अेक अॉनरेबल मेंबर ने फरमाया कि साबिक मे मैने अेल. अेल. बी. के फस्ट अियर का अिम्तेहान दिया था लेकिन दूसरे साल अेल. अेल. बी. के फायनल अियर का अिम्तेहान मकान न होने से न देसका। जब मैं कानून पढ़ता था तो मृजे अुसमें बड़ी दिलचस्पी मालूम हुआ। मैं अुनसे कहना चाहता हूँ कि अिसके सिलसिले में अेक कानून औंवान के सामने आ रहा है और आप अेल. अेल. बी. में फिर से बैठसकते हैं। मैं अुनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर फिर से अेल. अेल. बी. के अिम्तहान में बैठें।

आज जो यह बिल हाथुस के सामने लाया जा रहा है वह अिसके पहले ही लाया जाता तो अच्छा होता। लेकिन फिर भी जब आज यह कानून लाया जा रहा है तो मैं अॉनरेबल मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। और अिस बिल का स्वागत करता हूँ।

टेनन्सी अंकट जो कि अिस हाथुस ने पिछले सेशन में पास किया था अुसके असरात देहातोंमें ज्यादा तर हुआ। और शहर के जो बांशिदे थे वंह अिसके असर से दूर रहे। देहात के लोग कहते हैं कि हमारे लिये तो आपने कानून लाया कि अेक मुकररा लिमिट से ज्यादा जमीन हम अपने पास नहीं रख सकते लेकिन शहर के जो बांशिदे होते हैं जिनके पास अेक अेक के नाम पर दस बारह मकानात होते हैं अुनके लिये तो आपने कोओ कानून नहीं बनाया कि अिससे ज्यादा मकानात वह अपने पास नहीं रख सकते हैं। जिनके पास दस दस बारह बारह मकानात रहते हैं और हवा के लिये पंखे चल रहे हैं और बड़े जैश व आराम में रहते हैं अुनके लिये क्यों कोओ कानून नहीं लाया जाता है? जिस तरह पहले बादा किया गया था अुसके मुताबिक अॉनरेबल मुच्छर अंक दो बिल ने यह बिल लाया है अिस लिये मैं अुनका स्वागत करता हूँ। यह बिल देहात के लोगों को अच्छा लगेगा कि जिनके पास बड़े बड़े मकानात हैं अुनके लिये भी कुछ न कुछ बिल आज हाथुस के सामने लाया जा रहा है।

देव आनंदवल मेंद्रन ने अन्तराज किया और यह न्वायद जाहिर की कि जो छोटे मालिक मकान इनमें से बिल्डिंग, इन्डस्ट्री, अम्ब बवान एवं ही अद्यवित रहती है अनुको अिस विल ने मुसतसना करना चाहिए। यह मनना है कि यह अन्नंदवल मेंद्रन हैदराबाद शहर मेरहनेवाले हैं, और अिनका ऐसा नहीं है, जानी मकान बिल्डिंग जो शिफ्टोने किये पर दिया होगा, अिस लिये वे छोटे छोटे मालिक मकानों के मुतालिक अिसे नहीं करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अिन लोगों की गुजर बसर का वही अंक नाथन है जो है। जब कि अिस अंचान के सामने टेनन्सी कानून लाया गया था तब अिन मेंद्रस ने जो छोटे देनद होते हैं अुके मुतालिक यह कानून लागू न किया जाय औसा क्यों नहीं कहा ? छोटे छोटे आगर्ज के कीलदार होते हैं अनपर अिस टेनन्सी कानूनसे कितनी मुसीबतें आयी होंगी अिसका तो आपकी अंहसाम नहीं हुवा। यह बेचारे तहमिल में जायेगे और ६,६ महिने के बाद अुच्चे जमीन बापस निलेंगे। अिन दिक्कतों का अंहसाम तो आपको अुस बक्त नहीं हुवा, वयोकि आप देहात में नहीं रहते हैं अिस लिये आप अन दिक्कतों को महसूस नहीं कर सकते। यह कहा गया कि अेक बेवा है और अम्के पास अेक मकान है जो वह किराये पर देती है और यही अुसका आमदनी का जरिया है तो अुसे यह कानून लागू न किया जाय। यही हालत जमीन के बुस गरीब किसान की रहती है। अुका यदि बैल मरणया और अुसने अपनी आरजी दूसरे को कौल पर दी तो वह आरजी जल्द बापस नहीं ले सकता है। अुके बारे में तो यह नहीं कहा गया कि औसे गरीब काश्तकार से यह टेनन्सी कानून लागू न किया जाय। अिस लिये आप जब आपके बारे में कोओ कानून लाया जाना है तो कहने हैं कि गरीब मालिके मकान से यह कानून मुतालिक न किया जाय। यह कहां-तक दुस्त है ?

अेक चीज़ मुझे यहां पर अर्ज करती है कि सरकार की तरफ से जो बिल लाये जाते हैं, या जो भी स्कीम बनाये जाते हैं अुसमे ज्यादा तर फायदा शहरवाले लोग ही अठाते हैं। शहरों में सिमेंट की मडके बनती हैं, बेस चलती हैं, प्रसूति गृह निकाले जाते हैं, दवाखाने निकलते हैं, और जो भी सहुलियतें दी जाती हैं वह ज्यादातर शहरों के लिये दी जाती है। देहातों के लिये अिसमें से कुछ नहीं बिल्ना है। मेरा सजेशन यह है कि अब देहातों में ज्यादा सहुलियते देने के बारे में कोशिश की जानी चाहिये। आप देहात के लोगों से टेक्स तो बसूल करते हैं लेकिन अुससे आनेवाला ज्यादा पैसा आप शहरों के लिये और शहरों में रहनेवाले लोगों के अंश व आराम के लिये खर्च किया जाता है, और देहातों की तरफ तब ज्ञह नहीं की जाती।

अब मुझे जिल कानून के मुतालिक यह कहना है कि अिसु कानून का असर होनेवाला है वह निर्क स्टेट के ४० मुवाजियात में होनेवाला है। यह कानून सिर्फ ४० मुकामांत से मुतालिक किया जानेवाला है। परभणी के अॉनरेबल मेंद्रन ने जो सजेशन दिया है कि सब स्टेट से यह कानून मुतालिक किया जाय अिस सजेशन की में तायिद करता हैं। यह कानून अस्मानावाद से मुतालिक किया गया है जिसके आवादी १२ हजार की है। लेकिन लातूर जिसकी आवादी ३५ हजार तक है और वहां पर बाजार भी बड़ा है अुससे यह मुतालिक नहीं किया गया। कल्याणी की आवादी १५ हजार की है, अदर्यार की आवादी १५ हजार की है, वहां पर यह कानून क्यों नहीं लागू किया जायेगा। जहा तालुका हो वहां भी जिसे लागू करने की जरूरत है। जिस लिये में अॉनरेबल मुक्कर साहब से स्वाभिष करंगा कि वे मुदतलिक जगहों पर यह कानून लागू करें जहां पर की म्पुनिसिपालिटीज टाबून कमिटीज, और अदालतों काम करती हैं।

‘अितना कहते हुवे और जिन लोगों ने अमेड़मेटम् दर्शये हैं वे अमे बाप्तम् केंगे अंसी अुमीद करते हुवे मे अपना भाषण समाप्त करता है।

سیئر دنی اسکر - مبن سمجھتا ہوں کہ ڈسکٹن کے لئے کاف وق دیا جا چکا

一

شري بي - ذي - دسمكھے۔ آج سورا نائم ڈسکشن کے لئے دیا چائے تو بہتر ہو گا  
کبھوں کہ اس صرف سے بھئی امنشنس دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔

سری گویاں راؤ اکبولے ۔ جس وقت اسیکر صاحب نے دریافت کیا تھا تو اوس طرف سے ہے خیال طہر کنبا گی ذیا کہ نانچ بھرے لک ڈسکنن کے لئے وقت دیا جانا چاہئے اس کے بعد اسیکر صاحب نے فرمایا یہا کہ بانچ بھرے سے پہلے ڈسکشن ختم کرنا چاہئے ۔ مجھے ذاتی طور پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے ۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ ڈسکشن کا وقت کم کیا جائے لیکن اسیکر صاحب نے جس خیال کا اظہار کیا تھا میں اوس جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں ۔

مسٹر ڈبی اسیکر - اس بل کے بارے میں جنرل ڈسکشن تو ہوچکا ہے - اگر کسی خاص بائیٹ کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں میں تمام آنریبل مبرس سے یہ خواہش کروں گا کہ جن مسائل پر ڈسکشن ہوچکا ہے ان کو ریپٹ ( Repeat ) نہ کیا جائے۔

\* شری جی - سری راملو - مسٹر اسپیکر سر - جن مسائل پر چلے گئے کوئی ہوچکی ہے  
یہیں ان کو نہ دھرا نے کی کوشش کروں گا۔

ہاؤز کو یاد ہوگا کہ جس وقت لیر ہاؤزنگ ( Labour housing ) کے بارے میں بل آیا تھا تو میں نے اوس وقت کہا تھا کہ جس طرح زمینداریاں ختم کی جا رہی ہیں اوسی طرح مکان داروں کے حق ملکیت کو بھی ختم کرنا چاہئے۔ بہت کچھ کہنے کے بعد آخر میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہل جوتیں والے کے درمیان سے مڈل میں ( Middleman ) کو ہٹانے کے لئے جو اقدام کیا جارہا ہے اوس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی اپنی زمینات کو فروخت کر کے پیسے اکھٹا کر رہے ہیں اور سڑی ( City ) میں بیٹھکر مکانات تعمیر کروارہ ہیں۔ گواہ فیوڈل لینڈ لارڈس ( Feudal Land Lords ) اکسپلائیٹریشن کے دونسرے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ اس کا انسداد ضروری ہے۔ ان لوگوں نے اپنا رخ گاؤں سے شہر کی طرف پہنچ دیا ہے اور شہر میں بڑے بڑے بنگلے۔ مکانات۔ اور سینما پناکر کرایہ پر دے رہے ہیں۔ پہلے یہ لوگ گاؤں والوں کا شکاروں۔ زراعت پیشہ طبقہ کو لوٹتے اور ان کا خون چوپنے کی کوشش کرتے تھے اور اب شہر والوں کی جیبوں پر ان کا ہاتھ پڑ رہا ہے۔ اور وہ اب اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہر سے سفید پوش۔ چھوٹے اور متوسط طبقے کے افراد۔ اہلکاروں وغیرہ کا خون چوپیں۔ اس کے انسداد کی حکومت کو کوشش کرنی چاہئے ہی میں نے اوس وقت بھی کہا تھا۔ لیکن حکومت نے اس بھانس سے ٹھال دیا کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج بھی اس پر ایتم ( Problem )

کو سمجھو کر حکومت کی طرف سے یہ بل لایا گیا ہے۔ خود آنریبل منسٹر (مور آف دی بل) منسٹر فار ایجو کیشن (جنہیں منسٹر فار ایجو کیشن اینڈ اکسبلینیشن کہا جائے تو بیجا نہوںک) جہنوں نے اسکی وضاحت کی ہے۔ انکی وضاحت کو منسٹر کے بعد معلوم ہوا کہ ڈیفسن آف جید را باد رولس کی تتبیع میں سنہ ۱۹۵۱ع کا جوقانون تھا اوس کو ہائی کورٹ سے منسوخ کر دیا گیا ہے لہذا اس ویاکیوم (Vacuum) کو پر کرنے کے لئے اس قانون کو لا لایا گیا ہے۔

تمہیداً منسٹر صاحب نے یہ خاکہ کھینچا ہے۔ ہاؤنگ پرایبل (Housing Problem) کو ختم کرنے کے لئے یا جس طرح زمینداریاں ختم کی گئی ہیں اوسی طرح مکانداروں کے حقوق کو مسدود کرنے کے لئے یہ قانون نہیں لایا گیا ہے۔ صرف یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ رنٹ کنٹرول آرڈر سنہ ۳۵۳ اف کو سبستیٹوٹ (Substitute) کرنے کے مدنظر اس کو پیش کیا گیا ہے۔ آنریبل لیڈی مبرن نے جن کی کانسٹیٹیونسی سے میں واقف نہیں ہوں اون تمام باتوں کی صراحت کی ہے کہ مکانات کی تعمیر میں کس طرح سرمایہ لگایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ وہ سرمایہ آٹا کھاں سے ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اون ذرائع کو ہی ختم کیا جائے۔ رہے باس نہ بیجی بانسری۔ نہ یہ جھگڑے رہیں نہ انہیں کرایہ وصول کرنے کی رحمت ہو۔ بلکہ ان کو ان پریشانیوں سے الگ ہی رکھنا چاہئے۔ اگر دس یاں سال سے کوئی ٹینٹ رہتا ہے تو مالک مکان کا (ختنه) قطع تعلق ہی اوس مکان سے کر دینا چاہئے اور اوس کو ٹینٹ کے حوالے کر دینا چاہئے۔ مکان کے اوپر اور نیچے کے علاحدہ علاحدہ حصے ہیں تو ذرا اس میں مشکل ہو گی کیوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اوپر کا حصہ ایک کرایہ دار کو دیا جاتا ہے اور نیچے کا حصہ دوسرے کرایہ دار کو۔ ایسی صورت میں ذرا مشکل ہو گی کیونکہ ایک شخص کے افعال کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ اندیپنڈنٹ ہوم (Independent House) کے (Right of purchase of the house by the tenant) دیا جائے اور یہ ایک پروگریسیو اسٹپ ہوگا۔ سپریٹ ہاؤز ہو تو رائٹ آف پرچز آف دی ہاؤس بائی دی ٹینٹ (Right of purchase of the house by the tenant) دیا جا سکتا ہے۔ دس سال سے زیادہ عرصہ سے کوئی ٹینٹ ہے تو اس کو حق خریدی دیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک ترقی پسندانہ نظریہ ہوگا اس پر عمل کرنا چاہئے۔ اگر ایسا کیا جائے تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ حکومت آگئے کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ دوسری چیزوں کے بارے میں میں اپنی رائے کا اظہار اس وقت کروں گا جب امنٹمنٹس کے سلسلے میں بحث ہو گی۔

اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت بہت سے قوانین لائے ہیں لیکن خود ان پر عمل کرنا نہیں چاہتی۔ حکومت اپنی طرف سے کوئی لیڈ دیتی ہے تو اس سال دیتی ہے اور دوسرے سال جھن لیتی ہے۔ اس طرح کئی امور میں حکومت اپنے آپ کو مستثنی رکھنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ قوانین تو بتتے ہیں لیکن وہ حکومت کے لئے نہیں ہوتے اس کو معلوم نہیں کہ چیف منسٹر صاحب نے سمجھا یا نہیں۔ ممکن ہے کہ وہ سمجھنے سے قاصر رہے ہوں کیوں کہ انہوں نے اس کے جواب میں کہا

کہ یہ آنریبل بیل کا حسن ظن ہے۔ جیسا کہ وہ عام طور پر کہا کرتے ہیں۔ جب حکومت کی کوئی زمین ہوتی ہے تو چاہے کوئی اس بر منت کرے ناگر کشی کرے کچھ بھی کرے قانون اوس سے متعلق نہیں ہوتا اور اس کو علاحدہ کر دیا جاتا ہے۔

شروع را و مادھوارا و وادھما رے:—دھکومت کے ملک میں بھی ڈنٹ کی ملک گامیل ہے یا نہیں؟

تری جی۔ سری راملو۔ آپ نے کیا کہا میں فالو (Follow) ( نہ کرسکا۔

پھر فرمائیے۔ (Not answered)

ہاں تو سی ائی بی کے تعلق سے بھی بھی بالیسی گورنمنٹ اختیار کرتی ہے۔ یہ بیکار سی باتیں ہیں۔ اس نقطہ نظر کو بدلتا ضروری ہے۔ ہر قانون سے حکومت اپنے آپ کو مستثنی کرنا چاہتی ہے چاہے اس سے گورنمنٹ کا نقصان ہوتا ہو یا نہ ہونا ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا اقدام ہے۔ رنٹ کنٹرول آرڈر جو نکالا گیا اس میں پراپرٹیز آف دی نظام (Properties of the Nizam) کو مستثنی کیا گیا ہے۔ اس بارے میں میں یہ کہوں گا کہ رنٹ کنٹرول آرڈر کا آپریشن (Operation) کرنا چاہئے

Nizam was not exempted from the operation of the Rent Control Order.

ہم بارے میں جب اسمبلی میں سوال کیا گیا تو صاف طور پر چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن جب حال نہیں ہم نے سوال کیا تو روپنیو منسٹر صاحب نے کہا کہ اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اور نظام کی پراپرٹی کو مستثنی کیا گیا ہے۔ ان کو مینوسپالیٹیز کے نکس سے بھی اگر مپٹ (Exempt) کیا گیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب اور روپنیو منسٹر صاحب کے جوابات متناقض ہیں اس بارے میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ

"Whether the answer given by the Chief Minister was misleading and gave wrong information or not, I will decide." میں کہوں گا کہ اس طرح نظام کی پراپرٹی کو مستثنی کرنے کرنے ہوئے چند میہی بھرلوگوں کو دولت جمع کرنے کا موقع دینا مناسب نہیں ہے۔ ان طریقوں کو ختم کرنا ضروری ہے اس میں ایوکشن کے لئے دو طریقہ رکھئے گئے ہیں۔ اگر وہ ایسے طریقہ اختیار کریں تو

He will be evicted under the provisions of this Act.

مثلاً مکان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں یا مالک مکان اپنی رہائش کیلئے چاہے تو خالی کیا جائیگا۔ اگر کسی مالک مکان کا دوسرا مکان اوس کی اپنی رہائش کے لئے اس ناؤن میں نہیں ہے جس کی صراحة شیڈیوں (Schedule) میں کیجئی ہے تو وہ خالی کر اسکتا ہے۔ کسی اور جگہ تو اس کا مکان ہے لیکن اس ناؤن میں جسکی صراحة شیڈیوں میں کی گئی ہے کوئی دوسرا مکان نہیں ہے تو وہ خالی کر اسکتا ہے۔ اگر کسی ناؤن میں نہیں ہے تو وہ وہاں بھی بنتا گا۔ لیکن جہاں جہاں ہے ٹینسٹ کو ایوکشن کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ریسیڈنٹیل ہاؤز (Residential House) نہ ہو تو اس

عذر بر وہ اوکٹ کرسکتا ہے - امن طرح سے لینڈ لارڈ کو اونکٹ کرنے کا موقع رہے گیا ہے - بڑے بڑے لوگ - نظام - سی - آئی - بی جو ستم ٹینٹس ہر دھا رہے ہیں اتنے بھی وہ جاری رہیگا - امن لئے جو بل لایا گیا ہے اوس سے ہاؤزس کے ٹینٹس کو مسلسلہ حس نہیں ہوسکتا - اس لئے میں آنریبل سوورسے ریکوست کرتا ہوں کہ اس بن کی سوری طرح سے جانچ کری۔ جائے اور اس جانب سے جو امنٹمنٹس دئے گئے ہیں اون کو قبول کرلیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گا۔ اس کا مطابق یہ نہیں کہ ہم لینڈ لارڈس کو تکلیف دینے کے لئے ہاں بیٹھے ہیں - جیسا کہ ایک آنریبل لیڈی ممبر نے فرمایا اوس کو پرمیٹٹ ریسٹنٹشیل کوارٹر نہ ہتو ہٹایا جاسکا ہے۔ اگر اس کا ذاتی مکان موجود ہو تو ٹینٹ کو پریشان نہیں کیا جائیگا۔ میں ریکوست کرتا ہوں کہ دفعہ (۲) پر آنریبل منسٹر غور کریں گے - اور جتنے بھی امنٹمنٹ قبول کر لئے جاسکتے ہیں قبول فرمایا لئے جائیں -

شری عبدالرحمن (ملک پیٹھ) مسٹر اسپیکر سر - حکم نگرانی کراہیہ امکنہ عدالت العالیہ سے كالعدم اور منسوخ ہونے کے بعد وہ مسودہ قانون ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اگر عدالت العالیہ سے حکم منسوخ ہونے سے بھلے یہ مسودہ ہمارے سامنے آتا تو یقیناً ہم حکومت کو مبارکباد دے سکتے ہیں پھر کافی مالک مکن اور کراہیہ داروں کی ضروریات کے تحت عبوری دور کے لئے لا یا گیا تھا اس لئے اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں تھیں کیونکہ عدالت دیوانی میں ایسے مقدمات کی ساعت ہوسکتی تھیں۔ مگر چونکہ عبوری دور میں مالک مکن اور کراہیداروں کے تعلقات ناخوشگوار ہونے کی وجہ سے مالک مکان حرص میں اور لالج میں آکر زیادہ کراہیہ حاصل کرنے لگے تھے۔ اور فاجائز استفادہ کر کے کراہیہ داروں کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس کو دور کرنے کے لئے عبوری دور کے لئے وہ قانون لایا گیا تھا۔ لیکن مکانوں کی قلت دور کرنے اور مکانوں کے متعلق ضروریات پوری کرنے کے متعلق وہ عبوری دور کا قانون کافی نہیں تھا۔ اس لئے آج بھی ایسے قانون کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ عدالت دیوانی کو اختیار ساعت ہونے کے باوجود وہاں کے پروسیجر کے لعاظ سے تصعیہ میں کافی تاخیر ہوئی ہے۔ اس لئے جلد از جلد اس قانون کو پیش کرنا ضروری تھا۔ ایکن یہ مسودہ پہنچ کیا گیا ہے وہ بعض خراییوں کے ساتھ ہمارے سامنے آیا ہے۔ بہت سکن ہے اس جانب کی زیبات کو قبول کرائیں کے بعد جو حکومت کے سامنے آجائیں گی یہ خرایاں دور ہوسکیں۔ فرستہ رینڈنگ کے موقع پر اون سارے نمائص کی طرف حکومت کو متوجہ کیتے بغیر صرف ایک نہایت اہم چیز کی طرف جس سے ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے مہربس جس سے مطمئن نہ ہوسکے اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ہے دفعہ (۲۶) اس میں جو امتیاز رکھا گیا ہے کراہیہ داروں کے پتعلق سے اوس کا کیا قانونی جواز ہے۔ سو کاری پنجز کے معزز ارکان کی تقاریب سے واضح نہیں ہوسکا۔ میں نے اس تعلق سے امنٹمنٹ بھی پیش کی ہے اوس وقت میں اس کے مضمرات ایوان کے سامنے رکھوں گا۔ اگر فرستہ رینڈنگ کے موقع پر ہی اونیں غلط

غیر فہمی کو آئوجی ستر صاف کر دیں تو ہب ممکن ہے کہ مجھے امنڈمنٹ سس کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے اس قانون سے سی اسرو منٹ بورڈ کو بھی مسٹنی کا گیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ سنی امپرومنٹ بورڈ کہاں ہے۔ کون گون اوس کے اراکین ہیں کیا اوس کے فرائض ہیں۔ دراصل سی امپرومنٹ بورڈ کا وجود ہے بھی یا صرف اوس کا نام ہی ہے۔ جو نکھلے نظ ”بورڈ“ یہ سمجھتا جانا ہے کہ وہ ایک جمہوری ادارہ ہو کہ جس میں بعض نمائندے ہونگے۔ جو سائل حل کرتے ہوں گے۔ عام طور پر بورڈ کے نام سے ہی تصور ہونا ہے۔ جہاں نک مبری معلومات ہیں سی امپرومنٹ بورڈ کا وجود ہی نہیں ہے۔ حیدر آباد اور سکندر آباد میں کافی مکانات ہیں۔ اون میں ہزاروں کرایہ داران سی۔ آئی۔ بی کے بھی ہیں اون کرایہ داروں کو جو بھی ریلیف اس قانون سے مل سکتی تھی اوس سے وہ محروم رہیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ نام ہباد سی امپرومنٹ بورڈ کا کوئی قانون نہیں ہے۔ میں اس کا دستور بھی دیکھتا ہوں لیکن اوس کا آج تک کوئی قانون نہیں بنا۔ آج سے ۳۰ سال پہلے کچھ قواعد بنے تھے ظاہر ہے کہ ۲۰ سال پہلے کا زمانہ کبسا تھا۔ کیا تصورات تھے اور کن تصورات پر انصاف بیتی ہوتا تھا اور کن تصورات کے تحت کام ہوتا تھا تو آج بھی وہی قواعد چل رہے ہیں۔ اور اون پر عمل ہوتا ہے۔ اس بورڈ کے کارندے نظام کے طور پر ہیں جو قانون سے زیادہ وہی قواعد استعمال کرتے ہیں اور کرایہ داروں پر اون کا نفاذ کرتے ہیں معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ حکومت اپنے اقتدار کو سی امپرومنٹ بورڈ کے نام سے ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ میں اون تفصیلات کو اس نوبت پر تو کہنا نہیں چاہتا۔ مگر میں آنریل منسٹر صاحب سے یہوضاحت چاہتا ہوں کہ وہ اوس بورڈ کے ممبرس کے نام بتائیں یا اوس کا کونسا قانون ہے مجھے بتائیں۔ میں امنڈمنٹ کے موقع پر اون تفصیلات کو رکھوں گا۔ ایک خاتون ممبر نے کہا کہ لینڈ ٹو دی ٹلر کی طرح ہاؤز ٹوڈی ٹینٹ ہی بھی ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نوبت پر ہم ایسا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں مگر سی۔ آئی۔ بی کے مکانات۔ سالارجنگ اسٹیٹ کے مکانات نظام کے مکانات جس کا کرایہ انہوں نے مکانوں کی مالیت سے زیادہ حاصل کر لیا ہے۔ اور جن کے پاس کافی دولت ہے جس کو وہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے مکانات کی حد تک ہم نے نعرہ لگایا تھا اور اون مکانوں کا مطالبہ کیا تھا اوس میں بھی ہم نے یہ گنجائش رکھی تھی کہ اگر مکانوں کی لاگت سے کم کرایہ ادا ہوا ہو تو اوسکی تکمیل کرایہ دار کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے کہا تھا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ سرمایہ دار جب تک، مکانوں کی تعمیر کے سلسلہ میں پیسہ نہیں لگائیں گے مکان کی قلت جوں کی توں رہے گی۔ سی۔ آئی۔ بی کے تعلق سے میں نے جو اعتراض کیا ہے منسٹر صاحب اون کا جواب دیدیں تو اچھا ہے۔ میں ترمیمات کے وقت اون تفصیلات میں جاوے گا۔

شری کٹھ رام ریڈی۔ (نلگنٹہ۔ عام)۔ سٹر اسپیکر سر۔ میں دو تین چیزوں ہی عرض کر دیں۔ سکشن (۲) کے تحت رنٹ کنٹرولر کو اکرزاکٹیو پاورس دئے گئے ہیں۔ پہلے رنٹ کنٹرولر کو اکرزاکٹیو پاورس نہیں تھے۔ وہ ذکری دیتا تھا اور سیوں

جورسٹ کشن کے تحت اکزیکوٹ کیا جاتا تھا لیکن اس قانون میں اکزیکٹیو پاورس جیسے رنٹ کنٹرولر کو دئے گئے ہیں اور وہ رنٹ کنٹرولر بھی کون ہوگا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ میں اپائٹ (Government may appoint) اس سے خطرہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض آریل ممبرس نے ظاہر کیا وہ مال کا کوئی تخصیصدار یا کوئی ڈویزن آفیسر ہوگا۔ ہم کو ماننا پڑیا کہ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے جہاں انصاف کا تعلق ہے اور جہاں تک قانون کے صحیح اپلیمیشن کا تعلق ہے سرنشتہ مال سے یہ ناممکن ہے۔ اس لئے میں دفعہ (۲۹) کو آپ کے ملاحظہ میں لانا چاہتا ہوں۔ اگر صحیح طریقہ پر حقوق حاصل کرنا ہے اور انصاف اور دادرسی حاصل کرنا ہے تو عدالت کے تفویض بے کام کیا جائے۔ یہی کہ رنٹ کنٹرول ایکٹ کا دفعہ (۲۸) قابل ملاحظہ ہے۔ جس میں سیول جورسٹ کشن کو اختیارات دئے گئے ہیں۔ اس قانون کے شیڈول پر بھی میں نے غور کیا اوس میں جتنے مقامات ہیں دو چار کو چھوڑ کر باقی سب مقامات پر سیول جورسٹ کشن ہے۔ اس لئے "اینی پرسن" ("Any person") جو لکھا گیا ہے اوس سے احتیال ہے کہ وہ مال کے جورسٹ کشن میں ہو جائیگا۔ اس کی وجہ سے قانون کا صحیح اپلیمیشن نہیں ہوگا۔ اوس میں ہمہ اقسام کی بد عنوانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ نہ مالک مکان کو امن رہیگا اور نہ کرایہ دار کو۔ اس لئے میں آریل مور سے خواہش کروں گا کہ رنٹ کنٹرولر کو بھی سیول جورسٹ کشن دیا جائے اس میں سہولت ہوگی اور وقت پر کام ہوگا۔ اور قانون کا صحیح طریقہ پر اپلیمیشن ہوگا۔ دفعہ (۲۰) میں ثیٹش فکس کرنے کے متعلق ہے۔ اوس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ۱۳۴ کے پہلے کے بارہ مہینوں میں جو رنٹ تھا اوس کا لحاظ کر کے رنٹ میں اضافہ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں کوئی ایسی چیزیں نہیں بتائی گئیں کہ کس وجہ سے پچس فیصد تک رسیڈنسیل یا نان رسیڈنسیل کے متعلق بھی تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ کیا اکمودیشن میں ترمیم کی وجہ سے پچس ہوست اضافہ ہوگا یا کمیٹریکے سے اضافہ ہوگا یہ نہیں بتایا گیا۔ مالک مکان یہ سمجھ کر کہ رنٹ کنٹرولر ترمیم کے بعد پچس فیصد اضافہ کرایہ میں کریں گے وہ لوگ کرایہ داروں کو بریشان کریں گے۔ فیرنٹ کے سلسلہ میں (۷) کا ہراویزو بھی قابل ملاحظہ ہے۔

Provided that where before the determination of the fair rent has been paid in excess thereof, the refund or adjustment shall be limited to the amount paid in excess for a period of six months.

یہ کوتاه نظری کیوں، اختیار کی جا رہی ہے۔ فیرنٹ کے تعین کے بعد جو زائد رقم ہو گی اوس کا تعین چہ مہینوں تک کے لئے ہی کیوں رکھا گیا ہے۔ جہاں کرایہ دار کا تعلق آتا ہے تنگ نظری برق جاتی ہے۔ جہاں مالک مکان کا تعلق آتا ہے تو حکومت اپنا ٹسکیپ پیش استعمال کرتی ہے۔ اس کے متعلق میرا یہ کہنا ہے کہ جتنا اضافہ کر لیا ادا کیا گیا ہے اوسکی لمبیشن تین سال کی رکھنی چاہئے۔ اگر کرایہ دار نے اپنے

اغراض کے لئے یا مالک مکان کی سختی کی وجہ سے ادا کیا ہوتا وہ اوسکو واپس مل سکتا ہے۔ دفعہ (۹) کے متعلق مختلف آنریبل سبرس نے اظہار کیا ہے۔ کرایہ اگر وہ نہیں لیتا ہے تو ڈبازٹ رنٹ کنٹرولر کے ہاس جمع کرے اوس میں سے وضعات ہو جائیں گا۔ (۶) میں ٹیکس کے متعلق کہا گیا ہے اور اس میں ٹینٹ بردہ داری ڈالی گئی ہے کہ اگر ٹیکس بڑھتا ہے تو کرایہ میں بھی اضافہ ہو گا۔ اس میں یہ نہیں رکھا گیا کہ کرایہ میں اضافہ کس طرح ہونا چاہئے۔ آنریبل منسٹر صاحب اس پر بھی غور کریں کہ ٹیکس بڑھنے کی وجہ سے کوئی سہولتیں کرایہ داروں کو مل رہی ہیں کرایہ دار جس مکان میں ہے اوسکی مالیت کو بھی کنسیدریشن میں رکھنا چاہئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں رنٹ میں اضافہ کرنے کا سوال آتا ہے تو کرایہ دینے والی کی حیثیت بھی کنسیدریشن میں لینی چاہئے۔

<sup>۱</sup> اسکے بعد کلار ۱۰ کے ضمن (۲) کے ضمن (۱) میں یہ ہے کہ

that the tenant has not paid or tendered the rent due by him in respect of the house, within fifteen days after the expiry of the time fixed in the agreement of tenancy...

یعنی اس میں ایوکشن سے متعلق کہا گیا ہے میں ٹینسی بل کے متعلق بتلاتا ہوں کہ وہاں بہت استنجی (Stingy) سے کام لیتے ہوئے بقایا کے لئے صرف پندرہ دن کی مدت دیکھی ہے کرایہ دار جنکی معاشی حالت اچھی نہیں رہتی انہیں سہولت بھم پہنچانے کے لئے آنریبل مسور آف دی بل سیریسلی غور کریں۔

<sup>۲</sup> سکشن ۷ کے ہراویزو میں بھی یہ ہے کہ

provided that in any case falling under clause (i) if the Controller is satisfied that the tenant's default to pay or tender rent was not wilful, he may, before making an order as aforesaid, give the tenant a reasonable time, not exceeding 15 days...

یہ ریزیبل ٹائم ٹھیک تھا کیونکہ حالات کے لحاظ سے اور اسکی حیثیت کے لحاظ سے عدالت غور کر سکتی ہے۔ لیکن اس ریزیبل ٹائم کو رکھ کر بھی ناٹ اکسیدنگ فیٹن ڈیز (Not exceeding fifteen days) رکھا گیا ہے جو سختی پر مبنی ہے۔ اسکو نکالنا چاہئے۔

<sup>۳</sup> اسکے بعد پیج ۸ پر ضمن ۷ میں یہ ہے

Where a landlord who has obtained possession of a building in pursuance of an order under sub-section (3) does not himself occupy it within one month of the date of obtaining possession, or having so occupied it, vacates it without reasonable cause within six months of such date, the tenant who has been evicted may apply to the Controller for an order directing

that he shall be restored to possession of the House and the Controller shall make an order accordingly, notwithstanding anything contained in this Act.

اس میں یہ ہے کہ مکان کو اکویٹ کرنے کے بعد مسلسل ۶ سوپنے تک قبضہ رکھا جائے۔ اگر ۶ سوپنے ۱۰ دن کے بعد مالک مکان یہ کہدا ہے تو سابقہ کراہیہ دار کا حق نہیں رہتا۔ اس پریشنا (Period) کو اس طرح پڑھانا چاہئے کہ مالکان اسکے کراہیہ داروں کے ساتھ سختی کرتے ہوئے انہیں ہٹا کر دوسروں کو کراہیہ پر نہ دین۔ اس میں وہ ان ون منٹھ (Within one month) جو رکھا گیا ہے اسکو اضافہ کیا جائے تاکہ زیادہ سہولت کراہیہ داروں کو مل سکے۔

اس میں (۶) کے تحت ایک سوچنا یہ بھی ہے کہ مالک مکان سمجھیف کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لئے ۰ ۰ روپیے فائن کیا جاسکتا ہے۔ ایک مالک مکان سمجھیف کرتا ہے۔ وہ کراہیہ دار کو عدالت میں کھنچوانا ہے جس میں اوسے طرح طرح کی پریشانیاں اٹھنی پڑی ہیں لیکن اس کے لئے سزا صرف یہ مقرر کی گئی ہے کہ جس طرح بلا قندیل سیکل گرفتار ہوتا ہو اسے جرمیانہ کیا جاتا ہے اسی طرح مالک مکان کو بھی ویسا ہی جرمیانہ ہوگا۔ اسکو سخت سے سخت کیا جائے تاکہ مالک مکان اسکے ہمت نہ کریں اور خلاف ورزی کے مرتكب نہ ہوں۔

اسکے بعد کلاز ۱۸ میں یہ ہے۔

"With such modifications as the circumstances may require."

یہ بہت ویگ ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سمری پروسیجر ہے۔ لیکن اسکو ویگ طریقہ سے رکھکر تحسیلدار یا دوم تعقدار کو یہ اختیارات دیتے ہوئے "ایز سرکم اسٹانسنس میں رکواٹر، (As circumstances may require)" کے الفاظ رکھیں تو وہ اپنا ڈسکریشن کیسے استعمال کریں گے مجھے اسکی نسبت اندیشہ ہے۔ اسلئے بیری سوچنا یہ ہے کہ خوبیتے دیوانی کے تحت جو پروسیجر ہے وہ اختیار کیا جائے۔

اس بل میں میں ایک دو خاص الفاظ کلاز ۱۹ میں پاتا ہوں۔

for making enquiries under this Act, the Controller shall follow as early as possible.

وہ کس طرح سے اپنا ڈسکریشن استعمال کریں گے میں آنریل مورو آف دی بل جو خود ایک اچھے وکیل ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس ورڈنگ کا کیا انر لیا جائیگا وہ بتلاتیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات میں دقت ہو رہی ہے تو سمری پروسیجر رکھا جائے۔ اور اسکے لئے جو ضابطہ ہے اسکو اپلائی کیا جائے ورنہ دوسروں کے حقوق کو ہامال کرنے کے لئے ایک موقع تکل آئیگا اور بہت ساری پیچیدگیاں واقع ہونگی۔

اسکے بعد دفعہ ۲۶ نو میں دو چار لفظ کہنا چاہتا ہوں - انڈو یجویل پر اپریٹر کے بارے میں ہم بہت کچھ سوچ کر قانون بنارہے ہیں لیکن عوامی حکومت کے اس دور میں بھی کیا ہم انہیں سہولت دیرے ہیں - کیا حکومت اپنی برپریٹر کیلئے بھی ایسا ہی عمل کر رہی ہے - سی آئی بی کوارٹرس یا میونسپالی کے کوارٹرس کیلئے بھی ایسا ہی عمل کیا گیا ہے جو گورنمنٹ کے بیسے ہے بنے ہیں - رنٹ کنٹرول کے تحت واجی کراہیہ دیا جاتا ہے اور کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں لیکن کیا اس بل سے اس سے بڑھ کر حقوق حاصل ہو رہے ہیں - اس سے کن لوگوں کو فائدہ زیاد، پہنچ رہا ہے - کیا سالار جنگ بلندنگ اور حضور نظام کی بلندنگ کو اس سے مستثنے نہیں کی جا رہا ہے - نہ صرف یہ بلکہ دوسروں کو لوگوں کو بھی جنہیں مستثنے کرنا حکومت مناسب سمجھے مستثنے کرسکتی ہے - لیکن میرے خیال میں یہ مناسب نہیں - البته کچھ ہ سٹلس اور انسٹیشیوشن کو استثنایاً دیا جاتا ہے تو مناسب ہو گا - ورنہ بڑے بڑے سرمایہ داروں اور مالکان اسکے کو استثنایاً دیا جائے تو اس سے خدا رون کے حقوق تلف ہونگے - اسلئے دفعہ ۲۶ میں جو مستثنیات ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنے کیلئے غور کیا جائے اور اسے اور بی کے سوا تمام چیزوں کو ڈیلیٹ کیا جائے ان چند سو جناؤں کے ساتھ میں آنریبل مور آف دی بل سے یہ اپل کرونگا کہ اس بل کا اثر تمام لوگوں پر یکسان ہونا چاہئے حکومت کا یہ رویہ نہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنی برپریٹر کو ایک نظر سے دیکھئے اور عوام کی پر اپریٹر کو دوسروی نظر سے -

شری گوبال راؤ اکبُریٰ - سٹر اسپیکر سر - پہلی خواندگی کے موقع پر اس بل پر کافی تقدیر ہوئی اور عام طور پر اس کو حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے دیکھا گیا۔ یہ کہا گیا کہ گوشۂ قانون کے مقابلہ میں اس بل میں امپریمنٹ ضرور ہوا ہے۔ سوائے ایک آنریبل ممبر کے جنہوں نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا عام طور پر ریلیٹک اپروچہ (Realistic approach) سے آنریبل لیڈرس آف دی اپوزیشن نے بھی اسکا استقبال کیا اور اسکی ضرورت محسوس کی۔ کچھ اعتراضات چیدہ چیدہ طور پر کئی گھنکا جواب تقضیل طور پر استمنٹس کے پیش ہونے پر دیا جائیگا۔ لیکن امنٹمنٹس کو اوایڈ (Avoid) کرنے کیلئے بعض دفعات کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں میں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں اس بل کی طرف دیکھنے کا جو نظریہ ہے اس میں میں تھوڑا سا کنفیوژن (Confusion) پاتا ہوں کیونکہ ایک صاحب ہنئے ٹیننسی ایکٹ کا رفرنس دیکھ لمبی چوڑی تقریر کرتے ہوئے اس سے کچھ مناسب اور مشابہت بتلانے کی کوشش کی ہے۔ بعض آنریبل ممبرس نے دفعہ ۲۶ کا حوالہ دیکھ رہا کہ ایسا ڈسکریمنیشن (Discrimination) کیوں کیا جا رہا ہے - جب اس قانون کو سب مکانات سے متعلق کیا جا رہا ہے تو سی آئی بی اور سالار جنگ بلندنگ اس سے کیوں مستثنے کئی جا رہے ہیں -

[ Mr. Speaker in the Chair ]

بعض آنریبل ممبرس نے اس ڈسکریمنیشن کو اور آگے بڑھا کر یہ بھی کہا کہ بعض دوسروے اسٹیشن جنکے تعلق سے اتنا یہ خیال ہے کہ وہ اسمیں آجئے ہیں اسکے مثال پیش کی اسمیں بھی انہوں نے ڈسکریمنیشن کا حوالہ دیا - اس سلسلہ میں میں ایک بنیادی چیز کہ

وپاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ لینڈ لارڈ اور ٹینٹس کے ریلیشن (Relation) کے جہاں تعنیٰ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا وہ ٹرانسنس آف برائٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے۔ جہاں وار کی وجہ سے یا مائٹریشن (Migration) کی وجہ سے جو ولیجن سے مشیز میں ہو رہا ہے یا خود مکانات کے شارٹیج کی وجہ سے جو کمی سدت سے محسوس کی جا رہی ہے اس سے ایک طرف تو مالک ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اسکو روکنے کیلئے اور دوسری طرف لینڈ لارڈس اور ٹینٹس کے ریلیشن کو ریلیشن کو اچھی حالت میں برقرار رکھ کر رگولیٹ (Regulate) کرنے کیلئے یہ قانون لا یا کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بعض مقامات کیلئے ایک مخصوص قانون ( اسمیٹل لا ) لا یا جاتا ہے تو وہ خود ایک ڈسکریمینیٹری میٹر ہوتا ہے۔ یہ عام قانون تو ہے لیکن اسکو صرف . ۳ مقامات کیلئے لا گو کیا جا رہا ہے۔ البتہ گورنمنٹ نے یہ اختیار اپنے یاں رکھا ہے کہ جہاں ایسے حالات رونما ہو جائیں کہ کسی شہر یا نگر میں اسکی ضرورت ہو تو وہاں بھی اسکو لا گو کیا جاسکتا ہے۔ تو یہ بل جو اسوقت ایوان کے سامنے پیش ہے خود ایک ڈسکریمینیٹری بل ہے۔ اب اسکو ٹرانسفر آف برائٹ ایکٹ جو ایک عام لا (Law) ہے کی طرح اپلانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہ معزز دوست جو اس پر اعتراض کر رہے ہیں وہ مجھ سے متفق ہو جائیں گے اگر میں انہیں یہ بتلوں کے آرٹیکل ۱۲ کے تحت ایسا ڈسکریمینیشن اوسوقت دستوراً جائز ہے جیکہ ایک ریشنل یسنس ( Rational basis ) پر اسکو رکھا جا رہا ہے۔ اب اس ریشنل یسنس کو دیکھنے کیلئے اس گاؤں کے حالات کو دیکھنا ہو گا۔ نہ صرف اس گاؤں کے حالات دیکھنے جائیں گے بلکہ جو مختلف پراویٹس ڈسکریمینیشن کے ہیں انہیں جسٹیفیٹی (Justify) کرنا پڑیا۔ اور وہ جو ریشنل آؤٹ لک ہمکو آرٹیکل ۱۲ کے اغراض کیلئے ضروری ہے لینڈ لارڈ اور ٹینٹس ان دونوں کو سامنے رکھ کر بتلاتا پڑیا کہ یہ ریشنل کلاسیفیکیشن من نظرے نظرے ہے۔ اس سے ایک طرف تو جو ناجائز رنٹ ریا کشنا ہو رہی تھی اسکو روکنے کی کوشش کی گئی ہے تو دوسری طرف ٹینٹس اس ایکٹ سے جو ناجائز فائدہ حاصل کرنے کا امکان تھا اسکو روکا گیا ہے۔ اس طرح ایک ریشنل کلاسیفیکیشن (Rational classification) اور جسٹس (Justice) ( لینڈ لارڈ اور ٹینٹس دونوں کے درمیان کیکنی ہے۔ اس ریشنل یسنس ( Rational basis ) کے سلسلہ میں میں یہ بتلاتا چاہتا ہوں کہ یہ جسٹی فائی ایبل (Justifiable) ( ہے اکویٹیبل (Equitable) ہے اور اس کا ایک سوشیل لیجیسٹیشن (Social legislation) ( حالات کے لحاظ نے ضروری تھا۔ پہلے ایکٹ کے مقابلہ میں یہ ایک ڈسکریمینیٹری بل (Discriminatory Bill) ہے اس لئے ہم ہر یہ ذمہ داری عائد ہوتے ہے کہ ہم اسکو ہر پوائنٹ آف ویو (Point of view) سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ریشنل کلاسیفیکیشن کیا جا رہا ہے اسکا مبہیانشیل گرونڈ (Substantial ground) کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں اور یہ آرٹیکل نوٹیفیکیشن (Article 14) کے لحاظ سے درست ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ کہنا کہ اسکو ہرے ہیدر آباد اسٹیٹ سے کیوں متعلق نہیں کہتے

خوازے سنیز ( Cities ) سے کمپنی متعین نہیں کر دیتے - درست نہ ہوگا - لیکن اس کے دراوشنس کو اندھو چھوٹی ( Individually ) دیکھنے سے کام نہیں چلیگا شوئے بل کے نتھے اسہ سیسٹنس ( Pith and Substance ) کو دیکھنا بڑیگا کہ آیا وہ رہنمائی نہیں - اگر اسکو جوں توائیٹ آف ویو ( Liberal point of view ) سے دیکھیں تو بھی نہیں ہے کہ آرٹیکل فوریں کو سامنے رکھئے آپ یہ تسلیم کر لینے کرنے سے اسکے سوپر نجسٹسینس میں ہے اور لینڈ لارڈ اور ٹینٹنٹ کے درمیان اکو یعنی ریشن قائم کرنے ہے - اسکے علاوہ رہانسٹر آف بوارٹی ایکٹ میں جو فریدم آف کنٹراکٹ کرنے ہے ( رکھا گا ہے اسکے لحاظ سے جو سینیم روٹر کشن Freedom of contract ) عائد کو سکتے ہیں اتنے عائد ہوئے جاہیں ( Minimum restrictions ) ان زیرِ نعل روٹر کشن ( Unreasonable restrictions ) عائد نہیں کر سکتے - اس جو کوئی سب ہمیں اس قانون کو دیکھنا ہے - ہم کوئی قدم ایسا نہیں اٹھا سکتے جس سے آرٹیکل فوریں آفند ( Offend ) ہوتا ہو - جلد بازی میں کوئی اسی برمیم کر دیں تو اسکو چیلنج ( Challange ) کیا جائیگا - اور وہی ہوگا جو گروئٹھے قانون کے سلسلے میں ہوا - چنانچہ اس فسم کے ایکٹ کو کوئی مقامات پر چیلنج کیا گیا ہے - اور جو ابکش تھے اپروج ( Test approach ) میں ٹھیک ثابت ہو گئے ہیں انہیں کو فالو ( Follow ) کیا گیا ہے - اور ہمنے چیلنج کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے - اگر آرٹیکل فوریں کو سامنے رکھیں تو مجھے کامل پیش ہے کہ یہ پورا بل جو ۳۲ دفعات پر مشتمل ہے اسکے کسی دفعہ پر آپ بنیادی اعتراض نہ کر سکتے گے - مجھے تعجب ہوتا ہے جب اس مسئلہ کو لینڈ ( Land ) کے مسئلہ سے ملا یا جاتا ہے - کیونکہ لینڈ کا مسئلہ اپنی نوعیت کا الگ مسئلہ ہے - وہاں زین ایک میں آف براؤکشن ( Means of production ) کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہاں ہزاروں ایکر زین اپنے قبضے میں رکھنے والے کیپیٹلیشن ( Capitalists ) ہیں - لیکن مکانوں کا مسئلہ صرف سیزیسے متعلق ہے - حکومت کی یہ رائے ہے اور عدالتون کی رائے سے بھی اس کی رہنمائی ہوئی ہے کہ ہاؤس شارٹیج ( House shortage ) ہونے کی وجہ سے رلیف ( Relief ) دینے کی ضرورت ہے - کیونکہ جس طرح آرٹیکل سبیر شری اختر حسین نے فرمایا دیبا توں میں تو ملے جلے لوگ ہوتے ہیں - کئی مکان سورجی ہوتے ہیں کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں جو بیواؤں یا نابالغوں کی ملک ہوتے ہیں اور یہی انکا گزر بسر کا ذریعہ ہوتا ہے - بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں دو تین چار یا پانچ ہزار روپیے ماہانہ رنٹ ( Rent ) آتا ہے - جو مکانات کرایہ پر دئے جاتے ہیں وہ دو مقاصد سے دئے جاتے ہیں - ایک تو زینڈشیل پریز ( Residential purposes ) کیلئے اور دوسرا نان زینڈشیل پریز ( Non-residential purposes ) کیلئے - نان زینڈشیل پریز میں گوڈاونس - شاپس - سینما - تھیٹر وغیرہ آتے ہیں - انکی طرف دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا چاہئے - اور قانون میں سہولتیں ایسے لوگوں کو ملنی چاہئیں جو لوور کلاس یا لوور مڈل کلاس یا اہمڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں - لیکن

آنریبل مبرس اس سے متفق نہونگے کہ ان گروپس اور ہائیر گروپ کے لوںوں کے - تھے اپک  
ہی سا سلوک کیا جائے - جو ۰ ۰ مقامات دئے گئے ہیں ان میں سے کسی بھی مدد کی مثال  
لین تو معلوم ہوگا کہ وہاں ایسے لینڈ لارڈز بھی ہیں جو کبیٹشنس بھی کئی جسکتے  
ہیں - لیکن اسکے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں پانچ اپنی صرف آف انجینئرن  
( ) کبیٹنس نہیں کہا جاسکتا - By any stretch of imagination

بعض مکانات میں آف پروڈکشن ( ) کے طور پر  
استعمال کئے جاتے ہیں - جو مکانات ریز بتنشیل پریز کیلئے استعمال ہوتے ہیں جن میں  
لوور گروپ کے لوگ رہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہائیر گروپ ہے ان دونوں میں عمیں  
ریشنل بیسنس ( ) فائل کرنا ہے حس سے لوگ یہ کہے سکیں  
کہ واقعی یہ سوشیل لیجسلیشن ہے - غریب لوگ جو ٹینٹس کی حیثیت سے رہتے ہیں انکی  
مدد ہو اس درشتی سے دیکھیں تو مجھے یقین ہے کہ اس بل پر امنڈمنٹس ہوت کم آئیں گے -  
دفعہ ۲۶ کے تعلق سے اعتراض کیا گیا کہ یہ ڈسکریٹینشنس کیوں رکھا گیا ہے - لیکن میں  
نے جو چوکھٹ بنایا ہے اس میں یہ نہیں آتے - اس سے فالدہ یا نقصان ٹینٹس یا لینڈ لارڈ  
دونوں کیلئے ہیں - میں نے جو وضاحت کی ہے آنریبل مبرس سے میں نہایت ادب کے  
ساتھ استدعا کروں گا کہ اس کی روشنی میں کریٹیسیزم کریں - اور اگر واحدی کریٹیسیزم ہو تو  
مجھے بھی ضرور اس پر غور کرنے کا موقع ملیگا - اور میں اسپر غور کرسکوں گا کہ ان تجویز  
کو اس قانون کے چوکھٹ میں کھانا تک پٹھایا جاسکتا ہے - میں ضرور ایسی تجویز کو  
ویلکم کرنے کیلئے تیار ہوں - لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس طرح لینڈ پر ایلم پر غور کیا جاتا  
ہے اسی طرح اس ہاؤسز کے مسئلے پر غور نہ کیا جانا چاہئے - اور جو نان ریز بتنشیل پریز  
کیلئے ہاؤسز استعمال کئے جاتے ہیں انکی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص ہمدردی  
نہوں چاہئے - وہ انانالا گس پرنسپل ( ) Analogous principle

اس سے متعلق نہیں ہوگا - اس کے علاوہ اس سے ہاؤس شارٹیج کی سمسیا بھی حل نہو گی -  
جو لوگ مکانات کی تعمیر بنس کے طور پر کرتے ہیں اگر وہ زیادہ مکانات تعمیر کرتے  
ہیں تو کوئی ریز بتنیل آدمی اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ اسکی مخالفت نہ کی جانی چاہئے -  
جب تک کہ حکومت خود مکانات زیادہ تعمیر کرنے کے موقوف میں نہ ہو اگر کوئی مکانات  
کی تعمیر پر سرمایہ لگاتا ہے، تو محض اس وجہ سے کہ وہ کبیٹشنس ہے اور اپنا کچھ  
پروگریسوں ( ) Progressiveness پتتے ہوئے اسکو روک دین تو میں اس کو  
سب سے زیادہ ری ایکشنری اسٹپ ( ) Reactionary step اور  
اگر ایسا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی بدقدستی ہو گی - اور  
اس سے ہاؤس شارٹیج کا مسئلہ کبھی حل نہو گا - جو پرائیویٹ مکانات بنانے جاتے ہیں ان  
سے یہی ہاؤس شارٹیج کا مسئلہ ایک حد تک حل ہوتا ہے - دوسری طرف لیئر ہاؤزینگ  
لوور انکم گروپس ہاؤزینگ ( ) Lower income Groups housing

انڈسٹریل ہاؤزینگ ( ) Industrial housing  
کی اسکیوں کے ذریعہ بھی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے - اگر اس طرح صحیح طور پر سوچنے کی

کو ششن کریں تو بہتر ہوگا۔ ورنہ صرف ”ٹینٹ“، کا لفظ آتے ہی ان کے ساتھ ایک ہمدردی بتانے کا جذبہ ظاہر کیا جائے تو مناسب نہیں۔ آج ہزاروں ٹینٹس ایسے ہیں جو فی الواقع بڑے بڑے کیپیلشن ہیں۔ لیکن بہر بھی وہ ٹینٹ رہتے ہیں۔ کیا اس بات کو سنن نظر نہ رکھا جائے۔ کما آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈسکریمینیٹری برائیز کے ذریعہ اب سے نو گول کی مدد کی جائے جو کسی خاص مدد یا ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرے لائق دوست کا یہ تصور ہوسکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ٹینٹ کو زیادہ قائدہ ملے۔ اور لینڈ لارڈ جو ناجائز طور بر استھصال کرتا ہے اس پر بھی باہندیاں عائد ہوں۔ اس نقطہ نظر سے یہ بل لایا گیا ہے۔ اس وضاحت کے بعد میں تفصیلی جواب کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ صرف دونین پوائیش کا ذکر کروں گا۔ ایک چیز کنٹرولر کے تعلق سے بہ کہی گئی کہ پہلے ایکٹ میں کنٹرولر روینیو آفیسر تھا۔ اپیلیٹ اتهاڑی سوانیے سکندر آباد اور حیدر آباد ڈسٹرکٹ کے باقی مقامات پر لکھر ہی تھے۔ رویز کے لئے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آرٹیکل ۲۲۶ کے تحت اکسٹرا آرڈنری پاور (Extra-Jurisdiction) کے ذریعہ رٹ (Writ) کا جو رسٹ کشن (ordinary powers) ہائیکورٹ کو تھا جسکا دائیہ محدود ترین تھا۔

ان خراییوں کو دور کرنے کے لئے یہ چیز روینیو اتهاڑی کے جو رسٹ کشن میں دیکھی جو عام طور پر لیگل اپیلیکیشن (Legal implications) سے واقف نہیں ہوتے اور لیگل پروسیجر (Legal Procedures) کو ادا پڑھتے (Inherent difficulty)۔ یہ ان ہیرنٹ ڈیفیکٹی (Adopt) کی نہیں کرتے۔ اکی یہ نیت نہیں ہوتی کہ کسی کو بلا وجہ ستائیں لیکن وہ کرنٹ واقع ہوتی ہے۔ اکی یہ نیت نہیں ہوتی کہ کسی کو بلا وجہ ستائیں لیکن وہ کرنٹ کیس لا (Current case law) یا اپٹو ڈیٹ لیگل آر گیومنٹ (Up-to-date legal argument) سے وہ واقف نہیں ہوتے اسلئے ظاہر ہے کہ اپیلیٹ اتهاڑی (Appellate authority) نے انکو نہیں مقرر کیا گیا بلکہ ہائیکورٹ جو فائیل اتهاڑی (Final authority) ہے اوسک ساعت کے دائیہ میں ٹسٹ رائیٹ (Test right) کی اپلیکیشن (Application) کے ڈسٹ جو ڈیشل آر کواسی جو ڈیشل (Judicial or Quasi Judicial) برائیزنس مہیا ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو دور کرنے کے لئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایو کشن اینڈ فکریشن آف فیر رنٹ (Eviction and fixation of fair rent) کا تعلق ہے جتنے ایسے قوانین کا تعلق ہے جتنے ایسے قوانین ہیں۔ جتنے جو ڈیشل آر کواسی جو ڈیشل ایکٹس (Judicial or Quasi Judicial acts) ہیں وہ متمدن مالک کے قوانین کا نچوڑ ہیں۔ تمام متمدن ور ترقی پاٹھ مالک ایسے قوانین نافذ کرتے ہیں۔ امریکہ اور انگلینڈ میں ایسے

**پیارامونٹ پاورس (Powers)** ۔ نوٹ ترست پرسن (Provisions) میں ہائیکورٹ کو اختیار دیا جاسکتا ہے نیکن ہمارا یہ تجربہ رہ کرہے تو سایہ پر کافی کشاکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس سب اموری کلکٹر کی بجائے ڈسٹرکٹ چیج ہو ۔ بجائے اسکے کہ کسی دوسرا عدالت میں ہے جائے اور دوسری عدالت سے پھر واپس ہو ہم نے مناسب ختم آئنا کہ نہیں اسی حق نے فرست اپیلیٹ اتھاریٹی مقرر کیا جائے ۔ اس بارے میں آپ مجھ سے سبق ہوتانے لئے ہے نے ایک اپروڈ اسٹپ (Improved step) اور نیچے پیرس (Comparatively) اکر آپ دنیا کے دیگر متسنن میانک سے مشابہ کریں تو محسوس کریں گے کہ واقعی یہ ایک اپروڈ اسٹپ ہے ۔

یہ بھی کہا گیا کہ کنٹرولر امنسٹریشنو آرڈرس (Administrative orders) دے سکتا ہے لیکن جہاں جوڈیشل آرکواسی جوڈیشل پاورس کے استعمال کرنے کا سوانح ہے اسکو اختیار نہیں دینا چاہئے ۔ لیکن آپ مجھ سے یہ معلوم کر کے منفی ہوں گے کہ اگزیکیشنو مائنڈ (Executive side) اور امنسٹریشنو سائٹ (Administrative side) میں بھی ایسی چیزوں رکھنی گئی ہیں کہ جوڈیشل ہوائیں آف ویو (Judicial point of view) اور کواسی جوڈیشل پاور کا جانا ضروری ہے اسلئے چند ملے جیلے جو فوائیں ہیں ان کی حد تک ایسے لوگوں کو اختیارات کا دینا نامناسب نہیں ہے ۔ اسلئے حالات کے لحاظ سے کنٹرولر کے اختیارات مسکن ہے کہ ہم بعض ڈسٹرکٹس میں منصف کے تفویض کریں بعض جگہ سب چیز کے تفویض کریں اور اگر کہیں ایل ۔ ایل ۔ بی تھیصلدار ہو تو انکو کنٹرولر کے اختیارات تفویض کریں ۔ بہر حال حالات مقامی کے اعتبار سے یہ پاورس (Powers) دنے جائیں گے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مستحسن اقدام ہے کہ ایوان کو اسکے قبول کرنے میں کوئی عذر نہیں ہوا ۔ گذشتہ دس ماں سے ہم جو مشکلات محسوس کر رہے تھے اونکو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسکے باوجود تعجب ہے کہ اسپر اعتراض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔ جو حقیقت سے بعید ہے ۔ میں کہونا کہ اگر آنریبل میرس اپنے کریسمیزم (Criticism) ہو ریکنسایڈر (Reconsiderer) کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو مان لینی گے ۔

**اسکے ساتھ فکریشن آف فیرنٹ (Fixation of fair rent)** کے بارے میں بھی اعتراضات کئے گئے ہیں ۔ دفعہ ۱ کے تعلق سے بھی آنریبل میسر نے مایوسی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ ٹینٹ کے فائندہ کے لئے ہے یا لبڈلارڈ کے فائندہ کے لئے ہے ۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس دفعہ ۱ کا دوسرے پروپرٹی میں جو متأہل دفعہ ہے اوس سے مقابلہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اختلاف کی ضرورت معزز ارکان محسوس نہ کریں گے اور نہ کوئی امنشنسٹ اس سلسلہ میں دینا پسند کریں گے ۔ میں اس سلسلہ میں کچھ عرض کروں گا اور دو ایک واقعات کی

طرف سرچہ سندوں کراون گا۔ مہ رنٹ کنٹرول کا سسٹم جو نکلا ہے لور انکم گروپ نہیں کی طرف سے نکلا ہے اور سروع میں اسکاٹ لینڈ سے یہ تحریک سنہ ۱۹۲۰ع میں جیلی۔ اور انگلینڈ میں جو مارکریئس اسکوئنہ کی حوالی میں سفارش کروں گا کہ آنریبل ممبرس اوسکی روپورٹ ملاحظہ دریں اوس میں انہوں نے اس تحریک کا پس منظر بتا ہے اور میں اس کی بھی سفارش کروں گا کہ اس کمیٹی کی روپورٹ یہ جو ڈیش (Debates) ہرئے ہیں اسکو بھی آنریبل ممبرس ملاحظہ کریں ناکہ یہ معلوم ہو گا۔ دراصل رنٹ رسترنیشن ایکس (Rent restriction acts) کی غرض و ضعی کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے ایکٹ ۱۹۳۹ع کو پھرے ہمارے بھائی - مدرس اور کمکتھے نے اذاپٹ (Adopt) کیا۔ یہ اون ہی ایکٹ کا مجموعہ ہے۔ بعض دفات کی حد تک بھار کے ایکٹ کی اباع کی گئی ہے اور بعض دفات بھائی ایکٹ سے لئے گئے ہیں اور انہیں ریشنل بیس (Rational basis) کی تہیواری (Theory) کی تہیواری (Approved) کردا اپٹ کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ ایک ایسا اپروڈبل (Approved) ہاوز کے سامنے لا یا گیا ہے جس کی واجبیت کو کٹی جگہ Bill تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اس لئے میں کہوں گا کہ جو کریسیزم کیا گیا ہے وہ ریزنبل (Reasonable) نہیں ہے اور اس چوکٹ میں بیٹھا ہے اس میں اسکا اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں اس چوکٹ میں بیٹھے سکیں گی اونکو میں قبول کرنے کے لئے آمادہ ہوں گا۔ اون ریزنبل امنٹمنٹ کو میں قبول کرنے کے لئے تیار ہوں گا جو، اس چوکٹ میں بیٹھتے ہیں۔ آخر میں میں ہاوز سے التجا کروں گا کہ وہ فرست رینٹ کو منظور کرے۔

*Mr. Speaker:* The question is :

"That L. A. Bill No. XII of 1954, the Hyderabad Houses (Rent, Eviction and Lease) Control Bill, 1954, be read a first time."

The motion was adopted.

### Business of the House

مسٹر اسپیکر۔ کل ہاوز کے اوقات کے بارے میں میرے پاس چند درخواستیں آئی ہیں کہ کل کا اجلاس صبح ساری ہے آئٹھے بھرے سے بارہ یا سارٹھی بارہ بھرے تک جیسی کہ ضرورت ہو رکھا جائے۔ میں نے اس سلسلہ میں لیئر آف دی پارٹیز سے بھی مشورہ کیا جنہوں نے اس سے اتفاق کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل ممبرس بھی اس سے متفق ہوں گے۔

شری کے۔ وینکٹ رام راؤ۔ کیا پھر دو پھر میں اجلاس نہیں رہیگا۔

مسٹر اسپیکر۔ ظاہر ہے کہ صبح میں اجلاس ہونے کے بعد پھر دو پھر میں نہیں ہو گا۔

The House then adjourned till Half Past Eight of the Clock on Monday, the 7th April, 1954.

